

RNI No : MPHIN/2022/82783

कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 2 मासिक पत्रिका

25 फरवरी 2024

हमारा देश



हमारा अभिमान

हर-हर महादेव



**लोकसभा चुनाव: भाजपा ने
बनायी जोरदार रणनीति...**

हमारा देश 
हमारा अभिमान 

हर-हर महादेव

वसंतपंचमी

की हार्दिक शुभकामनाएं



वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेश्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौवे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकाेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना वाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुवेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडों कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित

प्रमुख परामर्शदाता

कानूनी सलाहकार

- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

विशेष संवाददाता

• रवि परिहार • रविकांत शर्मा

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)

सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डि रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुवे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री वृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डि रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादीन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान

सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक

और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर

• सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4, रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी। (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	02
शुभाशीष	03
कवर स्टोरी	04-05
देश	06-07
देश	08
उत्तरप्रदेश	09
देश	10-11
देश	12-13
देश	14-15
देश	16-17
देश	18-19
मध्यप्रदेश	20
विदेश	21
देश	22-23
आंदोलन	24-25
देश	26
देश-प्रदेश	27
देश	28
इन्दौर	29
देश	30
देश-प्रदेश	31
देश	32
देश-प्रदेश	33
धर्म	40-41
धर्म	42-43
स्वास्थ्य	46
खेल	47
ग्लैमर	48



48

जियोर्जिया ने की थी ब्रेकअप पर बात, अरबाज खान को नहीं आई रास...



संपादकीय

अदृश्य दुश्मन पर नजर रखने के लिए हुई हैं कुछ सराहनीय पहल...

इंटरनेट की ताकत ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। यही वजह है कि आज साइबर अपराध दुनिया भर के देशों के लिए चुनौती बन चुके हैं। भारत में चक्षु और डीआईपी जैसी पहलें सराहनीय हैं, लेकिन साइबर अपराधी जिस तरह नित-नए तरीके लेकर आ रहे हैं, लोगों को भी जागरूक होना होगा। भारत बड़े स्तर पर साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी के हमलों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो साइबर अपराध के मामले बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। दरअसल, कोविड-19 का दौर साइबर अपराध के लिए स्वर्ण युग के रूप में आया। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखकर यही लगता है कि यह आगामी कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाला है। आज हम नित-नए प्रकार के साइबर अपराध के मामले देख रहे हैं। दुनिया भर के देशों के लिए साइबर अपराध बड़ी चुनौती बन चुके हैं। सच तो यह है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। इंटरनेट ने साइबर अपराधियों को उनके अपराध का पूरा ताना-बाना बुनने में मदद की है। ऐसे में, साइबर अपराधियों की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति राष्ट्रीय सरकारों के लिए मुसीबत बन गई है। जबकि, सरकारें साइबर अपराध को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय कानून अपना रही हैं। दरअसल, साइबर अपराधी जल्द पैसा कमाने के सारे हथकंडे जानते हैं। अपराधियों को पता होता है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को विश्वास में लेकर कैसे आसानी से उन्हें अपना शिकार बनाया जा सकता है और पैसा कमाया जा सकता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी आज सबसे बड़े अपराधों में एक हो गई है। आए-दिन हमारे आसपास का कोई न कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनता दिखता है। अनुमान है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाला हर तीसरा व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी से पीड़ित है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में आज ज्यादा से ज्यादा लोग बिना किसी प्रशिक्षण के इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। और, जब व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ता है, तो तमाम सूचनाओं और चुनौतियों के गहरे सागर में गोते लगाता है।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

== शुभाशीष ==

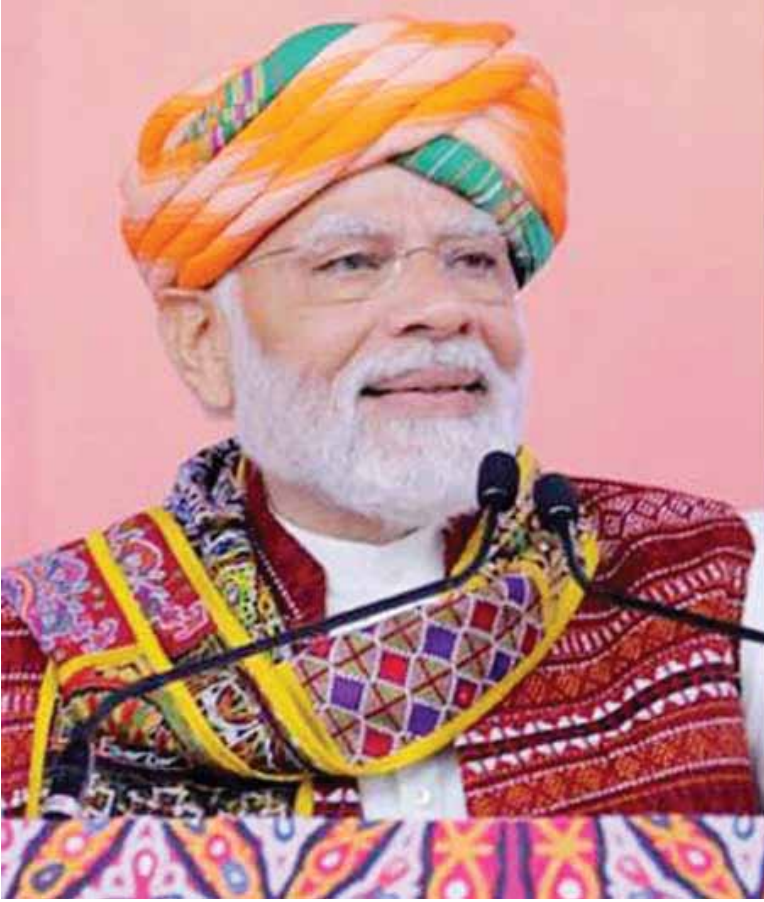


कानूनों का सरलीकरण करके ही भारत को सशक्त बनाया जा सकता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी, आधुनिक, तकनीकी बनाने के लिये उठाये कदमों की चर्चा की। उन्होंने अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाओं के नये कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयन्ती एक अवसर है भारतीय न्याय प्रणाली की कमियों पर मंथन करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सस्ता हो। इस दृष्टि से यह अकल्पित उपलब्धियों से भरा-पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी, और नया परिवेश देने वाला साबित हो रहा है। क्योंकि आजादी के अमृतकाल में पहुंचने तक भारत की न्याय प्रणाली अनेक कंटिली झाड़ियों में उलझी रही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था का छिट्टान्वेषण करें तो हम पाते हैं कि न्यायाधीशों की कमी, न्याय व्यवस्था की खामियाँ और लचर बुनियादी ढाँचा जैसे कई कारणों से न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर न्यायाधीशों व न्यायिक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। न्याय में देरी अन्याय कहलाती है लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था को यह विडंबना तेज़ी से घेरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 75वें वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी, आधुनिक, तकनीकी बनाने के लिये उठाये कदमों की चर्चा की। उन्होंने अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाओं के नये कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया औपनिवेशिक दौर के पुराने पड़ चुके कानूनों की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून लाना बड़ा कदम है। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और इनसे जुड़े कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार की जरूरत भी महसूस की जा रही है, लेकिन फिर भी इस कदम की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

लोकसभा चुनाव : भाजपा ने बनायी जोरदार रणनीति...



उत्तर प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड भी भगवा रंग में रंगता जा रहा है। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसलों से यह बात बार-बार साबित हो रही है। धामी सरकार द्वारा मदरसों की मनमानी पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं जगह-जगह बनाई गई मजारों को हटाया जा रहा है...

भा रतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों से इतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में अलग तरह से राजनैतिक पिच तैयार करने में लगी है। बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के लिए यूपी को भगवा कर दिया गया है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की गुंज देश-विदेश सहित सियासी मोर्चों पर भी सुनाई दी तो वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी सरकार की इच्छाशक्ति के चलते जल्द सुलझता नजर आ रहा है। यह सब घटनाक्रम बीजेपी को मौजूदा राजनीति और चुनावी टाइमिंग के हिसाब से

काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भी चुनावों के समय कौन-सा मुद्दा उठाना है और कौन-सा छोड़ना है, इसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महारथ हासिल है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा के बजट सत्र के दौरान भी प्रभु श्रीराम का नाम खूब गुंजा। सत्ता पक्ष ने विधान सभा में श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिये पीएम मोदी और सीएम योगी को बधाई संदेश देकर अयोध्या मुद्दे पर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ ही कर दिये। समाजवादी पार्टी को प्रभु श्रीराम के मंदिर पर सियासत करना लोकतंत्र के मंदिर में उस समय भारी पड़ गया, जब सपा के विधायकों ने विधान सभा के भीतर हाथ उठाकर मोदी-योगी के लिए

बधाई संदेश का समर्थन कर दिया। मात्र 14 विधायकों ने ही इसका विरोध किया। बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर भी बधाई संदेश का समर्थन करते दिखे। कुल मिलाकर बीजेपी और योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले यूपी को पूरी तरह से भगवामय कर देना चाहती है ताकि हिन्दू वोटर्स को एकजुट किया जा सके। यदि ऐसा हो जाता है तो समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस और बसपा के लिये भी आम चुनाव चुनौती साबित हो सकते हैं। भाजपा अबकी से सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है।

2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में एनडीए के घटक बीजेपी और अपना

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और भाजपा के गढ़ गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक व महाराष्ट्र की बात है तो इन सभी राज्यों में राम मंदिर का असर बीजेपी के पक्ष में



दल (एस) एक साथ मिलकर लड़े थे और एनडीए का 51.19 प्रतिशत वोट शेयर रहा था। जिसमें बीजेपी के खाते में 49.98 प्रतिशत और अपना दल (एस) को 1.21 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। वहीं महगठबंधन (बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल) को 39.23 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। जिसमें बसपा को 19.43 प्रतिशत, सपा को 18.11 प्रतिशत और रालोद को 1.69 प्रतिशत वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 6.36 वोट शेयर मिला था। बात सीटों की कि जाये तो बीजेपी को 62, अपना दल (एस) को दो, बीएसपी को 10, सपा को पांच और कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी।

साल 2019 में हुए चुनाव के बाद यूपी की तीन सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें रामपुर, आजमगढ़ और मैनपुरी लोकसभा सीट शामिल रहीं। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। आजम का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा

सीट पर भी उपचुनाव हुआ। इस सीट पर सपा ने धर्मेन्द्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, वहीं बीजेपी ने इस सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेन्द्र यादव को 8 हजार से अधिक वोटों से हराया था। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में सपा की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में थीं और इस सीट पर बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। अबकी से सपा और बसपा अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा का कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड भी भगवा रंग में रंगता जा रहा है। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसलों से यह बात बार-बार साबित हो रही है। धामी सरकार द्वारा मदरसों की मनमानी पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं जगह-जगह बनाई गई मजारों को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य भी बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में सभी धर्मों के लड़के-लड़कियों की शादी की उम्र तय कर दी गई है। इसी तरह तलाक के मामले भी एक ही तरह से निपटाये जायेंगे। वहीं हलाला, बहुविवाह पर रो लगा दी गई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में यूसीसी कानून के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था। वैसे इसका विरोध भी शुरू हो गया है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि क्या इसके (यूसीसी) आने पर जितने भी कानून हैं उनमें एकरूपता आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल एकरूपता नहीं होगी। जब आपने कुछ समुदायों को इससे छूट दे दी है तो एकरूपता कैसे हो सकती है? हमारी कानूनी समिति मसौदे का अध्ययन करेगी और उसके अनुसार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री द्वारा 6 फरवरी को विधेयक पेश किये जाने के दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने “भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्रीराम” के नारे भी लगाये। गौरतलब हो कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 04 फरवरी को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा पर संदेह है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनने में कोई अड़चन नजर नहीं आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की पांचों सीटों जीती थीं। यहां इस बार भी बीजेपी के सामने कोई खास अड़चन नहीं दिखाई दे रही है।

बात बिहार की कि जाये तो यहां भी बदले सियासी माहौल में बीजेपी बढ़त में नजर आ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से यूपी के साथ बिहार पहले से ही राममय था, अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें पिछड़ों का जनक कहा जाता है, को उनकी जन्म शताब्दी पर भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने हिंदी पट्टी के पिछड़ों और अति पिछड़ों को भी साथ लिया है। कहते हैं, संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। दोनों ही राज्यों में पिछड़े और अति पिछड़े चुनावी गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दरअसल, बिहार भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और यहां नीतीश कुमार कुछ-कुछ सालों में

पाला बदलने का खेल खेलते रहते हैं। आज वह फिर से बीजेपी के साथ आ गये हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं लौटा है इसीलिए नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को साथ रहते हुए भी अप्रासंगिक कर दिया जाए। वर्ष 2014 से इसके प्रयास भी वो लगातार करते आ रहे हैं। बिहार से लोकसभा की 40 सीटें हैं। वर्ष 2014 में जनता दल (यू), राजद और भाजपा, तीनों अलग-अलग चुनावी मैदान में उतरे थे। भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उषेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसे छोटे दल थे। चुनाव में भाजपा ने सहयोगियों के साथ 40 में से 31 सीटों पर विजय हासिल की थी। जनता दल (यू) को दो और राजद को चार सीटें ही मिली थीं। इसके बाद नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए थे। वर्ष 2019 में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए बिहार में चुनाव लड़ा और लोकसभा की 16 सीटों पर विजय हासिल की। दोनों दलों के गठबंधन में राजद का सुपड़ा-साफ हो गया था और वो लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी। हालांकि, इसके बाद नीतीश कुमार एक बार पलटी मार कर राजद के साथ चले गये थे, परंतु अब फिर बीजेपी के साथ आ गये हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं।

जहां तक हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और भाजपा के गढ़ गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक व महाराष्ट्र की बात है तो इन सभी राज्यों में राम मंदिर का असर बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। यह वोटों में तब्दील भी होगा, यह समय बतायेगा। इन राज्यों में लोकसभा की 222 सीटें हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के असम समेत अन्य राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत दिख रही है। वो यहां पुनः वर्ष 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है। नरेंद्र मोदी जब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, उससे पहले वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 18.80 प्रतिशत था और पार्टी की 116 सीटें थीं, लेकिन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व ने भाजपा का वोट शेयर 31 प्रतिशत कर दिया और 282 सीटें पार्टी को मिलीं। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने 336 सीटों पर विजय हासिल की। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वोट शेयर को और बढ़ा दिया। यह बढ़कर 37.7 प्रतिशत हो गया और पार्टी ने अपने बलबूते पर 303 सीटों पर विजय हासिल की, यानी नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जनता को क्या पसंद है और कैसे चुनाव-दर-चुनाव जीत हासिल करनी है। लोकसभा चुनाव में अब चंद दिन ही बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जबकि विपक्षी दल गठबंधन बनाकर सीटों की शेरारंग में ही उलझे हुए हैं।



जुलाई में मेट्रो में सफर कर सकेंगे इंदौरवासी



इंदौर में सात माह बाद शहरवासी मेट्रो में बैठ सफर का आनंद ले सकेंगे। जुलाई में गांधी नगर से टीसीएस तक बने सुपर कारिडोर स्टेशन नंबर 3 तक 5.9 किलोमीटर के प्रायरीटी कारिडोर पर मेट्रो का कमर्शियल रन होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रालय में सोमवार को भोपाल-इंदौर परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रायरीटी कारिडोर को जुलाई तक शुरू करने की बात कही। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में 30 सितंबर को इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन हुआ था। हालांकि कुछ माह में मेट्रो निर्माण की रफ्तार धीमी होने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। अब मेट्रो के अधिकारी व नगरीय विकास आवास मंत्री के निर्देश पर मेट्रो प्रोजेक्ट फिर से रफ्तार पकड़ेगा।

रिपोर्ट के बाद मिलेगी हरी झंडी

इंदौर में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करने के पहले प्रायरीटी कारिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से में बने स्ट्रक्चर का वैधानिक निरीक्षण रेल मंत्रालय की रिसर्च एवं डिजाइन स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) करेगी। उसके बाद कमिश्नर आफ मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही इंदौर की मेट्रो में यात्रियों का सफर शुरू होगा।

कारिडोर पर यात्री कम मिलेंगे

शहर में सबसे पहले गांधी नगर से टीसीएस चौराहे तक तक मेट्रो का संचालन शुरू होना है। हालांकि इस रूट पर मेट्रो के सफर के लिए यात्री कम मिलेंगे। ऐसे में यात्रियों की संख्या के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि कितने सेट की मेट्रो का संचालन शुरू किया जाए। यह संभावना जताई जा रही है कि निर्धारित समय के अंतराल पर मेट्रो कोच को चलाया जाए।

पटवारी भर्ती में गड़बड़ी से नाराज सैकड़ों युवाओं ने घेरा कलेक्टर कार्यालय



पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और सरकार इसे दबाना चाह रही है। स्थानीय कलेक्टर कार्यालय को घेर कर दो घंटे तक बैठे रहे सैकड़ों युवाओं ने यह आरोप लगाया है। सरकार द्वारा भर्ती परीक्षा से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रोकने और एसआइटी गठित कर नए सिरे से जांच की मांग की है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने भीड़ के बीच कुछ प्रवेश पत्रों की प्रतियों को भी लहराया। कुछ उम्मीदवारों के नाम लेते हुए उन्होंने दावा किया कि साफ जाहिर हो रहा है कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की गई है।

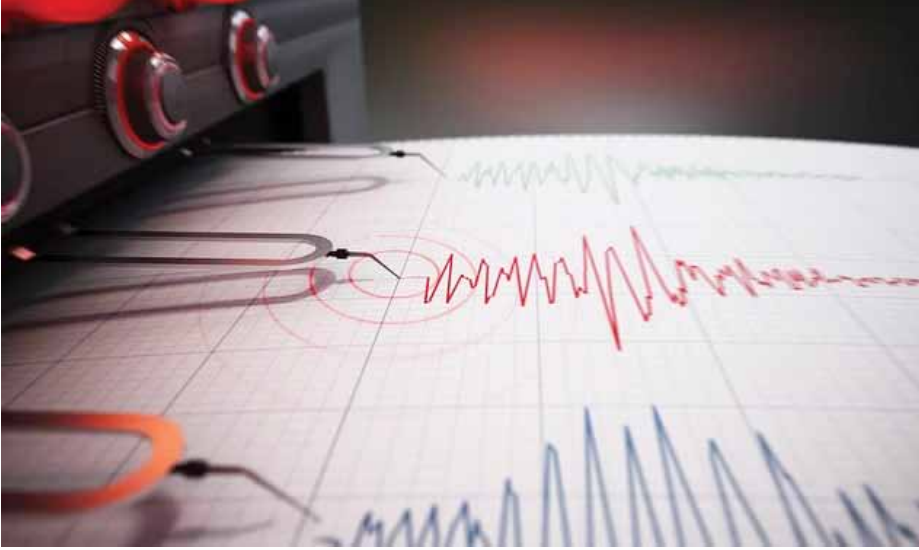
कम से कम साढ़े तीन सौ युवा पटवारी भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन करने स्थानीय कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (एनईवाईयू) की अगुवाई में पहुंचे युवाओं को कलेक्टर कार्यालय से पहले ही सड़क पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक लिया। करीब दो घंटे तक सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने मांग की कि बीती सरकार के कार्यकाल में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां हुई थीं।

इस पर शोर मचा और कई सबूत सामने आए तो

तत्कालिन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने एक पूर्व जज को जांच सौंपी थी। अब सरकार 25 फरवरी से इस चयन परीक्षा से चुने उम्मीदवारों को नियुक्ति दे रही है। बिना जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए नियुक्तियों की हड़बड़ी जाहिर कर रही है कि सरकार धांधली को दबाना चाहती है। युवाओं ने मांग रखी कि एसआइटी बनाकर भर्ती प्रक्रिया की पूरी जांच हो। चीफ जस्टिस मप्र के साथ इसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी रखे जाए, क्योंकि पूरी परीक्षा आनलाइन हुई थी।

प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पटवारी भर्ती से जुड़ी मांगों के साथ अन्य मांगे भी रखी गईं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने कहा कि यहां कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पटवारी भर्ती परीक्षा में एक-दो नंबरों से बाहर कर दिया गया। ये इसलिए हुए क्योंकि भ्रष्टाचार कर अयोग्यों को चयनित किया गया। परीक्षा के बाद ही सामने आ गया था कि कई मेरिट होल्डरों को सामान्य ज्ञान तक नहीं है और वे पैसे देकर चयन होने की बात कैमरे पर स्वीकार कर चुके हैं। ज्ञापन के बाद सरकार को दो दिन का समय दिया है। इसके बाद मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेशभर के छात्र भोपाल पहुंचेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।

भूविज्ञान: आखिर क्यों देश में आ रहे हैं इतने भूकंप



भू- वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप के यूरेशियन प्लेट से टकराने के फलस्वरूप धरती हिलती-डुलती है और भूकंप आते हैं। इसके अलावा धरती के भीतर की ऊर्जा के दबाव से भी भूकंपन होता है। लेकिन इसके प्रभाव-क्षेत्र में इंसानी बसाहट होने से परिणाम दुखद होते हैं। ऐसे में, इस संबंध में किए जाने वाले शोधों के लिहाज से यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि भूकंपन की आवृत्ति कितनी है? उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के 365 दिनों में से 34 दिन देश में कहीं-न-कहीं भूकंप की घटनाएं होती रही हैं। यहां तक कि पिछले वर्ष का पहला व अंतिम दिन भी भूकंप से प्रभावित रहा है।

भूभ्रम विशेषज्ञों ने भारत के करीब 59 फीसदी भू-भाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। पिछले वर्ष एक जनवरी को दिल्ली से हरियाणा तक 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके रात 1.30 बजे दर्ज किए गए। पिछले वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर को भी दोपहर 2.30 पर 3.6 तीव्रता के झटके मध्य प्रदेश के सिंगरौली में महसूस किए गए। यहां 26 दिसंबर को भी कुछ झटके आए थे। मई को छोड़कर शेष सभी महीनों में देश के 14 राज्यों के 30 शहरों में 2.0 से 6.6 तीव्रता के झटके आए, परंतु कोई बड़ी जन-हानि नहीं हुई। दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तरकाशी एवं मणिपुर क्रमशः नौ, पांच, चार एवं दो बार झटकों से प्रभावित हुए। देश के उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र में ज्यादा झटके आए। कुछ भूकंप के क्षेत्र काफी व्यापक भी रहे। 24 जनवरी को दोपहर 2.30 पर 3.0 सेकंड तक दिल्ली-एनसीआर में 5.3 तीव्रता के झटके आए। इन झटकों का प्रभाव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ भागों में देखा गया।

19 फरवरी को मध्य प्रदेश के धार, बड़वानी, अलिराजपुर सहित कई जिलों में दोपहर 12.45 पर छह सेकंड तक तीन से चार तीव्रता के झटके आते रहे। इसका केंद्र धार जिले में 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। दो अप्रैल को प्रातः जबलपुर, नर्मदापुरम एवं पंचमढ़ी में 3.6 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। नर्मदापुरम में 21 मार्च की रात को भी कुछ झटके आए थे। 21 मार्च को

दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में रात 10.20 पर 6.6 तीव्रता का कंपन हुआ था। तीन अक्टूबर को दोपहर में फिर दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कंपन हुआ। इस भूकंप की तीव्रता 5.3 से 6.3 रेक्टर पैमाने पर आंकी गई। इसी दिन नेपाल में भी शाम को चार से पांच तीव्रता के झटके आने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए एवं 10 लोग घायल हुए। गुजरात के कच्छ एवं राजकोट में 30 जनवरी एवं दो फरवरी को 4.3 तीव्रता के झटके आए, परंतु कोई हानि नहीं हुई। मणिपुर के उखरूल व विष्णुपुर में चार फरवरी व 16 अप्रैल को हल्के झटके दर्ज किए गए।

छत्तीसगढ़ के गौरला-पेंड्रा-मरवाही और कोरबा जिले के गांवों में 13 अगस्त की रात एवं सरगुजा तथा अनूपपुर में 28 अगस्त को भूकंप आया। कलबुर्गी (कर्नाटक), जोरहाट (असम), बोकानेर (राजस्थान), बिजनौर व अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में क्रमशः 18 जनवरी, 18 मार्च, 25 मार्च, तीन अप्रैल व पांच नवंबर को हल्के झटके आए।

हिमालयी क्षेत्र एवं दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते भूकंपों के संदर्भ में भू-वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे-छोटे कंपनों से भूगर्भीय ऊर्जा निकल जाती है एवं बड़े भूकंप का खतरा कम हो जाता है। हिमालय के नीचे स्थित 'यूरेशियन प्लेट' के 'इंडियन प्लेट' से टकराने से 200 किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली-एनसीआर में कुछ भ्रंश (फाल्ट) बन गए हैं, जिनके कारण इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा झटके आ रहे हैं। दूसरी ओर, मध्यभाग के संदर्भ में भूकंप वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां भी 'टेक्टोनिक प्लेट्स' में हो रही हलचल से झटके आ रहे हैं। खंडवा एवं नर्मदा नदी से जुड़े जिले ज्यादा संवेदनशील बताए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भी नर्मदा व सोन नदी घाटी वाले जिलों में ज्यादा खतरा बताया है। इन जिलों में पिछले तीन वर्षों में 38 झटके दर्ज किए गए हैं। बढ़ता भूकंप देश के लिए एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। अतः गंभीरता से ध्यान देकर ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि जानमाल की हानि कम-से-कम हो।

राहुल की न्याय यात्रा पर कही बड़ी बात BJP में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ ने लगाया विराम!



कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं मध्यप्रदेश की जनता और कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर राहुल गांधी जी का संबल और साहस बनें। हम और आप मिलकर अन्याय के खिलाफ जारी इस महाअभियान को अंजाम तक पहुँचायेंगे।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 23 फरवरी को कहा कि मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। उनका यह बयान उनके कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जाने की अफवाहों के बीच आया है। कमलनाथ ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि मध्यप्रदेश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगवानी के लिए उत्साहित हैं। अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ हम सबके नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में सड़कों पर उतरकर एक निर्णायक लड़ाई का एलान कर चुके हैं।

कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं मध्यप्रदेश की जनता और कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर राहुल गांधी जी का संबल और साहस बनें। हम और आप मिलकर अन्याय के खिलाफ जारी इस महाअभियान को अंजाम तक पहुँचायेंगे। इससे पहले कमलनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए 'वर्चुअल' माध्यम से एक बैठक में भाग लिया था। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य में चार दिनों की यात्रा के दौरान राहुल रोड शो और सभाएं करेंगे। वह छह मार्च को उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और धार जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बैठक में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा और जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी, वहां से पार्टी के जिला प्रभारी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। यात्रा दो मार्च को राजस्थान से मुंबई में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यह छह मार्च को सैलाना से फिर से राजस्थान में प्रवेश करने से पहले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, धार और रतलाम से होकर गुजरेगी। राहुल छह मार्च को धार जिले के बदनावर कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

सेना भर्ती के लिए 1.50 लाख युवाओं का आंदोलन

अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी 'नाम-
नमक-निशान' की लड़ाई...

देश के विभिन्न हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले करीब डेढ़ लाख युवा, जिन्होंने सेना में भर्ती होकर 'नाम-नमक-निशान' के जज्बे को साकार करने का सार्थक प्रयास किया था, अब उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी। अभी तक इन युवाओं की यह लड़ाई, सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इन अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आशवासन नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी के 'पूर्व सैनिक विभाग' के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी के मुताबिक, 'युवा न्याय' की कानूनी लड़ाई प्रारंभ होने जा रही है। अग्निपथ योजना की वजह से सेना की पेंडिंग भर्तियों में चयनित 1.5 लाख युवाओं के हक व न्याय की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। सेना भर्ती के अभ्यर्थियों ने रोहित चौधरी के साथ पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से बातचीत की है। चौधरी ने बताया, इन युवाओं के साथ न्याय होगा। वे सेना में भर्ती होने की लड़ाई अवश्य जीतेंगे।

अभ्यर्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 'अग्निपथ' योजना लाकर लाखों युवाओं के सपनों को रौंद दिया है। डेढ़ लाख से अधिक युवाओं को 'अग्निपथ' योजना लागू होने से पहले तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए चयनित किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें ज्वाइनिंग लैटर नहीं मिला है। इनमें एयरफोर्स के 7000 युवा और नर्सिंग असिस्टेंट्स आर्मी (मेडिकल कोर) के लगभग 2,500 नर्सिंग असिस्टेंट भी शामिल हैं। इनकी भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। 2019 से 2021 के बीच आर्मी में हुई लगभग 97 भर्तियों को भी 'अग्निपथ' योजना की आड़ में रद्द कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के 'पूर्व सैनिक विभाग' के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी बताते हैं, इसमें इन अभ्यर्थियों का क्या कसूर था। इन युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए अथक मेहनत की थी।

उपराष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शन : बतौर रोहित चौधरी, कड़ी मेहनत के बावजूद इन युवाओं को सेना की वर्दी नहीं मिल सकी। इन युवाओं ने सेना भर्ती के दो पड़ाव

गत वर्ष अभ्यर्थियों ने राहुल
गांधी से की थी मुलाकात

गत वर्ष कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन युवाओं से मुलाकात की थी। तब राहुल ने कहा था कि सरकार ने 'अग्निपथ' योजना की आड़ में सेना एवं वायुसेना में स्थायी भर्ती के लिए संचालित प्रक्रिया को रद्द कर, इन युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। अनेक युवा, 'सत्याग्रह की भूमि' चम्पारण से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे थे। राहुल गांधी ने इन युवाओं से मिलने के बाद एक्स पर लिखा था, 'अस्थायी भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना (अग्निपथ) की आड़ में 2019-21 तक चली सेना एवं वायुसेना की 'स्थायी भर्ती प्रक्रिया' को रद्द कर सरकार ने अनगिनत परिश्रमी एवं स्वयंसेवक युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। राहुल ने लिखा, 'दुखद है कि 'सत्याग्रह की भूमि' चम्पारण से लगभग 1100 किलोमीटर पैदल चल कर अपना हक मांगने दिल्ली आए इन नौजवानों के संघर्ष को मीडिया के किसी भी कैमरे में जगह नहीं मिली। 'छोटे-छोटे कमरों में रहकर बड़े बड़े लक्ष्यों को साधने वाले इन महत्वाकांक्षी छात्रों की पीड़ा शायद मुख्यधारा के मीडिया के 'प्राइम टाइम' में जगह न बना सके। हम सिर्फ 'रोजगार की बात' कर रहे इन युवाओं के संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक उनके साथ हैं।

भी पार कर लिए थे। केंद्र सरकार ने उसी वक्त 'अग्निपथ' योजना लागू कर दी। नतीजा, नियुक्ति पत्र लेने का इंतजार कर रहे डेढ़ लाख युवाओं के सपने चूर हो गए। तब से लेकर अब तक वे युवा, सड़कों की खाक छान रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन युवाओं ने अपने हक के लिए हुंकार भरी है। पिछले दिनों में युवाओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया था। युवाओं के प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। उन्हें समय नहीं मिला तो अभ्यर्थियों ने मजबूर होकर उपराष्ट्रपति आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वह प्रदर्शन बिस्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। जिस वक्त उपराष्ट्रपति का काफिला गुजर रहा था, युवाओं ने लाइन पार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दूर खड़े होकर प्रदर्शन किया।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा व श्रीनिवासन भी पहुंचे थे : गत दिनों जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हजारों अभ्यर्थियों को अपना समर्थन देने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी भी पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार को बिना किसी देरी के इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। अग्निपथ योजना आने से पहले इन युवाओं का आर्मी व वायुसेना में निकली भर्तियों में चयन हो चुका था। इन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार था। सेना भर्ती में चयनित होने के बावजूद, डेढ़ लाख से ज्यादा युवा मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज बेरोजगार हैं। देश सेवा का जूनून पाले ये युवा दर दर की टोकरें खाने को मजबूर हैं। अग्निपथ योजना की आड़ में सेना में चयनित डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया।

सामूहिक विवाह आयोजन में सख्ती... एक बार में 100 से अधिक शादियां नहीं होंगी

राज्य सरकार ने ये कदम बलिया जिले में एक सामूहिक विवाह समारोह में हुई धोखाधड़ी के हालिया मामले के मद्देनजर उठाए हैं, जहां 240 अपात्र लोगों ने 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण कराया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान पहले से शादीशुदा लोगों की दोबारा शादी कराई गई थी



उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अंतर्गत होने वाले किसी भी आयोजन में अब 100 से अधिक शादियां नहीं हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने यह जानकारी दी। अरुण ने साथ ही बताया कि हर विवाह का पंजीकरण अब कार्यक्रम स्थल पर ही किया जाएगा और फोटो युक्त विवाह प्रमाणपत्र भी तुरंत जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने ये कदम बलिया जिले में एक सामूहिक विवाह समारोह में हुई धोखाधड़ी के हालिया मामले के मद्देनजर उठाए हैं, जहां 240 अपात्र लोगों ने 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण कराया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान पहले से शादीशुदा लोगों की दोबारा शादी कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण ने रविवार को कहा, "अब सामान्य सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में 100 से अधिक विवाह नहीं कराए जाएंगे। अगर किसी ऐसे कार्यक्रम में कोई मंत्री या कोई अन्य विशिष्ट अतिथि आ रहा हो और उस कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वयं मौजूद हों तो 100 से अधिक विवाह कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, "इसके अलावा हर शादी का पंजीकरण अब कार्यक्रम स्थल पर ही किया जायेगा और विवाह प्रमाणपत्र भी तुरंत जारी होगा। दूल्हा-दुल्हन की तस्वीर खींची जाएगी, सभी रस्म और संस्कार पूरे होने के बाद विवाह को कम्प्यूटर पर दर्ज किया जाएगा।

इसके अलावा प्रत्येक नवविवाहित जोड़ों के विवरण को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) और आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह में गड़बड़ियों को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम सचिव और लेखपाल को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी कि इन कार्यक्रमों में शादी करने वाला युवक या

युवती पहले से विवाहित तो नहीं है। समाज कल्याण मंत्री अरुण ने कहा कि मौजूदा नियमावली के अनुसार सत्यापन की जिम्मेदारी खंड स्तर के अधिकारियों की है। उन्होंने कहा, "प्रदेश सरकार खंड स्तर से सत्यापन के बाद उनमें से एक निश्चित प्रतिशत मामलों का जिलाधिकारी कार्यालय और उप निदेशक समाज कल्याण से फिर से सत्यापन कराने पर भी विचार कर रही है। बलिया जिले में 25 जनवरी को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गड़बड़ी का मामला नौ फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी गुंजा। समाजवादी पार्टी के लाल जी वर्मा ने यह मामला सदन में उठाया। मंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर घर की बेटी का विवाह धूमधाम से हो। अरुण ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार "भ्रष्ट लोगों से प्रभावी ढंग से निपटने" के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, "बलिया के मामले में तीन अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, भले ही वह अधिकारी हो या कोई दलाल। अरुण ने कहा, जहां एक तरफ चोर को पकड़ा गया है, वहीं ताले (संपूर्ण व्यवस्था) को भी मजबूत किया गया है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, सामूहिक विवाह योजना के तहत हर साल हजारों जोड़ों की शादियां हो रही थीं और कहीं से किसी गड़बड़ी की बात सामने नहीं आयी थी, लेकिन बलिया में ऐसी गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद अब विभाग प्रत्येक जनपद में होने वाले ऐसे आयोजनों की बहुत बारीकी से जांच-पड़ताल कर रहा है। हर मामले की कई स्तर पर जांच और गहन पड़ताल किए जाने की व्यवस्था की गयी है।"

बलिया में 25 जनवरी को एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान करीब 537 शादियां हुई थीं जिनमें से

240 शादियों में गड़बड़ियां पायी गयी थीं। इस मामले में अभी तक 16 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और समाज कल्याण विभाग समेत विभिन्न विभागों के पांच सरकारी कर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। योजना को शुरू करने के वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 तक कुल 2,77,292 सामूहिक विवाह कराए गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के 27,782, अन्य पिछड़ा वर्ग के 78,300, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के 1,50,357 एवं सामान्य वर्ग के 10,353 जोड़े शामिल हैं। पिछले वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 विवाह संपन्न करवाए गए। इस वर्ष अभी तक 66,673 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है। इस वर्ष करीब एक लाख 10 हजार शादियों का लक्ष्य रखा गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत विवाह करने वाली महिला के खाते में 35,000 रुपये सहायता राशि भेजी जाती है।

विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजन के दौरान भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु 6,000 रुपए प्रति जोड़ा व्यय किया जाता है। एक जोड़े के विवाह पर कुल 51,000 रुपए व्ययभार आता है। अरुण ने कहा कि बलिया मामले में फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के बाद "हमने व्यवस्था कड़ी कर दी है लेकिन किसी भी जनपद में ऐसे कार्यक्रमों पर किसी तरह की रोक नहीं लगायी है। अब गहन जांच-पड़ताल और कड़ी निगरानी में ही ऐसे सामूहिक विवाह के आयोजन कराए जा रहे हैं।

कीटनाशकों का नया विकल्प है सौर ऊर्जा, तकनीक साबित हो रही पर्यावरण अनुकूल



मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में धान की पैदावार काफी अच्छी होती है। यहां का किसान धान में लगने वाले कीड़ों से परेशान था। जिले के कटंगझरी ग्राम के वीरेंद्र धांद्रे एवं अन्य किसान कृषि विभाग से मिले सौर ऊर्जा आधारित सोलर लाइट ट्रेप लगाया और अब बगैर किसी रसायन के उनकी फसल निरापद है।

घटती जोत और बढ़ती आबादी ने अधिक फसल उत्पादन का दबाव बढ़ा दिया है। खेतों में नैसर्गिक रूप से कीट-पतंगे होते हैं, जिनमें से कई खेती और धरती के लिए जरूरी होते हैं। फसल को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए छिड़की जाने वाली रासायनिक दवाएं न केवल फसलों के पोषक तत्वों की दुश्मन हैं, बल्कि प्रकृति-मित्र कीट-पतंगों को भी नष्ट कर देती हैं। लेकिन अब खेतों में सूरज की चमक से चलने वाले प्रकाश-उत्पादक बल्ब बगैर किसी नुकसान के मामूली व्यय में हानिकारक कीटों का नाश कर देते हैं।

तेजी से हो रहे मौसमी बदलाव और बढ़ते तापमान ने हर फसल चक्र के दौरान फसलों पर अलग-अलग कीटों के प्रकोप में भी बढ़ोत्तरी कर दी है। हर साल सैकड़ों किसान जहरीली दवाओं के बेतहाशा इस्तेमाल के चलते मौत या दमे-कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार होते हैं। हमारे देश में हर साल कोई दस हजार करोड़ रुपये के कृषि-उत्पाद खेत या भंडार-गृहों में कीड़ों के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस बर्बादी को रोकने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा। वर्ष 1950 में इसकी खपत 2,000 टन थी, लेकिन आज कोई 90 हजार टन जहरीली दवाएं देश के पर्यावरण में घुल-मिल रही हैं। इसका कोई एक तिहाई हिस्सा विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के

अंतर्गत छिड़का जा रहा है। वर्ष 1960-61 में केवल 6.4 लाख हेक्टेयर खेत में कीटनाशकों का छिड़काव होता था, लेकिन आज अनुमानतः करीब डेढ़ करोड़ हेक्टेयर में इनका छिड़काव होता है।

ये कीटनाशक जाने-अनजाने में पानी, मिट्टी, हवा, जन-स्वास्थ्य और जैव विविधता को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इनके अंधाधुंध इस्तेमाल से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। कई कीटनाशकों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। इस्तेमाल की जा रही दवाओं का महज 10 से 15 फीसदी ही असरकारक होता है, शेष जहर मिट्टी, भूगर्भ जल, नदी-नालों का हिस्सा बन जाता है। कीट नियंत्रण के लिए सोलर लाइट ट्रेप तकनीक का इस्तेमाल कम लागत वाला और नुकसान रहित है। सौर ऊर्जा संचालित कीट जाल पूरी तरह से स्वचालित, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल है, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट लगी है। दिन में सूर्य के प्रकाश में सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा एकत्रित होती है और अंधेरा होने पर सेंसर के कारण यंत्र में लाइट चालू हो जाती है, जो कीटों को आकर्षित करती है। ट्रेप में कीटों के आने के बाद कीट नीचे लगी जाली में फंस जाते हैं। इस प्रकार खेत में किसानों को तना छेदक तितली और अन्य कीटों से फसलों को बचाने में मदद मिलती है।

यह अत्याधुनिक उपकरण कीट और कीड़ों के पैटर्न की पहचान करता है और उसके अनुसार कीट प्रबंधन और नियंत्रण योजना विकसित करता है। इसकी पकड़ में सभी उड़ने वाले निम्फ और वयस्क कीड़े आदि आते हैं।

इसकी तकनीक बेहद सामान्य-सी है, जिसका कोई खास रखरखाव भी नहीं होता। इसमें स्वचालित सौर लाइट ट्रेप में 10 वाट का सोलर लाइट पैनल है, जो बैटरी को चार्ज करता है। इसकी खासियत है कि यह मशीन केवल शत्रु कीटों को निशाना बनाती है। ऐसे कीट शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच अधिक सक्रिय होते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित यंत्र की लाइट अंधेरा होते ही शुरू हो जाती है और सुबह उजाला होते ही बंद। खेत में हर पौधे की लंबाई अलग-अलग होती है, इसलिए इस उपकरण को इस तरह ऊंचाई पर लगाया जाता है कि औसत ऊंचाई पर बैठे कीट इसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। इस साधारण-सी तकनीक के गांव तक पहुंचने में एक ही व्यवधान है-ताकतवर अंतरराष्ट्रीय कीटनाशक लॉबी, जिसका अरबों का उत्पाद इसके चलते बिकना बंद हो सकता है। इसे ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से लिया जा सकता है। इस पर सरकार कुछ सब्सिडी भी देती है, लेकिन अभी इसका व्यापक स्तर पर प्रचार बहुत कम है।

कोविड ने बदल दी दुनिया, छोटे शहरों का रुख करती जिंदगी



कोविड ने दुनिया को बदलकर रख दिया। यह हम सभी जानते हैं कि इससे मानव जीवन की विनाशकारी क्षति हुई, लेकिन इसने एक मौन आंदोलन को भी जन्म दिया, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों में स्थानांतरित होने लगे और उन्होंने शांत व धीमी गति वाले जीवन को चुना। मैंने खुद ऐसा किया है, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम से मैं एक छोटे घाटी शहर देहरादून में स्थानांतरित हो गई हूँ।

हालांकि मैं इन दोनों शहरों में आती-जाती रहती हूँ, लेकिन अब मैं अपना ज्यादातर समय देहरादून में ही बिताती हूँ, जो एक छोटा अनोखा शहर है और शैक्षणिक संस्थानों, सेना और सेवानिवृत्त लोगों का प्रमुख केंद्र भी है। यहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन हवा अपेक्षा साफ है। कोविड के दौरान, विशेष रूप से डेल्टा वायरस की लहर के समय, जब अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि बड़े शहरों में रहने के नुकसान ज्यादा हैं।

सामान्य दिनों में लंबा ट्रैफिक जाम, वायु गुणवत्ता की बदतर स्थिति, चरम मौसमी स्थितियाँ और व्यस्त व आक्रामक सामाजिक माहौल ऐसी चीजें हैं, जो लोगों को बड़े शहरों से दूर कर रही हैं। कोविड काल के बाद प्रचलित मिश्रित कार्य-संस्कृति का मतलब यह भी है कि जो लोग खर्च उठाने में सक्षम हैं, वे तेजी से स्थानांतरित हो रहे हैं। चाहे राजमार्गों का विकास हो या उड़ान योजना, पिछले दस वर्षों में बढ़ी कनेक्टिविटी ने भारत को आपस में अधिक जोड़ा है। इसके साथ ही इंटरनेट ने भी दूरियां कम की हैं। और यह सब इतनी तेजी से बदला है कि हैरानी होती है।

एक दशक पहले जब मैं टीवी बहस में शामिल होती थी, तो कैमरामैन, लाइटमैन और साउंडमैन के साथ एक बड़ी ओबी वैन आती थी। वे लोग मेरे घर में लाइट और कैमरा लगाते थे, मुझे लाइव टीवी स्टूडियो से जोड़ते थे। आज मैं चाहे दुनिया में कहीं भी रहूँ, जूम के माध्यम से टीवी बहस में शामिल हो सकती हूँ। यह एक ऐसा बदलाव है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अस्तित्व के संकट और परिस्थितिवश मजबूरी में लोग बड़े शहरों में रहने के लिए बाध्य होते थे, लेकिन अब कई लोग ऐसी बाध्यता महसूस नहीं करते हैं।

देहरादून में मेरे अपार्टमेंट में एक नई बात यह है कि यहां

बहुत से वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन तीस से चालीस की उम्र के लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो बड़े से छोटे शहरों में शहरी परिप्रेक्ष्य लेकर आए हैं और साथ ही संतोष की हवा भी। भारत में हुए तीव्र विकास से उन लोगों के लिए छोटे शहरों में रहना आसान हो गया है, जो बड़े शहरों में रहने के आदी हैं। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में भी काफी सुधार हुआ है। जीवन-शैली में बदलाव अब उतना कठोर नहीं रह गया है, जितना पहले माना जाता था। असल में जीवन-यापन की लागत सस्ती हो गई है और पैसे के लिहाज से अचल संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है। शिक्षा के प्रचुर अवसर हैं और सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक है।

मेरे बचपन में दिल्ली से देहरादून पहुंचने में रुकते हुए सात से नौ घंटे लगते थे, लेकिन अब मुश्किल से चार घंटे लगते हैं तथा इसमें और कमी होने वाली है। गुरुग्राम से जयपुर मात्र तीन घंटे दूर है और बीस साल पहले गाड़ी से इतनी दूरी तय करने में पांच घंटे लगते थे। छोटे शहर सामाजिक रूप से घुलने-मिलने के भी काफी अवसर प्रदान करते हैं, लोगों के पास काफी समय होता है और वे एक-दूसरे का साथ ढूंढते हैं।

बड़े शहरों, जहां मानव अस्तित्व एक निश्चित संकीर्णता में घिर गया है, के विपरीत देश के छोटे शहरों और कस्बों में समुदाय की अवधारणा अब भी काफी जीवित है। जब यह सदी शुरू हुई होगी, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत के लोग छोटे शहरों में जाना चाहेंगे, लेकिन आज हम छोटे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता, यात्रा में आसानी और ई-कॉमर्स-इन सबने इस बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है।

अब चुनौती यह है कि छोटे शहरों की गुणवत्ता बनाकर रखी जाए और इन्हें शहरी फैलाव न बनने दिया जाए। विवेकपूर्ण शासन से ऐसा संभव है। इसके अलावा

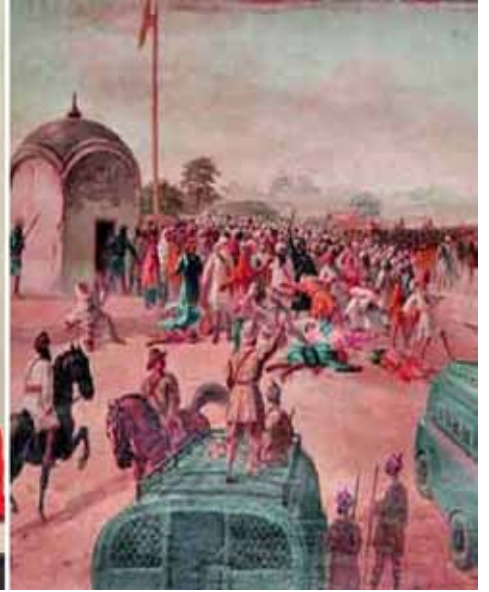
यह प्रवासन भारतीयों की प्राथमिकता और मूल्यों में ठोस बदलाव को भी दर्शाता है, जो इस पारंपरिक आख्यान को चुनौती देता है कि सफलता महानगरीय जीवन का पर्याय है। भारत के लोगों में आत्मबोध और सांस्कृतिक जागरूकता का विकास तेजी से हो रहा है। पश्चिमी जीवन-शैली का अंधानुकरण थम गया है और लोगों ने उस जीवन-शैली को विफलता को पहचान लिया है। समुदाय और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने वाली भारतीय जीवन-शैली ऐसी समृद्धि लाती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती।

मानसिक स्वास्थ्य की मूक महामारी से बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आधुनिक समय में यह बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाएं और उसे समृद्ध करें। और यह पूरी तरह संभव है। लंबी जीवन-प्रत्याशा वाले भौगोलिक क्षेत्रों यानी ब्लू जोन्स का अध्ययन दर्शाता है कि इसका एक प्रमुख कारण सामुदायिक जीवन जीना और दूसरे मनुष्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहने से लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है- फोन या इंटरनेट पर नहीं। जैसे-जैसे ज्यादा भारतीय सफलता को फिर से परिभाषित करेंगे और चूहा-दौड़ से अधिक कल्याण को प्राथमिकता देंगे, बड़े शहरों से छोटे शहरों में जाने का चलन बढ़ेगा, देश के जनसांख्यिकी स्वरूप में बदलाव होना जारी रहेगा। यह जीवन के प्रति अधिक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है कि शहरीकरण ही समृद्धि का अंतिम रास्ता है। छोटे शहरों की शांति को अपनाकर अब लोग कामयाबी की नई परिभाषा तलाश रहे हैं, जो अराजक शहरी जीवन-शैली के ऊपर खुशी, स्वास्थ्य और सामुदायिक भावना को तवज्जी देती है। गांधी जी ने जिस भारत को गांवों में बताया था, वह नए समय में छोटे-छोटे शहरों में भी दिखाई देता है।

जैतो मोर्चा आंदोलन के 100 वर्ष पूरे...

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इस प्रसंग का स्वर्णिम इतिहास

‘जैतो मोर्चा’ गंगसर साहिब सिक्खों द्वारा अहिंसात्मक पूर्ण एवं शांतिपूर्ण किये गये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का स्वर्णिम इतिहास है। 21 फरवरी 2024 को जैतो मोर्चा आंदोलन के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह एक साहसपूर्ण संघर्ष का इतिहास है जो सिक्खों द्वारा अंग्रेजों से अपनी संस्कृति व धार्मिक स्थानों को बचाने के लिए अहिंसात्मक रूप से किया गया था। अंग्रेज पंजाब में अपना शासन स्थापित करने के लिए बहादुर समुदाय को कुचलने को अपना प्राथमिकता माना।



अंग्रेजों ने सिक्खों पर अत्याचार किये जिनके विरोध में सिक्खों ने संगठन बनाए और इन संगठनों ने जैतो मोर्चा आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सिक्खों और अंग्रेजों के बीच मुख्य संघर्ष था। नाभा रियासत के महाराजा रिपुदमन सिंह सिक्खों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हटाने के लिए 9 जुलाई 1923 को महाराजा रिपुदमन को जबरन हटाकर उनके नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बिठाना चाहा।

5 अगस्त, 1923 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाभा के महाराजा द्वारा आयोजित एक सभा में सहानुभूति प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा ‘सभी उचित और शांतिपूर्ण तरीकों से महाराजा रिपुदमन सिंह के साथ हुए अन्याय को दूर किया जाए।’ इस संकल्प पर अमल करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 9 सितम्बर, 1923 को ‘नाभा दिवस’ मनाए का निर्णय लिया। सिक्ख संगत द्वारा गांव-गांव धार्मिक दीवान, नगर कीर्तन और महाराजा रिपुदमन सिंह के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए अरदास में शामिल होने की अपील की गई। और इस तरह पूरे उत्साह के साथ नाभा दिवस हर जगह बड़े जोश के साथ मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गईं।

सिक्ख संगत ने 25, 26 व 27 अगस्त, 1923 को नाभा के गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब, जैतो में दीवान सजाने और श्री अखंड पाठ साहिब करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने कार्यक्रम में विघ्न डालने के लिए सिक्खों के नामों की एक सूची तैयार की और लंगर चलाने वाली संगत को डराया। साथ ही नाभा रियासत के सिक्खों को परेशान भी किया। प्रबंधकों ने हालात खराब होते देख लंगर की सेवा के लिए दीवान में अपील की, जिसको स्वीकार करते हुए सरदार नंद सिंह (रियासत फरीदकोट) ने लंगर का प्रबंध करने की पेशकश की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

द्वारा पंथ को की गई अपील के कारण 9 सितंबर, 1923 को ‘नाभा दिवस’ मनाते हुए सिक्ख रियासतों और पंजाब के लगभग सभी शहरों में नगर कीर्तन निकाले गए, दीवान सजाए गए, प्रस्ताव पारित किए गए और अरदास की गईं। जैतो मंडी में भी नगर कीर्तन निकाला गया और गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब में दीवान सजाकर श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किये गये।

इस समय नाभा राज्य का प्रशासन ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त श्री विल्सन जॉनस्टन के अधीन था। 9 सितंबर, 1923 को नगर कीर्तन में भाग लेने वाले सिक्ख अकालियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 सितंबर, 1923 को ब्रिटिश सैनिकों ने सिक्खों के दीवान में घुसकर सेवादारों सहित सभी उपस्थित संगत को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने श्री अखंड पाठ साहिब की सेवा में बैठे ज्ञानी इंंदर सिंह को भी बांह से पकड़कर नीचे गिरा दिया और घसीटते हुए ले गए। यह जानकारी सभी जगह फैल गयी, जिसके बाद सिक्खों ने एकत्रित होकर विरोध किया।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने सदस्यों के अलग-अलग समय पर तीन समूह गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब, जैतो भेजे। प्रत्येक समूह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह देखकर संगत ने प्रतिदिन 25-25 सिक्खों का जत्था गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब, जैतो भेजने का निर्णय लिया। ऐसा पहला समूह 15 सितम्बर, 1923 को श्री अकाल तख्त साहिब से पैदल रवाना हुआ। प्रतिदिन 25-25 सिक्खों को जैतो भेजने पर कोई संतोषजनक परिणाम न देखकर एक बार तो पूरा देश गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन गहन विचार के तुरंत बाद शिरोमणि कमेटी ने 25 की बजाय 500-500 सिक्खों को जैतो भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत वे 9 फरवरी, 1924 को गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब, जैतो में श्री

अखंड पाठ साहिब प्रारम्भ करने के लिए निकल पड़े। कई दिन चलने के बाद 20 फरवरी, 1924 को शहीदी जत्था अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। फरीदकोट के बरगाड़ी गांव पहुंचकर 21 फरवरी 1924 को सुबह ‘आसा दी वार’ का कीर्तन और दीवान खत्म करके जत्था जैतो की ओर चल पड़ा, जोकि 5-6 मील की दूरी पर था।

अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद 500-500 सिक्खों के 13 अन्य शहीदी जत्थे जैतो पहुंचे और गिरफ्तारियाँ दे दी। गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब की ओर जाने वाली सड़क पर कंटीले तार लगा दिए गए और भारी पुलिस तैनात कर दी गई। गुरुद्वारे के पास पुलिस जगह-जगह बंदूकें ताने खड़ी थीं। शहीदी जत्था गुरुद्वारा श्री टिब्बी साहिब से लगभग 150 गज पीछे था जहां पर एक अंग्रेज अधिकारी ने जत्था को आगे बढ़ने से रोका और कहा, ‘रुको, आगे मत बढ़ो। नहीं तो बंदूक चल जाएगी, गोली चल जाएगी।’ सभी ने यह आदेश सुना, लेकिन जत्था नहीं रुका और गुरुद्वारा श्री टिब्बी साहिब की ओर लगातार बढ़ता रहा। यहां तक कि जब एक मां द्वारा ले जाए जा रहे एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई तो उस मां ने बच्चे के शव को जमीन पर लिटा दिया और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती चली गई, हालांकि, इसके तुरंत बाद उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और वह भी शहीद हो गईं। इसके बावजूद भी जत्थे के किसी भी सिक्ख ने शांति भंग नहीं की। अंग्रेज अधिकारी यह देखकर सेना की ओर दौड़ा और सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन करते हुए तीनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गयी। कुछ देर के अंतराल के बाद दूसरी बार भी गोलियाँ चलनी शुरू हो गयीं। ये

गोलीबारी पांच मिनट तक निरंतर चलती रही, लेकिन सिक्खों का जत्था शांतिपूर्वक, साहस और शीतलता के साथ आगे बढ़ता गया इस गोलीबारी में इतिहास के अनुसार, लगभग 300 सिक्ख घायल हुए एवं 100 से अधिक सिक्खों ने शहीदियाँ प्राप्त की।

गोलीबारी बंद होने तक सभी संगत गुरुद्वारा श्री टिब्बी साहिब पहुँच चुके थे। इसके बाद जत्थे के घायल और शहीद सिक्खों को गुरुद्वारा साहिब में लाने के प्रयास शुरू हो गए। जैतो के गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब में हुई इस दर्दनाक घटना से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सिक्खों में आक्रोश की लहर फैल गयी। जैतो के इस मोर्चे में कलकत्ता से एक जत्थे के अलावा, 11 सिक्खों सहित एक जत्था कनाडा से आया, दो जत्थे चीन से आए, एक शंघाई से और दूसरा हांगकांग से। सिक्खों में गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब जाने और श्री अखंड पाठ साहिब जी शुरू करने का उत्साह और भी बढ़ गया। परिणामस्वरूप, कुल 17 शहीदी जत्थों ने क्रमिक रूप से मार्च किया और इस मोर्चे में अंततः सफल हुए। सत्रहवाँ शहीदी जत्था 27 अप्रैल, 1925 को श्री अकाल तख्त साहिब से लायलपुर होते हुए पैदल जैतो की ओर निकला। रास्ते में सिक्खों को सूचना मिली कि ब्रिटिश सरकार ने इस संबंध में सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह जत्था गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब जैतो में पहुँचा और इस प्रकार वहाँ पहला श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किया गया।

गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब, जैतो में श्री अखंड पाठ साहिब को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करके नए सिरे से शुरू करने के लिए सिक्खों को एक वर्ष और दस महीने तक अथक प्रयास करना पड़ा। इस संघर्ष के दौरान, सैकड़ों सिक्ख शहीद हुए, हजारों सिक्ख घायल हो गए, कई विकलांग हो गए। कई सिक्खों की संपत्ति और घर ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए और उन्हें उनकी संबंधित रियासतों से निर्वासित कर दिया गया। कई सिक्ख सरदारों के पद भी छीन लिये गये। इस पूरे संघर्ष के दौरान सिक्खों को जैतों में जिन कठिनाइयों, तसीहों एवं अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनका पूरी तरह वर्णन करना भी संभव नहीं है।

पंजाब के गवर्नर सर मेल्कॉम हैली अंग्रेज शासक द्वारा सिक्खों को जैतो में श्री अखंड पाठ साहिब करने की अनुमति देने के मुद्दे पर सरकार, पंडित मदन मोहन मालवीय और भाई जोध सिंह के माध्यम से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार थी परंतु ब्रिटिश सरकार महाराजा रिपुदमन सिंह को अपने राज्य में पुनः स्थापित करने की इच्छुक नहीं थी। लेकिन इसी बीच सरकार द्वारा 7 जुलाई 1925 को सिक्ख गुरुद्वारा बिल सर्व सहमति के साथ पारित कर दिया गया।

इस जैतो मोर्चे के संघर्ष के कारण आगे जाकर ऐतिहासिक सकारत्मक परिणाम निकले। सारे बंदियों को रिहा कर दिया गया। सारी पाबंदियाँ हटा दी गईं और सिक्खों द्वारा 101 श्री अखंड पाठ साहिब की संपूर्णता 6 अगस्त 1925 को की गई। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि सिक्खों ने देश और धर्म की रक्षा करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध साहस के साथ पहला शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक आंदोलन करते हुए सफलता प्राप्त की।

गुरु साहिब के प्रेम के मार्ग पर चलते हुए सिक्खों ने ब्रिटिश सरकार को यह संदेश भी दिया कि सिक्ख युद्धों में साहस दिखाने के साथ-साथ शांतिपूर्ण विरोध भी व्यक्त कर सकते हैं और फ़तेह प्राप्त कर सकते हैं।

इस मोर्चे में भाग लेने वाले सिक्खों को ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया था। देश और धर्म की रक्षा के लिए सिक्खों द्वारा दिये गये इस बलिदान के सम्मान में भारतवासी सदैव नतमस्तक रहेंगे। जैतो मोर्चे की सफलता जहाँ एक तरफ अंग्रेजों की करारी हार थी वहीं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी इसमें दिशा-निर्देश तय करने की प्रेरणा मिली।

मुन्नाभाई के लिए आ गया कानून, सर्किट भी बचा नहीं पाएगा...

पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में पास हुआ बिल



लो कसभा में मंगलवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। विधेयक का उद्देश्य नकल और पेपर लीक पर लगातार लगाया है। साथ ही यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनईईटी, जेईई और सीयूईटी सहित विभिन्न डोमेन में सार्वजनिक एग्जाम में चीटिंग की समस्या से निपटना है। इसे अब राज्यसभा में भेजा जाएगा।

आरोप में तीन से पांच साल जेल और जुर्माना हो सकता है

विधेयक में अधिकतम तीन से पांच साल की जेल और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके प्रावधान मेधावी छात्रों और उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए हैं। विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को अस्वीकार करने के बाद विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा, 'सरकार संगठित अपराधों के मामले में उम्मीदवारों को बलिदान नहीं होने देगी।' उन्होंने कहा कि छात्र और अभ्यर्थी इस विधेयक के दायरे में नहीं आते हैं। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा।

पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के प्रावधान

दोषी को तीन से पांच वर्ष की जेल और दस लाख तक का जुर्माना। दूसरे परीक्षार्थी की जगह एग्जाम देने के दोषी को तीन से पांच वर्ष की जेल और दस लाख का जुर्माना। संस्थान से मिली भगत साबित होने पर संस्थान से परीक्षा का खर्च वसूला जाएगा। साथ ही एक करोड़ का जुर्माना और प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। संस्थान के इंचारज के दोषी होने पर तीन से दस साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। अपराध में शामिल लोगों को पांच से दस साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। **जम्मू-कश्मीर के स्थानीय चुनावों में आरक्षण पर चर्चा हुई** : संसद के बजट सत्र के 5वें दिन (मंगलवार) सदन की कार्यवाही जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकायों में आरक्षण पर चर्चा से शुरू हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2024 पेश किया। वहीं, राज्यसभा में कंसीडरेशन द कॉन्स्टीट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 और कॉन्स्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर्स बिल 2024 पर चर्चा शुरू हुई।

दो दशक के भीतर बदल गई लोगों की मानसिकता...

अब खान-पान की बजाय दूसरी चीजों पर बढ़ गया है खर्च

एनएसएस की रिपोर्ट का समग्र विश्लेषण किया जाए तो खाने-पीने की वस्तुओं में चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, दोनों ही जगह ब्रेवरेज यानि की पेय पदार्थों और प्रोसेस्ड फूड यानि की डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ा है।

नेशनल सैपल सर्वे की हालिया रिपोर्ट में रहन-सहन और खान-पान के प्रति देशवासियों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर 1999-00 से 2022-23 के दौरान खाने-पीने की वस्तुओं पर खर्च में तेजी से कमी देखी जा रही है वहीं खाने-पीने से इतर अन्य पर खर्च में बड़ा उछाल सामने आ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि यह बदलाव केवल शहरी क्षेत्रों में हो ऐसा नहीं है अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की बयार लगभग समान ही नहीं अपितु शहरी क्षेत्र से अधिक ही है। ऐसा नहीं है कि इस दौरान प्रति व्यक्ति व्यय में कमी आई हो अपितु प्रति व्यक्ति व्यय में लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। यह रुझान तेजी से बदलती प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है।

एक और तथ्य यह है कि कि खाद्यान्न के उपयोग में कमी आई है वहीं अखाद्य सामग्री की खरीद में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल यह बदलाव बदलते परिदृश्य को भी स्पष्ट करता है। एनएसएस की रिपोर्ट का समग्र विश्लेषण किया जाए तो खाने-पीने की वस्तुओं में चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, दोनों ही जगह ब्रेवरेज यानि की पेय पदार्थों और प्रोसेस्ड फूड यानि की डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ा है पर इन्हें भी शामिल कर लिया जाये तो भी खान-पान पर होने वाला व्यय 1999-00 की तुलना में 2022-23 आते आते बहुत कम हो गया है वहीं अखाद्य वस्तुओं पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा दिल खोलकर पैसा खर्च किया जा रहा है। लगता है जैसे अब लोगों की समान रूप से प्राथमिकताएं बदल गई हैं। बल्कि यह कहना अधिक युक्तिसंगत होगा कि अब रहन-सहन और सुख सुविधाओं के उपयोग में गांव किसी तरह से भी शहरों से पीछे नहीं रहे हैं। बल्कि रिपोर्ट से तो यही उभर कर आता है और यह स्पष्ट हो गया है कि माल संस्कृति के बावजूद अब उत्पादकों को ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा बाजार मिलने लगा है। इसे अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत भी माना जा सकता है तो दूसरी ओर मांनें या ना मांनें पर सर्वे से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि अब गांव गांव नहीं रहे और वह शहरों से कहीं पीछे नहीं रहना चाहते। यही कारण है कि उत्पादकों द्वारा अब ग्रामीण क्षेत्र को भी टारगेट बनाकर रणनीति तैयार की जाने लगी है।

देश में दो दशक में ही आये ड्रास्टिक बदलाव को आंकड़ों की भाषा में समझें तो ग्रामीण क्षेत्र में 1999-00 में खाद्य सामग्री पर 59.40 प्रतिशत राशि व्यय की जा रही थी वहीं 2022-23 आते आते यह घटकर 46.38 प्रतिशत ही रह गई। खास बात यह कि इसमें तेजी से बदलाव खासतौर से पिछले एक दशक में देखा गया है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 1999-00 में



खाद्यान्न पर खर्चा 48.06 प्रतिशत राशि की जाती थी जो 2022-23 आते आते कम होते हुए 39.17 प्रतिशत रह गई। सबसे खास बात यह कि खाद्यान्न में जो कमी आई है भले ही उसके पीछे विशेषज्ञ एक कारण सरकार द्वारा खाद्य सामग्री का निःशुल्क व कम कीमत पर वितरण माना जा रहा है पर यह गले उतरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि खाद्य सुरक्षा के तहत एक सीमा तक ही निःशुल्क खाद्य सामग्री का वितरण हो रहा है। हां कुछ हद तक खाने-पीने के बदलाव की बात कही जाती है पर यह भी सही नहीं मानी जा सकती क्योंकि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिख रही जितनी खाद्यान्न के उपयोग में कमी आई है। लगता है जैसे खाद्यान्न से लोगों का मोहभंग होता जा रहा है। पर इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत भी नहीं माना जा सकता।

1999-00 में ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न व खाद्यान्न के विकल्पों पर 22.23 प्रतिशत राशि व्यय होती थी जो दो दशक में ही कम होते होते इकाई की संख्या यानि कि 6.92 प्रतिशत पर आ गई है। यह तो गांवों की स्थिति है। शहरों में भी खाद्यान्न व खाद्यान्न उत्पादों पर होने वाला व्यय 12.39 से कम होकर 4.51 प्रतिशत रह गया है। दूसरी ओर खाद्य सामग्री में ही ब्रेवरेज और प्रोसेस्ड फूड को लिया जाये तो इसका उपयोग शहरी क्षेत्र में 6.35 प्रतिशत से बढ़कर 10.64 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 4.19 प्रतिशत से बढ़कर 9.62 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर अखाद्य वस्तुओं की खरीद की बात की जाए

तो ग्रामीण क्षेत्र में 40.60 प्रतिशत से बढ़कर 53.62 प्रतिशत हो गई तो शहरी क्षेत्र में 51.94 प्रतिशत से बढ़कर 60.83 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसमें भी ज्यादा उछाल इयूरेबल आइटम्स में देखा जा रहा है। लोगों की रुचि वाहन, एसी, फ्रीज, ओवन, प्लैट्स या मकान आदि की ओर बढ़ा है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि कपड़े-जूते और इसी तरह की निजी उपयोग की वस्तुओं पर व्यय में कमी आई है।

दरअसल यह दो दशक में देशवासियों के बदलते मिजाज की तस्वीर है। पर खाने पीने की वस्तुओं के उपयोग में कमी आना, डिब्बा बंद व पेय पदार्थों के उपयोग में बढ़ोतरी चिंता का विषय होनी चाहिए। इसी तरह से इयूरेबल आइटम्स के लिए जिस तरह से पर्सनल और अन्य तरह के लोन लेने व क्रेडिट कार्ड के उपयोग के कारण कर्ज के बोझ तले दबने को भी उचित नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो इनसे आज की पीढ़ी व आज के लोग तनाव, कुंठा, प्रतिस्पर्धा आदि को भी बिना किसी तरह का दाम चुकाये प्राप्त करने लगे हैं। एक समय था जब दो टाइम की दाल रोटी पहली आवश्यकता व प्राथमिकता होती थी, वह दो दशक में ही नेपथ्य में चली गई लगती है। सर्वे से यह तो साफ हो गया है कि आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र लगभग एक रफ्तार से एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और गांव शहर का भेद कम हो रहा है पर खाने पीने की आदतों में बदलाव भविष्य की चिंता का कारण बन सकता है।

ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा टिकट देगी भाजपा



इन चार जातियों को मिलेगी प्राथमिकता

भाजपा इस बार ऐतिहासिक बदलाव के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। सीटों के आवंटन में वह विपक्ष के उन सभी हमलों का पूरा जवाब देने की कोशिश करेगी, जिनके सहारे विपक्ष उसे घेरता रहा है। पहली सूची में इस बार सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय को टिकट मिलने की संभावना है... लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी भाजपा एक सप्ताह में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। भाजपा इस बार ऐतिहासिक बदलाव के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। सीटों के आवंटन में वह विपक्ष के उन सभी हमलों का पूरा जवाब देने की कोशिश करेगी, जिनके सहारे विपक्ष उसे घेरता रहा है। पहली सूची में इस बार सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय को टिकट मिलने की संभावना है, तो दलित और आदिवासी समाज को प्रमुखता देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाणित कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा चार जातियों महिला, युवा, गरीब और पिछड़े की बात करते रहे हैं। इस बार चुनाव में इन्हीं वर्गों को सबसे ज्यादा भागीदारी देकर वे इन वर्गों को सत्ता में भागीदारी देने की रणनीति अपना सकते हैं। जानकारी के अनुसार, टिकट बंटवारे में महिलाओं को प्रमुखता दी जाएगी, लेकिन जीतने की क्षमता किसी उम्मीदवार के चयन का सबसे बड़ा आधार होगी।

सबसे पहले उन सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है, जिसे पार्टी ने अपने लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सीटें माना है। लगभग 160 सीटों की इस सूची में वे सीटें शामिल हैं, जिस पर भाजपा को या तो कभी जीत हासिल नहीं हुई, या उन पर जीत में वोटों का अंतर बहुत कम रहा है। पार्टी ने यही रणनीति पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान भी अपनाई थी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, पार्टी 70 वर्ष से अधिक चुके सांसदों को इस बार टिकट से वंचित कर सकती है। इस कैटेगरी में आने के कारण पार्टी के कई बड़े दिग्गजों के टिकट भी कट सकते हैं। कुछ नेताओं के परिवार के सदस्य लंबे समय से भाजपा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन्हें टिकट देकर वरिष्ठ नेताओं को विश्राम देने की रणनीति अपनाई जा सकती है।

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में लोहे के संदूक को बाय-बाय

जवानों को मिलेगा ट्रॉली वाला मॉडर्न सूटकेस

खास बात है कि जवानों को लोहे के ट्रंक के बदले जो स्मार्ट सूटकेस मिलेगा, उसे कई तरह के परीक्षणों से गुजरना होगा। हालांकि अर्धसैनिक बलों के लिए इस सूटकेस को खरीदने का प्रपोजल लंबे समय से चल रहा था। इस दिशा में कई तरह के टेस्ट, जैसे सरफेस हार्डनेस टेस्ट, हैंडल जर्क टेस्ट और स्टैंडिंग पुल हैंडल जर्क टेस्ट आदि हो चुके हैं...



केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीएपीएफ' के तहत आने वाले असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी के जवानों को अब लोहे के संदूक से निजात मिलेगी। इन जवानों को अब पांच साल की वारंटी वाला मॉडर्न सूटकेस विद् ट्रॉली, मुहैया कराया जाएगा। खास बात है कि जवानों को लोहे के ट्रंक के बदले जो स्मार्ट सूटकेस मिलेगा, उसे कई तरह के परीक्षणों से गुजरना होगा। हालांकि अर्धसैनिक बलों के लिए इस सूटकेस को खरीदने का प्रपोजल लंबे समय से चल रहा था। इस दिशा में कई तरह के टेस्ट, जैसे सरफेस हार्डनेस टेस्ट, हैंडल जर्क टेस्ट और स्टैंडिंग पुल हैंडल जर्क टेस्ट आदि हो चुके हैं। अब बहुत जल्द सीएपीएफ जवान, स्मार्ट सूटकेस संग नजर आएंगे।

इस ट्रॉली सूटकेस पर पांच साल की वारंटी मिलेगी। सभी बल, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी खरीद कर सकते हैं। हालांकि खरीदने से पहले सूटकेस को कई तरह के मुश्किल परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ सहित सभी दूसरे बलों के जवानों यह स्मार्ट सूटकेस मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की स्थापना से लेकर अभी तक जवानों को लोहे का ट्रंक मुहैया कराया जाता है। अगर इसके कई फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। जैसे लोहे का ट्रंक, मजबूत रहता है। उसे बस, ट्रेन या ट्रक में जैसे मर्जी रख सकते हैं। हालांकि यहां पर जवानों को उस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब उसे छुट्टी आना होता है। उसे वह ट्रंक सार्वजनिक परिवहन में अपने साथ लाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस में उसे आसानी से नहीं रखा जा सकता। वजह, वह जगह बहुत ज्यादा घेरता है। इसी तरह ट्रेन में भी दिक्कत आती है। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से

आटो या टैक्सी के द्वारा आना हो, तो भी लोहे का ट्रंक का आसानी से फिट नहीं होता। अगर कोई छोटा वाहन है या आटो में उसे रखना हो तो ट्रंक के बाद किसी दूसरे सामान या सवारी के लिए जगह कम ही बचती है।

इन बलों के जवानों को अब जो मॉडर्न सूटकेस विद् ट्रॉली मुहैया कराया जाएगा, उसकी अपनी कई खूबियां हैं। जैसे, वह लोहे के ट्रंक की तुलना में काफी हल्का है। उसे साथ ले जाना आसान है। वह निजी या सार्वजनिक परिवहन के साधन में एडजस्ट हो सकता है। किसी भी बल को खरीद से पहले सूटकेस का परीक्षण, टेस्टिंग लैब या फैक्ट्री परिसर में कराना होगा।

सूटकेस में थ्री प्वाइंट लॉकिंग सिस्टम व एंटी थैफ्ट सिक्झोर ज़िपर रहेगा। पॉलीप्रोपाइलीन हार्ड टॉप बॉडी से बने सूटकेस से लंबी दूरी के सफर में दिक्कतें पेश नहीं आती हैं। यह रफ हैंडलिंग वाला सूटकेस है। सफर में इस पर स्केच आदि लगने का भी डर नहीं है। इसमें पहिये लगे होंगे। सूटकेस को 22 किलो तक के सामान के साथ पुल हैंडल ट्यूब व सरफेस हार्डनेस टेस्ट आदि से गुजरना पड़ेगा। सूटकेस के पहियों का परीक्षण करने के लिए एक ही दिशा में उसे 16 किलोमीटर चलाने का टेस्ट होगा।

इनके अलावा हैंडल जर्क टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट और टंबर टेस्ट भी कराया जाएगा। ये देखना होगा कि टंबर टेस्ट के दौरान सूटकेस का न तो रंग खराब हुआ हो और न ही क्रेक आया हो। पुल हैंडल टेस्ट में मल्टी पुश पुल हैंडल साइकिल टेस्ट, हैंगिंग पुल हैंडल जर्क और स्टैंडिंग पुल हैंडल जर्क टेस्ट किया जाएगा। सूटकेस को 240 घंटे के आर्द्रता कक्ष हार्डवेयर टेस्ट से गुजरा जाएगा। लॉक ओपन एवं क्लॉज टेस्ट भी होगा। साथ ही ओवन टेस्ट भी रहेगा। इसमें 120 घंटे तक 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूटकेस को रखा जाएगा।

चुनावी बॉन्ड योजना...

लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। पिछले छह वर्षों में इस योजना से 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा धन सभी पार्टियों को मिला है। नोटबंदी के बाद तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2017 के वित्त विधेयक के माध्यम से इस योजना को पेश किया था। उसके लिए रिजर्व बैंक, आयकर, कंपनी, जनप्रतिनिधित्व और विदेशी चंदों से जुड़े कई कानूनों में बदलाव भी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद इस योजना के साथ सारे कानूनी बदलाव भी निरस्त हो गए हैं।

चुनावी बॉन्ड लागू होने से पहले पार्टियों को लगभग 81 फीसदी रकम अज्ञात स्रोतों से मिलती थी। जेटली ने दलील दी थी कि चुनावी बॉन्डों से पार्टियों की फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आने के साथ काले धन पर अंकुश लगेगा। पुरानी कानूनी व्यवस्था के अनुसार, कंपनियां सालाना मुनाफे की अधिकतम सीमा के अनुसार ही दान दे सकती थीं। लेकिन कानून में बदलाव के बाद घाटे वाली कंपनियां भी बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को चंदा देने की हकदार हो गईं। मतदाताओं और पार्टियों को चुनावी बॉन्ड देने वाले की जानकारी नहीं मिल सकती थी। लेकिन सरकार को स्टेट बैंक के माध्यम से ये सारी जानकारियां हासिल थीं। कहा जा रहा था कि निजी कंपनियां और कॉर्पोरेट्स चुनावी बॉन्ड में पैसा लगाकर सरकारों से अपने हित में अनुचित काम कराते हैं।

ऐसे अनेक कानूनी और सांविधानिक बिंदुओं पर इस योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन लोकतंत्र से जुड़े इस बड़े मामले की सुनवाई और फैसला आने में सात साल लग गए। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने इस योजना का अनेक तरीके से बचाव करने की कोशिश की। सरकारी दलीलों के अनुसार, वोटों को ऐसे चंदे के बारे में जानने का कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे बॉन्ड और विदेशों से मिल रहे चंदे पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। रिजर्व बैंक ने भी इन बॉन्डों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग होने की आशंका जाहिर की थी। केंद्र और राज्य सरकारों को चुनावी बॉन्ड में विशेष बंधन मिलती है, इसलिए इस योजना को जजों ने समानता के विरुद्ध माना है।

भारत में लॉबिंग गैर-कानूनी है, लेकिन चुनावी बॉन्डों के माध्यम से निजी कंपनियां सरकारों से अनुचित लाभ ले रही हैं। इस बात को सरकार ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार किया। सरकारी वकील के अनुसार, चुनावी चंदे का खुलासा होने से चंदा देने वाली कंपनियों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है। जो लोग चुनावी बॉन्ड से सिर्फ भाजपा को फायदा होने की बात कर रहे हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ एक राज्य में सरकार चलाने वाली टीएमसी को लगभग दस फीसदी फंडिंग मिली है। इसलिए अगले महीने चुनावी बॉन्ड का हिसाब-किताब सार्वजनिक होने पर लोकसभा चुनावों के पहले बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है। इस योजना के रद्द होने के बाद पुराने तरीकों से पार्टियों



को फंडिंग जुटानी होगी। कानून के अनुसार, 20 हजार रुपये से कम की रकम गुमनाम तरीके से ली जा सकती है। पार्टियों को चेक के माध्यम से कंपनियों से चंदा मिल सके, इसके लिए आयकर विभाग ने वर्ष 2013 में ट्रस्ट की व्यवस्था बनाई थी।

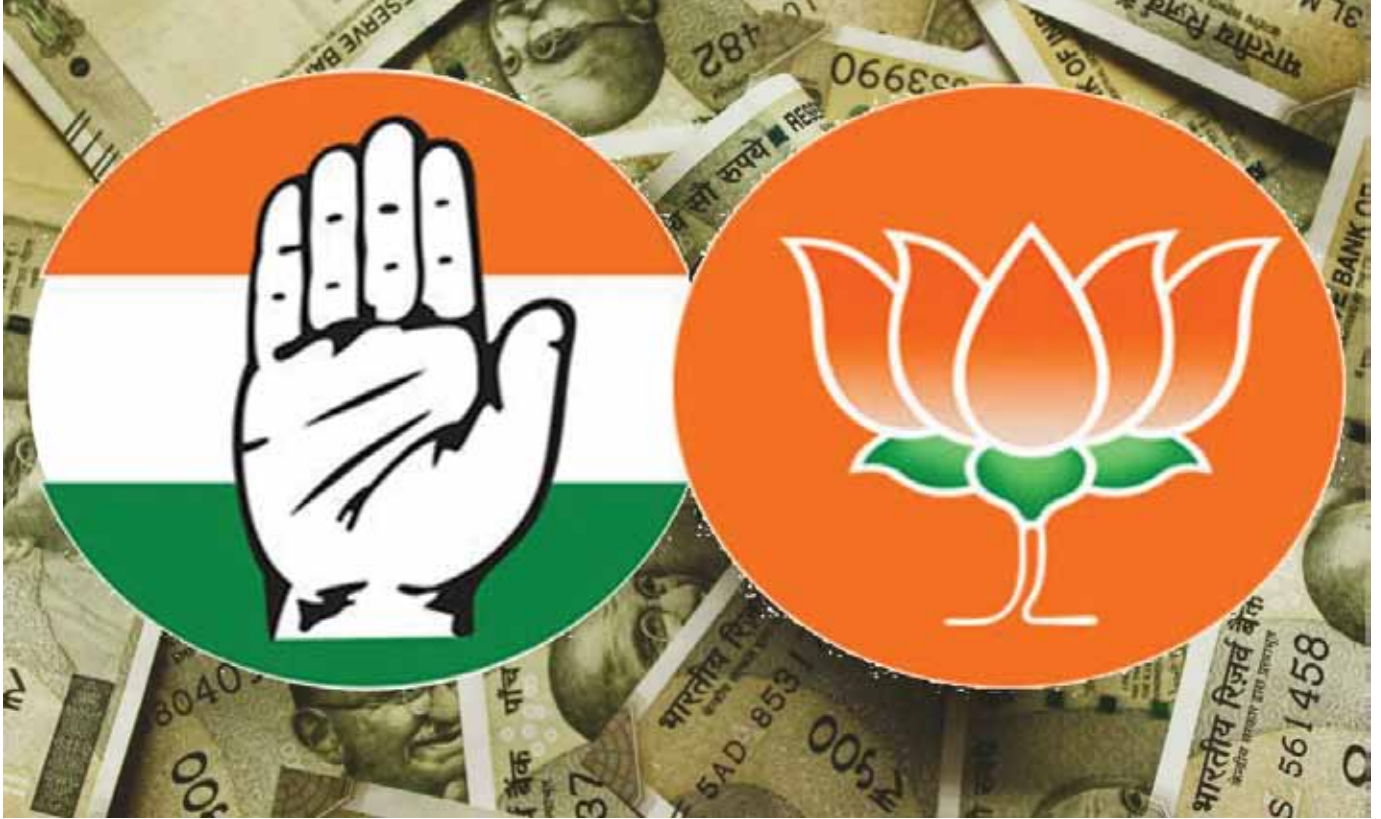
अनुमानों के अनुसार, पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। नियमों का उल्लंघन करके प्रत्याशी बड़े पैमाने पर काले धन का चुनावों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, सभी पार्टियों को कानूनी और गैर-कानूनी तरीके से चंदा मिलता है। पार्टियों के संगठित पैसे से कॉर्पोरेट ऑफिस, चार्टर्ड फ्लाइट, रोड शो, रैलियां और नेताओं की खरीद-फरोख्त भी होती है। 30 साल पहले बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में नेता, अपराधी और कॉर्पोरेट्स की मिलीभगत को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट माना गया था। वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में सरकार की तरफ से चुनावी खर्च देने की बात कही गई थी। विधि आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग ने चुनावी कानून दुरुस्त करने के लिए कई रिपोर्टें दी हैं। ऐसी सभी कमेटीयों में हुए विमर्श को धता बताकर नेता चुनावों में काले धन का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं।

चुनावों में टिकट पाने के लिए हाथ-तौबा मचाने और सरकार बनाने में रिसोर्ट पॉलिटिक्स से साफ है

कि राजनीति सबसे बड़ा व्यापार है, जहां सफल होने के लिए आपराधिक तरीके से काले धन का निवेश होता है। सीबीआई और ईडी के छापों से साफ है कि नेताओं के संरक्षण में खनन, शिक्षा, रियल एस्टेट और नौकरी में माफिया सक्रिय और प्रभावी हैं। दिवालिया कानून की आड़ में अनेक कंपनियां सरकारी बैंकों का पैसा हजम कर रही हैं। ऐसी कंपनियों को चुनावी बॉन्ड की आड़ में फंडिंग की इजाजत देना देश के खजाने की लूट ही मानी जाएगी। विपक्ष में रहकर सभी पार्टियां चुनावी व्यवस्था को ठीक करने की बात करती हैं, लेकिन काले धन के बाहुल्य से सरकार बनाने की होड़ में शुचिता के संकल्प तिरोहित हो जाते हैं।

नेताओं को चुनाव जीतने के बाद गाड़ी, बंगला और अनेक सुविधाएं मिलती हैं। पार्टियों के चंदे और आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता और उन्हें बेशकीमती सरकारी जमीन पर ऑफिस बनाने की सहूलियत मिलती है। चुनाव आयोग और आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कई रजिस्टर्ड पार्टियां मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में लिप्त हैं। संविधान में जनता के शासन को मान्यता मिली है, लेकिन इस सांविधानिक व्यवस्था को पार्टियों ने अपहृत कर लिया है। चुनावों में काले धन के कैसर को खत्म करके ही राजनीति में अपराध और सरकारों में भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है।

देशभर में किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड से कितना पैसा मिला...



देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनाववाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना की और कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनाववाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना की और कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है।

अदालत के फैसले से यह भी सामने आया है कि योजना की शुरुआत के बाद किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। इसमें केंद्र की सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। हम आपको विशेष रिपोर्ट में बता रहे हैं कि देशभर की तमाम पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से कितना पैसा मिला है? इन दलों की सियासी ताकत कितनी है?

भाजपा की स्थिति क्या है?

2017-18 से 2022-23 के बीच वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि भाजपा को सबसे अधिक दान मिला है। यह राशि 6566.125 करोड़ है जो सभी पार्टियों को मिले कुल दान का 54.7786% हिस्सा है। भाजपा की

सियासी ताकत देखें तो 18 राज्यों में अकेले या सहयोगियों के साथ सत्ता में है। ये राज्य हैं राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार।

अन्य दलों की क्या स्थिति है?

भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी दलों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसी भी चुनावी बॉन्ड के योगदान की जानकारी नहीं दी है। इस मामले में तीसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है। पार्टी को बीते पांच वर्षों में 1092.9876 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के रूप में मिले हैं। सभी दलों में इसकी हिस्सेदारी 9.1184% है। टीएमसी केवल पश्चिम बंगाल में भी शासन कर रही है। चुनावी बॉन्ड में हिस्सेदारी के हिसाब से चौथा स्थान भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का है। बीआरएस को गत पांच वर्षों में 912.6899 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं और सभी दलों का यह 7.6142% हिस्सा है। इसने 2020-21 में चुनावी बॉन्ड के योगदान की जानकारी नहीं दी है। बीआरएस अभी किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है। पिछले साल तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस को सत्ता से बेदखल करते हुए कांग्रेस सरकार में आ गई। इस सूची में पांचवां स्थान बीजू जनता दल (बीजद) का है। पिछले पांच वर्षों में बीजद को 774.00 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड से मिले हैं और कुल हिस्सेदारी 6.4572% है। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ओडिशा में सरकार चला रही है।

क्षेत्रीय दलों का क्या हाल है?

छठे पायदान पर मौजूद डीएमके को 616.50 करोड़ चुनावी बॉन्ड से मिले हैं। पार्टी की कुल भागीदारी 5.1432% की है। डीएमके फिलहाल तमिलनाडु में सत्ता में है। वायएसआर कांग्रेस को बीते पांच वर्षों में 382.44 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड से मिले हैं। सभी पार्टियों के हिसाब से इसकी भागीदारी 3.1905% है। जगन मोहन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सत्ता में है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने चुनावी बॉन्ड से 146.60 करोड़ का योगदान हासिल किया है। दलों के हिसाब से यह 1.2230% हिस्सा है। टीडीपी अभी किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है।

वहीं महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियों शिवसेना को 101.38 करोड़ रुपये (0.8458%) तो एनसीपी को 63.75 करोड़ रुपये (0.5318%) चुनावी बॉन्ड से मिले हैं। ये योगदान वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में मिला है।

आम आदमी पार्टी को 94.28521 करोड़ चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुए हैं। सभी दलों में इसका हिस्सा 0.7866% है। आप अभी दिल्ली और पंजाब में सरकार में है। इसके अलावा कर्नाटक की पार्टी जनता दल सेक्युलर को 48.7836 करोड़ रुपये (0.4070%), बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू को 24.40 करोड़ रुपये 0.2036% और समाजवादी पार्टी को 14.05 करोड़ रुपये (0.1172%) चुनावी बॉन्ड से मिले हैं।

सधी हुई ऊर्जा कूटनीति...

LNG आयात समझौता शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार...



बढ़ते पर्यावरणीय संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। अनुमान है कि देश में प्राथमिक ऊर्जा मांग 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। भारत की मौजूदा आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत से अधिक है। आर्थिक तरक्की को गति देने और समावेशी विकास के लिए ऊर्जा की नई साझेदारियां विकसित करनी होंगी। इस दिशा में भारत ने कतर के साथ 20 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात का समझौता किया है। 78 अरब डॉलर का यह समझौता ऊर्जा आपूर्ति के लिए निर्णायक हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयातक कंपनी पेट्रोनेट लि. हर साल 75 लाख टन गैस खरीदेगी।

प्राकृतिक गैस की मदद से देश में बिजली, उर्वरक और सीएनजी की उपलब्धता टिकाऊ होगी। देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 35 हजार किलोमीटर लंबी 'वन नेशन-वन गैस ग्रिड' स्थापित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक पीएनजी और एलएनजी की उपलब्धता आसान बनाना है। हमारी ऊर्जा जरूरतों में अभी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी छह प्रतिशत है। इस दशक के अंत तक इसे 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक गैस शून्य कार्बन उत्सर्जन से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक होगी।

इस समझौते से वर्तमान भाव पर भारत को 0.8 डॉलर

प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बचत होगी, जिससे 2048 तक देश को छह अरब डॉलर का लाभ होगा। साथ ही, भारत के एलएनजी आयात में कतर की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत हो जाएगी। प्राकृतिक गैस आयात को लेकर इससे पहले दोनों देशों के बीच 1999 में समझौता हुआ था, जो 2028 में समाप्त होगा। अमेरिका के बाद कतर एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी अपनी क्षमता को 2027 तक बढ़ाकर 12.6 टन सालाना करेगी।

भारत और कतर गैस समझौता देश की सधी हुई ऊर्जा कूटनीति का परिणाम है। अभी हम अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करते हैं। प्राकृतिक गैस के मामले में यह अनुपात लगभग 56 प्रतिशत है। तेल और गैस के लिए खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता अधिक रही है। इससे हमें ओपेक की मनमानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए पिछले वर्ष भारत ने सबसे अधिक कच्चे तेल की खरीदारी रूस से की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्ष देश ने रूस से प्रतिदिन 16.6 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीदारी की है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत परिशोधित (रिफाईंड) पेट्रोलियम उत्पादों का न सिर्फ बड़ा केंद्र बना, बल्कि यूरोप को सस्ती दर पर परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी किया। इससे ऊर्जा क्षेत्र के बड़े बाजार में भारत की मौजूदगी बढ़ने से ओपेक की मनमानी घटेगी।

पिछले दिनों गोवा में आयोजित ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत की ऊर्जा विविधिकरण को दुनिया ने देखा। इस दौरान भारत-कतर गैस समझौते के साथ ही भारतीय कंपनियों ने कई नवाचार पेश किए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी अल्कलाइन (क्षारीय) इलेक्ट्रोलाइजर पेश किया, जो दुनिया में सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर है। भाभा परमाणु शोध संस्थान के सहयोग से इसका प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लिया गया है। इस प्रौद्योगिकी से औद्योगिक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है। भारत ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

ऊर्जा सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ओएनजीसी द्वारा तैयार समुद्री सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। समुद्र में तेल एवं गैस परियोजनाएं सबसे जटिल अवसरचना होती हैं। तेल और गैस उत्खनन तथा परिशोधन के दौरान जोखिम अधिक होता है। यहां मानव निर्मित हादसों के अलावा मौसमी बदलाव का खतरा बना रहता है। ऐसे में मानव जनित तथा प्राकृतिक हादसों का प्रभाव कम करने के लिए ओएनजीसी ने समुद्री सर्वाइवल सेंटर स्थापित किया है। इससे तेल एवं गैस के उत्खनन में लगे मानव संसाधन को समुद्र में उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह सर्वाइवल सेंटर हर साल 15 हजार लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। इससे भारत की दक्षिण एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी भी मजबूत होगी।

भारत बंद का कोई असर नहीं, दुकानें-संस्थान खुले, जाम में रेंगती रही दिल्ली



मार्च के पहले हफ्ते में अयोध्या जाएगी मोहन कैबिनेट!

विधायकों की इस मांग से बढ़ी सीएम यादव की टेंशन



किसानों के प्रभाव क्षेत्र वाले पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भारत बंद का सीमित असर देखा गया है। कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं, तो व्यावसायिक-सरकारी संस्थान भी बंद रहे। चूंकि, किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी पंजाब के किसानों की ही है, इसलिए उनके प्रभाव क्षेत्र वाले क्षेत्रों में बंद का मिलाजुला असर हुआ है...

किसानों ने आज 16 फरवरी को भारत बंद का एलान कर रखा है, लेकिन पूरे देश में इसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। दिल्ली-एनसीआर में दुकानें और व्यापारिक-शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह खुले रहे और सामान्य कामकाज हुआ। देश के सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान में भी कहीं बंद का असर दिखाई नहीं पड़ा। इसका बड़ा कारण किसानों के बड़े संगठनों और नेताओं का आंदोलन से दूर रहना हो सकता है। आम आदमी का किसानों के इस आंदोलन के प्रति कोई सहानुभूति न होना भी भारत बंद को असफल बनाने में अहम रहा। पूरे देश में सबसे बड़े व्यापारियों के संगठन कैट ने एक दिन पहले ही इस आंदोलन में शामिल न होने की घोषणा कर दी थी। आंदोलन को बेअसर करने में इस घोषणा को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके एक दिन पहले किसानों के रेल रोकने आंदोलन को भी कोई सफलता नहीं मिली थी।

पंजाब में कुछ असर

किसानों के प्रभाव क्षेत्र वाले पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भारत बंद का सीमित असर देखा गया है। कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं, तो व्यावसायिक-सरकारी संस्थान भी बंद रहे। चूंकि, किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी पंजाब के किसानों की ही है, इसलिए उनके प्रभाव क्षेत्र वाले क्षेत्रों में बंद का मिलाजुला असर हुआ है। **किसान विरोधी रैली भी निकली** : जहां किसान अपने साथ पूरे देश के किसानों-मजदूरों के होने का दावा कर

रहे हैं, वहीं हरियाणा के कुछ इलाकों में किसान आंदोलन विरोधी रैली भी निकली। रैली में शामिल युवाओं का कहना था कि केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ किसान नेता बार-बार आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे किसानों के साथ-साथ आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कई लाख युवाओं के शामिल होने की संभावना है। इन युवाओं का भी कहना है कि आंदोलन और भारत बंद से उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। किसानों को बार-बार आंदोलन करने की बजाय सरकार से बातचीत और चुनाव में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनानी चाहिए। युवाओं का कहना था कि बंद के कारण यदि वे अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से वंचित रह गए तो उनका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा।

जाम से जूझती रही दिल्ली

भारत बंद भले ही असफल हो गया हो, लेकिन किसान आंदोलन के कारण दिल्ली-एनसीआर एरिया में लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह भी गाजीपुर यूपी गेट बॉर्डर पर वाहनों का कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हुई। इसी तरह नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों कालिंदीकुज बॉर्डर, बदरपुर और वजीराबाद में भी भारी जाम देखा गया।

अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में हर दिन भक्तों की लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं। हर दिन कोई न कोई वीवीआईपी या फिल्म स्टार श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। जल्द ही अब मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के बाद साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं। मोहन सरकार मार्च के पहले सप्ताह में अयोध्या जाएगी।

जानकारी के अनुसार, सीएम मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ चार मार्च को रामलला के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सीएम सभी मंत्रियों के साथ एक साथ अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने वीआईपी लोगों के आने से पहले जानकारी देने के लिए कहा था। जहां जानकारी मिलने के बाद उनका शेड्यूल तय किया गया है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार के लिए चार मार्च की तारीख तय की गई है।

खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच विधायकों की डिमांड ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। विधायकों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी सरकार अयोध्या रामलला के दर्शन कराने ले जाये, ऐसे में जल्द ही इस योजना पर पूरा विचार बनाया जा सकता है। अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा के समय सीएम मोहन ने मंदिर जाकर दर्शन करने की बात कही थी।

अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ आ रही है, ऐसे में मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय भी बढ़ाया है। अब सुबह से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन भक्तों को कराए जा रहे हैं। पहले यह समय 7 बजे तक ही था, लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया है।

नकुलनाथ बोले... सरकार नहीं होने के बाद भी होंगे सभी काम

कमलनाथ ने कहा कि एक समय ऐसा भी था कि अमरवाड़ा और हरई क्षेत्र का दौरा कर जब मैं छिंदवाड़ा लौटता था, तो कपड़े मिट्टी से सन जाते थे, पक्की सड़कें नहीं थीं। कोई आवेदन लिखने वाला नहीं मिलता था। भोपाल और नागपुर के लोग छिंदवाड़ा को जानते तक नहीं थे, कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा?

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ की भाजपा में जाने की अटकलें चल रही हैं। हालांकि कई बार कमलनाथ इन खबरों को खारिज कर चुके हैं। बीते रोज ही कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कमलनाथ ने अपने पुराने दिन याद किए। उन्होंने अपने दिल की बात कार्यकर्ताओं के साथ साझा की।

कमलनाथ ने कहा कि एक समय ऐसा भी था कि अमरवाड़ा और हरई क्षेत्र का दौरा कर जब मैं छिंदवाड़ा लौटता था, तो कपड़े मिट्टी से सन जाते थे, पक्की सड़कें नहीं थीं। कोई आवेदन लिखने वाला नहीं मिलता था। भोपाल और नागपुर के लोग छिंदवाड़ा को जानते तक नहीं थे, कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा? पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा कि आज हमारा छिंदवाड़ा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आप कहीं भी चले जाएं। सिर उठाकर कह सकते हैं कि हम छिंदवाड़ा से हैं। आज छिंदवाड़ा की एक अलग पहचान है और यह पहचान भी आप सभी के सहयोग, प्यार और सोच से बनी है, जिसका श्रेय भी मैं आप लोगों को ही देना चाहता हूँ। सांसद नकुलनाथ ने आयोजित



विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि हमारा 42 वर्ष पुराना पारिवारिक संबंध है, इसे नई पीढ़ी को बताना होगा। अब यह संबंध दो पीढ़ियों से जुड़कर और मजबूत हो चुका है। छिंदवाड़ा जिले में हाईवे, रिंग रोड, ग्रामीण सड़कें, सुचारू पेयजल के इंतजाम और बड़े जलाशय व तालाबों का निर्माण कमलनाथ जी ने अपने केंद्रीय मंत्रित्व कार्यकाल में पूर्ण कराये हैं।

मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिले के चहुंमुखी विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। कमलनाथ

जी के मार्गदर्शन में हम मिलकर जिले के विकास को पूरी गति से आगे बढ़ायेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि वे यह कतई न सोचें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो काम नहीं होंगे। पूर्व की भांति ही सभी कार्य होंगे। आगामी कुछ ही माह में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे, आप सभी को अभी से जुटना है और इसके लिये पहले से ही कार्ययोजना तैयार करें, ताकि चुनाव के दौरान कार्य करने में आसानी हो।

महिलाओं को आगे बढ़ाकर और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने से ही देश बनेगा महान-ओम बिरला



लो कसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सामाजिक कुरीतियां देश को आगे बढ़ाने में बाधा का काम करती हैं। महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में बढ़ावा देकर और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर ही देश को विकास की गति पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियां किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती होती हैं, जिससे पार पाने के लिए समाज के संतों की भूमिका प्रमुख होती है।

ओम बिरला बंजारा समाज के आराध्य संत सेवालाल जी महाराज की 285 वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत सेवालाल ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कुरीतियों को समाप्त करने और मानव कल्याण की दिशा में काम किया। उनके कार्य सदैव प्रेरणा के समृद्ध स्रोत रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बंजारा समुदाय अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में सदैव अग्रणी रहा है। इस आधुनिक समय में भी इस समुदाय ने अपनी मान्यताओं और परंपराओं को सहेज कर रखा है। इसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कई राज्यों में इस समुदाय को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ संत सेवालाल महाराज की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने और दीप प्रज्वलन से हुआ। डॉ. उमेश जाधव ने स्वागत नोट दिया और लोकसभा स्पीकर से दिल्ली में बंजारा भवन की निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की मंजूरी में सहायता देने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पीकर से गोरबोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का भी अनुरोध किया।

2.5 करोड़ रुपए देकर यूएई की जेल में बंद 900 भारतीयों को छुड़वाया, दुनिया में हो रही तारीफ

कौन हैं अरबपति मर्चेट?

प्योर गोल्ड ज्वैलर्स के 66 वर्षीय मालिक फिरोज मर्चेट ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों को 1 मिलियन दिरहम का दान दिया। वह दुबई में स्थित है। फिरोज मर्चेट के कार्यालय ने कहा, यह रमजान से पहले विनम्रता, मानवता, क्षमा और दयालुता का संदेश है।

भारतीय व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति ने 2024 की शुरुआत से खाड़ी देश की जेलों से 900 कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 1 मिलियन दिरहम (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) का दान दिया। उनका लक्ष्य इस वर्ष 3,000 कैदियों को रिहा कराना है। प्योर गोल्ड ज्वैलर्स के 66 वर्षीय मालिक फिरोज मर्चेट ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों को 1 मिलियन दिरहम का दान दिया। वह दुबई में स्थित है। फिरोज मर्चेट के कार्यालय ने कहा, यह रमजान से पहले विनम्रता, मानवता, क्षमा और दयालुता का संदेश है।

उनके कार्यालय के बयान में कहा गया है कि दुबई स्थित प्रमुख भारतीय व्यवसायी और प्योर गोल्ड के परोपकारी फिरोज मर्चेट ने अरब देश की जेलों से 900 कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए करीब 2.25 करोड़ (एईडी 1 मिलियन) का दान दिया है। मर्चेट अपनी 'द फॉरगॉटन सोसाइटी' पहल के लिए जाने जाते हैं, 2024 की शुरुआत से पहले ही 900 कैदियों की रिहाई की सुविधा प्रदान कर चुके हैं। मागलफ न्यूज पोर्टल के



अनुसार, इसमें अजमान के 495 कैदी, फुजैरा के 170 कैदी, दुबई के 121 कैदी, उम्म अल क्वैन के 69 कैदी और रास अल खैमा के 28 कैदी शामिल हैं। खाड़ी में रहने वाले तेलुगु समुदाय के लिए एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल, मैगलफ के अनुसार, मर्चेट ने उनके कर्ज का

भुगतान भी किया और उन्हें घर लौटने के लिए हवाई किराया भी प्रदान किया, जिसका लक्ष्य परिवारों को फिर से एकजुट करना और जीवन में दूसरा मौका देना था। 2024 के लिए उनका लक्ष्य 3,000 से अधिक कैदियों को मुक्त कराने में मदद करना है।

मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं...

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी की वरिष्ठ नेता और तीन बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सोमवार को पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। पीएमएल-एन के 50 वर्षीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) के सांसदों के बहिर्गमन के बीच मुख्यमंत्री पद का चुनाव जीता। मरियम नवाज ने 120 मिलियन लोगों के घर, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत के लिए मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के लिए पीटीआई समर्थित एसआईसी के राणा आफताब को हराया।

पंजाब विधानसभा में जाने से पहले उन्होंने जाति उमरा में अपनी मां की कब्र पर भी दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ था। एक्स पर एक पोस्ट में पीएमएल-एन ने कहा कि मरियम ने अपने नाना-नानी की कब्रों का भी दौरा किया। हमारे देश के इतिहास में पहली बार, एक महिला पंजाब की सीएम बनेगी। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की सीएम पद की शपथ लेने वाली पहली महिला होंगी! पीएमएल-एन ने चुनाव से पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा था।



राहुल गांधी के नशे वाले बयान पर मोदी का पलटवार...

'जिनके अपने होश ठिकाने नहीं, वो मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं'



नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अपने परिवार और वोटबैंक से बाहर देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम 'निल बटे सत्राटा' आता है तो ये एक-दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुवार को कहा कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 'नशेड़ी' शब्द सुना तो वह हैरान रह गए। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार के राजकुमार कहते हैं कि यूपी के युवा 'नशेड़ी' हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'उन्होंने मोदी को गाली देने में दशकों बिताए। लेकिन अब वे अपनी हताशा लोगों पर प्रकट कर रहे हैं।' राहुल पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो यूपी के, मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी को गाली देते-देते तो इन्होंने 2 दशक बिता दिए और अब ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी हताशा निकाल रहे हैं। अरे घोर परिवारवादियों... काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी-कैसी बातें करते हैं। मैं ये नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्रीराम से इतनी नफरत है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अपने परिवार और वोटबैंक से बाहर देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम 'निल बटे सत्राटा' आता है तो ये एक-दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है- हर लाभार्थी को शत-प्रतिशत लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी शत-प्रतिशत सीटें NDA के नाम करने वाला है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करते समय मोदी ने कहा कि यहां आने से पहले मैं बनास डेयरी प्लांट में गया था। वहां मेरी अनेक पशुपालक बहनों से बातचीत भी हुई है। किसान परिवारों की इन बहनों को 2-3 साल पहले हमने स्वदेशी नस्ल की गीर गाय दी थीं।

शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

2025-26 से साल में दो बार बोर्ड की परीक्षा दे सकेंगे 10वीं और 12वीं के छात्र



पिछले साल अगस्त में शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए पाठ्यक्रम (एनसीएफ) के अनुसार, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड परीक्षा साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बरकरार रखने का विकल्प भी मिलेगा।

बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अगले साल से दो बार परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस जानकारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक तनाव को कम करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनईपी 2020 में छात्रों को अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की परिकल्पना की गई है। पिछले साल अगस्त में शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए पाठ्यक्रम (एनसीएफ) के अनुसार, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड परीक्षा साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बरकरार रखने का विकल्प भी मिलेगा। रायपुर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने नए परीक्षा प्रारूप के प्रति छात्रों के स्वागत का आकलन करने के लिए छात्रों से बातचीत की। उन्होंने उनसे दोनों परीक्षाओं में अपनी उच्चतम



क्षमता का लक्ष्य रखने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि एनईपी के माध्यम से प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण छात्रों को तनाव मुक्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही उन्हें संस्कृति से जोड़े रखना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

मंत्री के अनुसार, इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन से भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनने में मदद मिलेगी, और उनका मानना है कि ऐसा करने के लिए एक सूत्र है। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री (प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधान ने कहा कि योजना के पहले चरण में राज्य के 211 स्कूलों को बजट के साथ 'हब एंड स्पोक' मॉडल का उपयोग करके अपग्रेड किया जाएगा।

कंपनी को भ्रामक विज्ञापन जारी करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने थमाया पतंजलि को अवमानना का नोटिस...

शीर्ष अदालत ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह कोई भ्रामक विज्ञापन जारी न करे या एलोपैथी के प्रतिकूल बयान न दे। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों को अगले आदेश तक नियमों के अनुसार बीमारियों/बीमारियों के इलाज के रूप में निर्दिष्ट उनके विपणन किए गए औषधीय उत्पादों के विज्ञापन और ब्रांडिंग से रोका जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को अपने औषधीय उत्पादों का विज्ञापन करने से रोक दिया और नवंबर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। हम रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करते हैं। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। एलडी वकील उनकी ओर से नोटिस स्वीकार कर 2 सप्ताह के भीतर उत्तर दें।

शीर्ष अदालत ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह कोई भ्रामक विज्ञापन जारी न करे या एलोपैथी के प्रतिकूल बयान न दे। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों को अगले आदेश तक नियमों के अनुसार बीमारियों/बीमारियों के इलाज के रूप में निर्दिष्ट उनके विपणन किए गए औषधीय उत्पादों के विज्ञापन और ब्रांडिंग से रोका जाता है। उन्हें प्रिंट या अन्य मीडिया में किसी भी रूप में किसी भी चिकित्सा प्रणाली के प्रतिकूल



कोई भी बयान देने से सावधान किया जाता है। यह याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सभी बीमारियों का इलाज करने का दावा करने वाले और एलोपैथिक दवाओं की प्रभावकारिता पर संदेह करके डॉक्टरों को बदनाम करने वाले सभी भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में रामदेव और पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की

भी मांग की गई है। बार एंड बेंच के अनुसार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा, "मैं प्रिंटआउट और अनुलग्नक लाया हूँ। हम आज बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से जाओ। आप कैसे कह सकते हैं कि आप ठीक कर देंगे? हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारी चीजें रसायन-आधारित दवाओं से बेहतर हैं?"

सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति के परिजनों को 1.35 करोड़ के मुआवजे के आदेश

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए



48 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा देना का आदेश दिया है। एमएसीटी के अध्यक्ष एसबी अग्रवाल ने

12 फरवरी को पारित आदेश में कहा कि दोषी बस का मालिक और उसकी बीमा कंपनी संयुक्त रूप से मुआवजे की राशि का भुगतान याचिका दायर करने की तारीख से

वसूली तक 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ करें। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी। ग्यारह नवंबर 2018 को महाराष्ट्र के सिन्नर-शिरडी रोड पर एक बस की पीड़ित के वाहन से टक्कर हो जाने से पीड़ित, ठाणे के मीरा रोड इलाके के निवासी एग्नेल इयुपुत्री चक्रमाकिल और कार में सवार चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता एग्नेल की 52 वर्षीय पत्नी और 31 साल के बेटे ने तर्क दिया कि बस चालक वाहन को लापरवाही से चला रहा था जिससे भीषण टक्कर हुई। उन्होंने एग्नेल की मौत के लिए 2.70 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। बस का मालिक न्यायाधिकरण के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए मामले में उसके खिलाफ एकपक्षीय फैसला

सुनाया गया। न्यायाधिकरण ने एग्नेल की एक लाख रुपये की मासिक आय और भविष्य की आय की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त रकम को ध्यान में रखते हुए दावे की गणना की। एमएसीटी ने मृतक की उम्र के आधार पर मुआवजे की गणना की जिससे मुआवजे का आंकड़ा 1,35,90,052 रुपये पर पहुंच गया, जिसमें आय, संपत्ति, सहायता संघ और अंतिम संस्कार का खर्च शामिल हैं। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि पीड़ित की पत्नी के लिए एक करोड़ रुपये और उसके बेटे के लिए पांच लाख रुपये सावधि जमा में रखे जाएं और शेष एवं अर्जित ब्याज का भुगतान महिला को खाते में भुगतान किये जाने वाले चेक के माध्यम से किया जाए।

किसान तो सिर्फ त

इस संगठित भीड़तंत्र के इरादे कुछ अ



वहीं किसान आन्दोलन में देखें तो लाखों रुपए के नए नए ट्रैक्टर, उनमें महंगे-महंगे साउंड सिस्टम, लगजरी सुविधाएं, वैनिटी बैन के रूप में ट्रैक्टर ट्राली को बनाकर रखना हैरानी पैदा करता है। कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के सुरक्षात्मक प्रबंध को तोड़ने के लिए 'पोकलेन मशीनें' लाई जा रही हैं।

ढाल हैं

और लगते हैं



कि सानों ने फिर से दिल्ली कूच करने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है। उनके प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार के मन्त्रियों की कई दौर की बैठकें भी विफल ही रही हैं। इस बीच यह किसान आन्दोलन निरंतर नए मोड़ और नए रंग ढंग में दिख रहा है। यदि किसानों की मांगों को देखा जाए तो किसानों एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कई विषय विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है- तकनीकी एवं प्रायोगिक रूप से ये अधिकांशतः मांगें ऐसी हैं जिन्हें पूरा करना सम्भव नहीं है। साथ ही ये देश की अर्थव्यवस्था एवं नीतियों पर विपरीत प्रभाव डालने वाली हैं। वर्तमान में यदि

केन्द्र सरकार द्वारा 22 फसलों पर दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की ही बात करें तो यह देश की जीडीपी का 2 प्रतिशत भाग है। जबकि देश के रक्षा बजट के लिए 1.7 प्रतिशत और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए जीडीपी से 2.1 प्रतिशत राशि आवंटित की जाती है। साथ ही एमएसपी का सर्वाधिक हिस्सा पंजाब के 43 लाख 33 हजार किसानों के खाते में ही जाते हैं। अतएव मुख्य मुद्दे सभी फसलों पर एमएसपी को लेकर केन्द्र सरकार क्या निर्णय लेती है, यह भविष्य में देखते ही बनेगा। किन्तु इन सबके बीच यह किसान आन्दोलन जिस ढंग से अशांति की ओर बढ़ता जा रहा है। उससे इसकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं।

वस्तुतः समूचा देश अपने किसानों के हित से जुड़े हुए मुद्दों में हमेशा साथ खड़ा रहता। यह आवश्यक भी है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों किसानों की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। ऐसी नीतियां एवं कार्य-प्रणालियां विकसित करें जिनसे किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। जहां किसानों से जुड़े हुए आन्दोलन यदि शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं तो उसमें एकजुटता दिखती है। वहीं इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने निकलकर आता है। किन्तु वर्तमान में पंजाब के सिख किसानों द्वारा किया जाने वाला आन्दोलन अपनी राह एवं उद्देश्य से पूरी तरह हटा हुआ दिख रहा है। इस किसान आन्दोलन में 'किसान' गौण होता हुआ और योजनाबद्ध राजनीति चरम पर देखने को मिल रही है।

वर्तमान में दिखने वाला यह पैटर्न हाल ही के वर्षों में 'भीड़तन्त्र' की दादागिरी के रूप में उभरा है। जो कहीं भी किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को धता बताने और उपद्रव को अपना अधिकार समझता है। आखिर ये कैसे आन्दोलन और प्रदर्शन हैं ? जो हिंसा, उत्पात मचाते हुए कानून व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होते हैं। एक संगठित भीड़ कहीं भी किसी भी सड़क व स्थान को घेर लेती है। यातायात को बुरी तरह बाधित कर आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया जाता है। क्या किसी भी आन्दोलन के नाम पर ऐसा किया जाना सही ठहराया जा सकता है ?

इस समय पंजाब के सिख किसानों ने आन्दोलन के नाम पर जिस ढंग का वातावरण उत्पन्न किया है। उससे उनकी गतिविधियां किसान हितैषी नहीं बल्कि संदिग्ध एवं राजनीति प्रेरित ही दिख रही हैं। वर्ष 2021 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से ट्रैक्टर मार्च के नाम पर उपद्रव किया गया। सशस्त्र हिंसा एवं उत्पात मचाते हुए दिल्ली को बंधक बना लिया गया था। लाल किले में धार्मिक प्रतीक के झंडे को फहराया गया और पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा की गई। यातायात को बुरी तरह बाधित किया गया। आम जनजीवन को बेपटरी करने का प्रयास किया गया। ठीक उसी प्रकार के दृश्य फिर से दिखाई देने लगे हैं। बल्कि उससे और अधिक खतरनाक मंसूबे वाले कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर से जिस ढंग के दृश्य और हालात सामने आ रहे हैं वह किसी को भी दहला कर रख देने वाले हैं। इस किसान आन्दोलन में खालिस्तानी आतंकी भिंडराले के फोटो और खालिस्तान के समर्थन वाले गाने बजते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान जिन्दाबाद लिखे हुए बड़े-बड़े गुब्बारे आसमान में उड़ाए जा रहे हैं।

हरियाणा बॉर्डर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। साथ ही अन्य सुरक्षात्मक उपाय बनाए हुए हैं। लेकिन आन्दोलन के नाम पर संगठित गिरोह के द्वारा कभी भी किसी भी समय पुलिस बल पर पथराव एवं सशस्त्र हमले किए जा रहे हैं। पुलिस बल के खिलाफ हिंसा करने के नारे एवं नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं टिवटर (एक्स) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खनौरी बार्डर के वे वीडियो भी सामने आए जिनमें किसान पुलिस पर लाठियां चलाते हुए दिख रहे थे। साथ ही पुलिस की ओर ऐसे पटाखों से हमला किया जा रहा था जोकि दूर जाकर फटते हैं। इन दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसान आन्दोलन नहीं बल्कि कानून व्यवस्था एवं सरकार के विरुद्ध युद्ध की

क्या आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए यह आन्दोलन चलाया जा रहा है? ऐसे कई सारे प्रश्न इस किसान आन्दोलन की संदिग्ध गतिविधियों के कारण उठ रहे हैं। इन सभी वाकियों से यही निष्कर्ष निकल रहा कि 'किसान' सिर्फ ढाल के रूप में हैं। इस संगठित भीड़तन्त्र के इरादे कुछ और हैं जिन्हें वह किसान आन्दोलन के नाम पर भुनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं।

घोषणा है।

इतना ही नहीं इस किसान आन्दोलन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ घृणा और हिंसा प्रेरित बयान भी दिए जा रहे हैं। मोदी को मारने की धमकियां देने वाले नारे और भाषण दिए जा रहे हैं। इसी आन्दोलन का एक बड़ा चेहरा माना जाने वाले सिद्धपुर के प्रधान जगजीत सिंह उल्लेवाल का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में उल्लेवाल यह कह रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसे नीचे लाना है। समय कम है। इसी तरह से एक अन्य किसान नेता इस आन्दोलन को विपक्ष की लड़ाई, ओपीएस, अग्निवीर आदि से जोड़कर बताता हुआ नजर आया। क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मारने की धमकी और उनके विरुद्ध हिंसात्मक- बयानबाजी किसान आन्दोलन का लक्ष्य है ? क्या मोदी की लोकप्रियता को कम करना और राजनीतिक उद्देश्य साधना ही इस किसान आन्दोलन की थीम है ? क्या ऐसे में इसे किसान आन्दोलन कहा जा सकता है ?

वहीं किसान आन्दोलन में देखें तो लाखों रुपए के नए नए ट्रैक्टर, उनमें महंगे-महंगे साउंड सिस्टम, लग्जरी सुविधाएं, वैनिटी बैन के रूप में ट्रैक्टर ट्राली को बनाकर रखना हेराना पैदा करता है। कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के सुरक्षात्मक प्रबंध को तोड़ने के लिए 'पोकलेन मशीनें' लाई जा रही हैं। ये पोकलेन मशीनें वही मशीनें हैं जिनका उपयोग पहाड़ों को तोड़ने, सुरंग आदि बनाने में किया जाता है। किसान आन्दोलन के नाम पर किए जा रहे ये सारे काम क्या किसी भी दृष्टि से जायज कहलाए जाएंगे ? यह विचारणीय विषय है कि किसान आन्दोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है क्या वह किसान हितैषी है ? क्या इनमें कहीं किसान दिख रहा है ? क्या इन सब बातों, दृश्यों और कृत्यों से राजनीति प्रेरित - 'संदिग्ध' दृश्य सामने नहीं आ रहे हैं ? प्रश्न तो ये भी हैं कि क्या किसान आन्दोलन के नाम अराजकता एवं उत्पात को उचित कहा जा सकता है ? जिस प्रकार से आन्दोलन के नाम पर एक संगठित भीड़तन्त्र- देश की कानून व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा है। हिंसात्मक गतिविधियों की जा रही है उसे देशविरोधी न कहा जाए ? क्या हमारे संविधान ने आन्दोलन के नाम पर उपद्रव, हिंसा एवं आमजनजीवन को बाधित करने की छूट दे रखी है ?

इसके साथ ही जिस ढंग से इस आन्दोलन में भारत-विरोधी संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में क्या इस आन्दोलन में विदेशी शक्तियां भी लगी हुई हैं ? क्या जार्ज सोरोस गिरोह इस आन्दोलन में प्रवेश कर चुका है ? क्या भारत-विरोधी टूलकिट गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है ? जो भारत की कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए इस आन्दोलन को ढाल बना रहा है ?

केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता फिर बढ़ सकता है! प्रदेश में पिछला ही नहीं मिला



केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर बढ़ाने की तैयारी है। भारत सरकार इसकी घोषणा कभी भी कर सकती है। उधर, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि, केंद्र सरकार जुलाई से 46 की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। चार प्रतिशत की वृद्धि के लिए वित्त विभाग दो बार प्रस्ताव बनाकर भेज चुका है लेकिन सरकार के स्तर से अंतिम निर्णय अब तक नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया तो विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि की थी। विधानसभा चुनाव के समय वित्त विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति के माध्यम से चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था लेकिन इसे मतदान को देखते हुए अनुमति नहीं मिली थी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजा पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

14 हजार रुपये तक प्रतिमाह की क्षति हो रही है...

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि चार प्रतिशत की वृद्धि का लाभ न मिलने से कर्मचारियों और पेंशनरों को दो से लेकर 14 हजार रुपये तक प्रतिमाह का क्षति हो रही है। मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और फिर जून तक वृद्धि संभव नहीं होगी, इसलिए सरकार अभी इस पर निर्णय करें। यदि 15 दिन में सरकार इस मामले में निर्णय नहीं करती है कि सभी कर्मचारी संगठन मिलकर विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन करेंगे। उधर, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष आमोद सक्सेना के



नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह से भेंट कर चार प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नीति के अनुरूप एक जुलाई 2023 से महंगाई राहत में वृद्धि की जाए और एरियर भी दिया जाए। साथ ही 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने संबंधी उच्चतम न्यायालय ने आदेश का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाए।

बजट में 56% के हिसाब से भते के लिए रखी जाएगी राशि

उधर, वर्ष 2024-25 में महंगाई भत्ते व राहत के लिए 56 प्रतिशत के अनुसार बजट प्रावधान रखा जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को अपना स्थापना व्यय इसके अनुरूप ही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। अभी बजट में 46 प्रतिशत के अनुसार प्रावधान है।

गलत रिपोर्ट के कारण ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित मरीज हुई परेशान, 5 लाख देना होगा हर्जाना



ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक निजी स्कूल की शिक्षिका जब डायग्नोस्टिक की ओर से गलत रिपोर्ट के कारण उनके इलाज में देरी हुई। मरीज का ओवरी व यूटेरस निकाल दिया गया था, लेकिन जब मरीज ने पीड़ती सीटी स्कैन कराया तो रिपोर्ट में सामान्य बता दिया। जब दूसरी जगह सीटी स्कैन कराया गया तो पता चला कि गलत रिपोर्ट है।

दरअसल अयोध्या बायपास स्थित नीलम त्रिपाठी ने जिला उपभोक्ता आयोग में सानया डायग्नोस्टिक के प्रबंधक, एमडी सीनियर कंसल्टेंट डा.अरविंद कुमार जैन व डा. सिकंदर के खिलाफ 2022 में याचिका लगाई थी। इसमें शिकायत की है कि मरीज ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। उनका इलाज गेस्ट्रोकेयर भोपाल में चल रहा था। उन्हें पूरी बाडी का पीड़ती सीटी स्कैन कराने की सलाह दी गई। उनकी रेडियोथैरेपी व कीमोथैरेपी भी की गई। इलाज के समय यूटेरस व ओवरी आपरेशन से निकाल दिया गया था। जब उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए सानया डायग्नोस्टिक से सीटी स्कैन कराया तो रिपोर्ट में गलत जानकारी लिखी गई कि उनका यूटेरस व ओवरी सामान्य है। इस कारण उपभोक्ता की तबियत और खराब हो गई और इलाज में देरी हुई। अभी भी मरीज का इलाज चल रहा है। आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व सदस्य अरुण प्रताप सिंह ने फटकार लगाई कि गलत रिपोर्ट के कारण कैंसर जैसी गंभीर इलाज में विलंब हुआ। इससे मरीज को परेशान होना पड़ा। इसके लिए सानया डायग्नोस्टिक के प्रबंधक, एमडी व सीनियर कंसल्टेंट अरविंद कुमार जैन व लेक सिटी के सर्जन रवि गुप्ता दोषी पाए गए और उन्हें मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये देने होंगे। आयोग ने दो माह के अंदर मानसिक क्षतिपूर्ति राशि के साथ-साथ डायग्नोस्टिक में खर्च 18 हजार और वाद व्यय 25 हजार रुपये देने होंगे।

मरीज नीलम त्रिपाठी ने बताया कि वे चौथे स्टेज की कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं। पीड़ती सीटी स्कैन रिपोर्ट अन्य जांच से बिल्कुल भिन्न था। गलत रिपोर्ट लिखा था। इससे मुझे बार-बार रेडियोग्राफी व कीमोथैरेपी कराने से रेडिएशन कराना पड़ा, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है।

झारखंड की राजनीति में अचानक चर्चा में क्यों हैं कल्पना सोरेन...



1 976 में रांची में जन्मी कल्पना ओडिशा के मयूरभंज जिले में पली बड़ीं और उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उनके पिता एक व्यवसायी हैं और उनकी माँ एक गृहिणी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमबीए किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन शीर्ष पद संभाल सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय बुधवार दोपहर 1 बजे सीएम कार्यालय में सीएम सोरेन से पूछताछ करने वाला है। सोरेन ने लगातार दो बैठकें बुलाई, पहली बैठक में उनकी पत्नी कल्पना शामिल हुईं। इसके बाद, एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें 43 विधायकों ने भाग लिया, जिसमें सीता सोरेन, रामदास सोरेन, चमरा लिंगा और लोबिन हेम्रम सहित चार अनुपस्थित थे - सभी ज्ञानमुमो पार्टी से संबंधित थे।

जबकि सोरेन की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने इस अटकल का खंडन किया है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के इसी तरह के दावे के बाद इसे बल मिला है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्तमान सूचना के अनुसार विधायक सीता सोरेन जी व विधायक बसंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी या अन्य विधायक को मुख्यमंत्री मानने से इंकार कर दिया है। दोनों विधायक राँची में हो रही विधायक दल की बैठक से अनुपस्थित हैं।

कौन हैं कल्पना सोरेन?

1976 में रांची में जन्मी कल्पना ओडिशा के मयूरभंज जिले में पली बड़ीं और उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उनके पिता एक व्यवसायी हैं और उनकी माँ एक गृहिणी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमबीए किया। 7 फरवरी 2006 को, कल्पना ने हेमंत सोरेन के साथ शादी की और आज, जोड़े के दो बच्चे हैं - निखिल और अंश। कल्पना ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज किया है और वह एक उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बताया गया है कि वह एक स्कूल चलाती हैं और उन्हें जैविक खेती में काफी रुचि है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पास तीन व्यावसायिक इमारतें हैं, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है। उन्हें महिला एवं बाल सशक्तिकरण से जुड़े राज्य कार्यक्रमों में भी नियमित रूप से देखा जाता है। जब धन और संपत्ति की बात आती है, तो कल्पना सोरेन, 2019 में अपने पति द्वारा प्रस्तुत चुनावी हलफनामे के अनुसार, करोड़पति हैं। तब पता चला कि उसके विभिन्न बैंक खातों में 2,55,240 रुपये जमा थे। दंपति के पास 70 लाख रुपये की विभिन्न एलआईसी पॉलिसियां भी हैं। इसके अलावा, वे 34 लाख रुपये से अधिक के सोने और चांदी के आभूषणों की मालिक हैं। राजनीति से दूर रहने के बावजूद कल्पना कई मामलों पर हेमंत को सलाह देती रही हैं।

चीते की तर्ज पर मध्यप्रदेश में सियागोश को बसाने की तैयारी, रिसर्च जारी...



आ जादी के बाद देश में चीता के बाद विलुप्त होने वाला स्यागोस दूसरा खूबसूरत वन्य जीव है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए रिसर्च जारी है। बतादे की देश में विलुप्त हो रहा बिल्ली प्रजाति का दुर्लभ जीव एशियाटिक कैराकल (स्यागोस) बेहद ही खूबसूरत और फूर्तीला होता है। जिसे हिंदी में सियागोस कहते हैं और यह जंगल में कलाबाजी करते हुए उड़ते हुए पक्षियों का शिकार करने का माहिर होता है। सियागोस जीव झाड़ियों के बीच छिपकर शिकार करने में माहिर माना जाता है। सिर्फ जनवरी से फरवरी के बीच ही नर और मादा साथ रहते हैं। इसके बाद मादा ही बच्चों के बड़े होने तक उनके साथ रहती है। भारत के कच्छ के रण और रणथंभौर से कुनो तक के जंगलों में इनकी संख्या करीब सौ के आसपास ही बची होना बताई जा रही है।

सूत्रों से जानकारी मिली है कि विलुप्त होते स्यागोस को बसाने की तैयारियां इन दिनों मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जोरों पर की जा रही है जहां दिनों दिन विलुप्त होते जा रहे स्यागोस को चीता प्रोजेक्ट की तर्ज पर बसाने की प्लानिंग वन विभाग ने बनाई है अभी इसके लिए घाटी गांव का जंगल काफी उपयुक्त माना जा रहा है बताया जा रहा है कि घाटी गांव के जंगल में बाड़ा बनाने के लिए स्थानों का चयन भी किया जा रहा है जैसे ही स्यागोस को लेकर उत्तर प्रदेश या राजस्थान से मिलने की स्वीकृति मिलेगी स्यागोस को घाटीगांव में वन विभाग की एक्सपर्ट टीम के माध्यम से बाड़ों में छोड़ा जाएगा इसके बाद धीरे-धीरे इन का कुनबा बढ़ाया जाएगा।

इनका कहना है

■ सियागोश (कैराकल) के संरक्षण और मध्यप्रदेश के जंगलों में इसकी बसावट को लेकर अलग कुछ प्रपोजल नहीं है हमारा एक रिसर्च चल रहा है कैराकल पर, कुनो पर, इसका संरक्षण ऑल प्रोफेसलि एरिया से होता है कैराकल को लेकर अभी कोई कार्य योजना नहीं बनी है कैराकल अभी रिसर्च सेल में है।

-आर.थिरुकुरल, डीएफओ, कुनो नेशनल पार्क श्योपुर

पीएम मोदी बोले- परिवारवाद ने किया कांग्रेस का नुकसान

अब दुकान बंद होने की आई नौबत...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम 5 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा पहुंचे। वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे हैं। 31 जनवरी को बजट सत्र का पहला दिन था, जिसे राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। पीएम मोदी के संबोधन पर भाजपा के सभी सांसद लोकसभा में मौजूद हैं। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर इसकी सूचना पहले ही दे दी थी।



पी एम मोदी अपने संबोधन में सरकार के 10 साल के काम काज का ब्यौरा दे रहे हैं। वह देश के सामने बता रहे हैं कि बीते 10 साल में भारत के आम जनमानस की जिंदगी में सुधार लाने के लिए सरकार की तरफ कितने प्रयास किए गए। पीएम मोदी बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वह इस मौके का फायदा उठाकर चुनावी एजेंडा भी सेट कर रहे हैं। वह विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखाई देगा। भाजपा अकेले 370 सीटें जीतेगी। वहीं एनडीए 400 पार सीटें जीतेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं लंबे समय तक विपक्ष में रहने के विपक्ष के संकल्प की सराहना करता हूँ। जिस तरह आप यहां (सरकार में) कई दशकों तक बैठे रहे, उसी तरह आप वहां (विपक्ष में) बैठने का संकल्प करते हैं। जनता जरूर आपको आशीर्वाद देगी।

कांग्रेस ने विपक्ष का हाल किया बुरा- पीएम मोदी

कांग्रेस को अच्छा विपक्ष बनने का अच्छा अवसर मिला था। उन्हें 10 साल का अवसर मिला था, लेकिन वह इसमें भी फेल हो गए। विपक्ष में कई तेजस्वी लोग हैं, लेकिन वह उनको दबाती है। उसको डर है कि अगर वह अच्छा दिखेंगे, तो किसी और की छवि दब सकती है।

विपक्ष छोड़ चुका है चुनाव लड़ने की हिम्मत- पीएम

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपमें से कई लोग (विपक्ष) चुनाव लड़ने की हिम्मत भी खो चुके हैं। पिछली बार भी कुछ सीटें बदली थीं, मैंने सुना है कि कई लोग इस बार भी अपनी सीटें बदलने की सोच रहे हैं। यह भी सुना है कि कई लोग अब लोकसभा की बजाय राज्यसभा जाना चाहते हैं। वे स्थिति का आकलन कर अपनी राह तलाश रहे हैं।

कब तक समाज को बांटेंगे विपक्ष- पीएम मोदी

विपक्षी सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं होने का मुद्दा उठाया तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हो सकता है कि आपके यहां मछुआरे अल्पसंख्यक नहीं हों, हो सकता है कि आपके यहां पशुपालक अल्पसंख्यक नहीं हों, हो सकता है कि किसान अल्पसंख्यक हों। आपके यहां महिलाएं अल्पसंख्यक नहीं हैं। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है। कब तक विभाजन के बारे में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे?

पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला- पीएम मोदी : पीएम मोदी ने कांग्रेस राहुल गांधी पर हमला

बोला है। उन्होंने कहा कि एक ही प्रोडक्ट बार-बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगाने की नौबत आ गई है।

भारत होगा तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति- पीएम मोदी : पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि शासन के 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और भारत के आगे बढ़ने की तेज गति को देखते हुए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। यह मोदी की गारंटी है।

नेहरू भारतीयों को कम अक्ल मानते थे- मोदी

प्रधानमंत्री नेहरू 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि हिंदुस्तान में लोगों में ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। हम उतना काम नहीं करते हैं, जितना रूस, चीन, जापान, अमेरिका वाले करते हैं। यह न समझिए कि वह कौमो कोई जादू से खुशहाल हुई है। वह कौमो मेहनत से व अपने से काम कर खुशहाल हुई हैं। नेहरू की सोच थी कि भारतीय आलसी व कम अक्ल के होते हैं। इंदिरा गांधी भी नेहरू की ही तरह सोचती थीं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है, तो हम खुश हो जाते हैं। जब काम बिगड़ने को होता है, तो पूरा देश ही निराशा के भाव से भर जाता है।

हर साल खर्च होते हैं 200 करोड़..

इसलिए... स्वच्छता में नंबर वन रहता है इन्दौर शहर..



इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय लोगों से कचरा संग्रहण शुल्क और जुर्माने की वसूली के साथ ही अन्य स्रोतों से इतनी ही राशि सरकारी खजाने में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्वच्छता के इस मॉडल को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके।

इंदौर। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार सातवीं बार अव्वल रहे मध्यप्रदेश के इंदौर में शहरी निकाय की ओर से कचरा प्रबंधन पर हर साल करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। निगम के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय लोगों से कचरा संग्रहण शुल्क और जुर्माने की वसूली के साथ ही अन्य स्रोतों से इतनी ही राशि सरकारी खजाने में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्वच्छता के इस मॉडल को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके।

“वेस्ट टू वेल्थ” की थीम पर केंद्रित वर्ष 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में अलग-अलग श्रेणियों में देश के 4,400 से ज्यादा शहरों के बीच कड़ी टक्कर

थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में दिल्ली में बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यक्रम में इंदौर को सूरत के साथ देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। अधिकारी ने बताया, हम शहर में अपशिष्ट प्रबंधन पर हर साल करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हम कचरे से कमाई की अलग-अलग मदों में इतनी ही रकम सरकारी खजाने में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि बायो-सीएनजी संयंत्र “गोबर-धन” को गीला कचरा मुहैया कराने के बदले एक निजी कंपनी की ओर से आईएमसी को हर साल 2.52 करोड़ रुपये की रॉयल्टी दी जाती है।

इसके अलावा, निजी कम्पनी शहरी निकाय को प्रचलित बाजार दर से पांच रुपये प्रति किलोग्राम कम दाम पर यह हरित ईंधन बेचती है जिससे सरकारी खजाने को लाभ होता है। उन्होंने बताया कि शहर के एक अन्य प्रसंस्करण संयंत्र को सूखा कचरा मुहैया कराने के बदले आईएमसी को एक निजी कंपनी की ओर से हर साल 1.43 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिलती है। अधिकारी ने बताया कि गीले और सूखे कचरे के प्रसंस्करण के दोनों संयंत्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत चलाए

जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट बेचने से आईएमसी को नौ करोड़ रुपये की सालाना आय होती है। अधिकारी ने बताया कि आईएमसी ने एकल उपयोग वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक को जप्त करने के बाद इसके पुनर्चक्रण के जरिये विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) के क्रेडिट भी हासिल किए हैं।

बहरहाल, शहर के लगातार विस्तार के मद्देनजर आईएमसी के सामने स्थानीय लोगों से कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। आईएमसी अधिकारी का दावा है कि कचरा संग्रहण के बदले शहर के कुल 6.5 लाख घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक संस्थानों से नियमित शुल्क वसूला जा रहा है। इसके अलावा, गंदगी फैलाने पर संबंधित लोगों से जुर्माना भी वसूला जाता है। अधिकारी ने बताया कि शहर में औसत आधार पर हर दिन 692 टन गीला कचरा, 683 टन सूखा कचरा और 179 टन प्लास्टिक अपशिष्ट अलग-अलग श्रेणियों में इकट्ठा किया जाता है। कचरा संग्रहण के लिए शहर भर में करीब 850 गाड़ियां चलती हैं।

**नितिन गडकरी बोले-
अच्छा काम करने वाले को
कभी सम्मान नहीं मिलता,
चर्चा का विषय बना**



मो दी सरकार में सड़क तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, 'मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है, उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है, उसे कभी सजा नहीं मिलती।'

साथ ही नितिन गडकरी ने अवसरवादी राजनेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह की विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। देश में आज भी ऐसे नेता हैं, जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है।

विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं में मतभेद समस्या नहीं है। हमारी समस्या विचारों की कमी है। न तो दक्षिणपंथी और न ही वामपंथी, हम जाने-माने अवसरवादी हैं। कुछ लोग यह फॉर्मूला अपनाते हैं। और सत्तारूढ़ दल से जुड़े रहना चाहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, भारत लोकतंत्र की जननी है।

नितिन गडकरी ने की लालू यादव की तारीफ

इस दौरान गडकरी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की वक्तृत्व कला की प्रशंसा की। साथ ही बोले- 'मैंने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के 'व्यवहार, सादगी और व्यक्तित्व' से भी बहुत कुछ सीखा है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मैं जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित था, वह जॉर्ज फर्नांडिस थे।

स्मृति ईरानी का गंभीर आरोप...

सुंदर महिलाओं को ले जाते हैं टीएमसी कार्यकर्ता, पार्टी ऑफिस में करते हैं दुष्कर्म



पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कुख्यात संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। यह आरोप खुद संदेशखाली की महिलाओं ने एक वीडियो में लगाया है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई है। यह बेहद दर्दनाक और डराने वाली सच्चाई है।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई है। महिलाओं ने बताया कि टीएमसी के गुंडे हर घर में सबसे खूबसूरत महिला की पहचान करने के लिए घर-घर गए। चिन्हित महिलाओं से कहा गया कि भले ही तुम पति हो, लेकिन अब तुम्हारा अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है। वे हर रात महिलाओं का अपहरण कर लेते थे। वह जब तक हम से संतुष्ट नहीं हो जाते, हमें नहीं छोड़ते। ये आरोप महिलाओं ने लगाए हैं। यह आरोप क्षेत्र के दलित, एसटी, मछुआरा और किसान समुदाय की महिलाओं ने लगाए हैं। संदेशखाली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं के नरसंहार के लिए जानी जाती हैं। वह अब अपने आदमियों को टीएमसी कार्यालय में युवा विवाहित हिंदू महिलाओं को बलात्कार के लिए ले जाने की अनुमति देगी। यह आदमी कौन है?

संदेशखाली की महिलाओं ने बंगाली हिंदू महिलाओं के सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है? अब तक हर कोई सोच रहा है कि शेख शाहजहां कौन है। अब, ममता बनर्जी को इस सवाल का जवाब देना होगा कि शेख शाहजहां कहां है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैंने जो देखा वह भयानक रूप से चौंकाने वाला था। मेरे होश उड़ गए। मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। मैंने बहुत सी चीजें सुनीं जो मुझे कभी नहीं सुननी चाहिए थीं। अगर आपके आंसू हैं, यह उन आंसुओं को बहाने का समय है। मानव जीवन कितना भयानक है, जहां कानून अपना काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैंने वहां अपनी माताओं और बहनों की बात सुनी। एक खुशहाल घर की कल्पना करें। पति और पत्नी, बड़े बच्चे, जिनमें बच्चियां भी शामिल हैं। कुछ गुंडे घर के अंदर से आते हैं, बच्चियों को पकड़ लेते हैं, पति के सामने पत्नी पर हमला करते हैं और पति को पीटते हैं। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि यह किसने किया। हमें इसे संविधान के तहत लड़ना चाहिए। मैं इसे संविधान के तहत लड़ूंगा। मैं इसे कानून के तहत लड़ूंगा। मैं राज्य की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के साथ इसके खिलाफ लड़ूंगा। निश्चित रूप से हम यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि दोषियों को सजा मिले।

भाभी से दुष्कर्म कर उसे मरने पर मजबूर करने वाले देवर को 10 साल की जेल



पति को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्मी देवर वर्षों तक भाभी से दुष्कर्म करता रहा। भाभी ने उससे बचने के लिए मकान भी बदल लिया लेकिन दुष्कर्मी वहां भी पहुंच गया और धमकी देकर दुष्कर्म करने लगा। आखिर परेशान होकर महिला ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच की तो सचाई सामने आ गई। बुधवार को विशेष न्यायालय ने दुष्कर्मी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। 18 जून 2021 को एक महिला को स्वजन इंदौर के एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इस महिला ने एसिड पी लिया था। आरंभिक जांच के बाद डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि महिला के साथ उसका ही देवर दो वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। वह महिला के पति को जान से मारने की धमकी देकर कई बार संबंध बना चुका था। उसके भय के चलते महिला ने यह बात पति को नहीं बताई और किराए के मकान में रहने चली गई।

दुष्कर्मी देवर वहां भी आ गया और उसे धमकाया कि मैंने तेरा मकान देख लिया है। मैं यहाँ भी आऊंगा। परेशान होकर महिला ने एसिड पी लिया था। पुलिस ने दुष्कर्मी देवर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान प्रस्तुत किया। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीपी) जयंत दुबे ने प्रकरण में अभियोजन की ओर से दस गवाहों के बयान करवाए। विशेष न्यायाधीश चारूलता दांगी ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी देवर को धारा 376 506, 306 में दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। दुष्कर्मी एफआइआर दर्ज होने के बाद से ही जेल में है।



इंस्पेक्टर का बेटा यूपी से भागकर इंदौर आया : पुलिस ले गई थाने

इंदौर। इंदौर यूपी के एक इंस्पेक्टर का बेटा घर से झगड़ा कर भाग आया था। सूचना मिली तो तुकोगंज पुलिस पहले ही बस स्टैंड पहुंच गई और बच्चे को सकुशल उतार लिया। गुरुवार को उसके परिजन आकर ले जाएंगे। टीआई जितेंद्र सिंह यादव के अनुसार युवक का नाम मो.ह ताहा पिता ऐनउद्दीन (21) निवासी गिरिजा नगर कानपुर है। लखनऊ में एनडीआरएफ में कार्य करने वाले इंस्पेक्टर ऐनउद्दीन का बेटा घर से झगड़ा करके एक ट्रेवल्स की बस में बैठकर इंदौर आ गया। यह सूचना तुकोगंज पुलिस को मिली तो बस यहां पहुंचने के पहले सिपाही बस स्टॉप पर पहुंच गए थे।

रिहा हुए भारतीय बोले-
प्रधानमंत्री मोदी
न होते तो हम कभी
रिहा नहीं होते...



कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है और इनमें से 7 नागरिक भारत लौट आए हैं। गौरतलब है कि जासूसी के आरोप में इन 8 नागरिकों को कतर में सजा-ए-मौत की सजा दी गई थी। इन भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में कतर के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। सभी 7 भारतीय नागरिकों ने भारत आने पर भारत माता की जय के नारे लगाए। कतर से लौटते पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों में से एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहां खड़ा रहना संभव नहीं था। पीएम मोदी और भारत सरकार के प्रयासों के कारण ही हमारी रिहाई संभव हो सकी है।

18 महीने किया इंतजार

एक अन्य पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी ने भारत लौटने पर खुशी जताते हुए कहा कि हमने भारत आने के लिए करीब 18 माह तक इंतजार किया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अधिक आभारी हैं। भारत सरकार के हर प्रयास के लिए हम तहे दिल से आभार जताते हैं। गौरतलब है कि भारतीय नागरिकों को 25 मार्च, 2023 को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कतर के कानून के मुताबिक, कानूनी कार्यवाही से गुजरना पड़ा। इस दौरान 8 भारतीयों को मौत की सजा दी गई थी। तब भारत ने कतर के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही थी। भारतीय की रिहाई पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए डहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है।

संस्कृति के पन्ने करते हैं खुलासा

सूर्योदय से पहले आकाश क्यों होता है गुलाबी...

महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से दो प्रमुख थीं—कद्रू और विनता। विवाह के कुछ समय बाद कद्रू और विनता ने कश्यप से संतान-प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। कश्यप के पूछने पर कद्रू ने एक हजार पुत्रों की कामना की जबकि विनता बोली, 'मुझे केवल दो पुत्र चाहिए, जो यशस्वी हों।' महर्षि कश्यप ने तथास्तु कहकर दोनों को आशीर्वाद दिया। समय आने पर कद्रू ने एक हजार अंडे और विनता ने दो अंडे उत्पन्न किए। कद्रू के अंडों में से नियत समय पर काले सर्प निकले और धरती पर रेंगने लगे। परंतु विनता के दोनों अंडे जस के तस रहे। काफी प्रतीक्षा के बाद भी अंडों से बच्चे नहीं निकले। कद्रू के बच्चे बड़े हो गए किंतु विनता के अंडे यूं ही रखे रहे। विनता पहले तो चिंतित हुई फिर धीरे-धीरे उसके मन में कद्रू के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई।

एक दिन विनता का धैर्य समाप्त हो गया। उसने एक अंडे को जबरदस्ती फोड़ दिया। उसके भीतर एक पक्षी था। लेकिन वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। वह बाहर निकला तो उसकी त्वचा कच्ची और गुलाबी थी। उसके शरीर का केवल ऊपरी आधा भाग ही विकसित हो पाया था। विनता अपने अर्द्धविकसित पुत्र को देखकर रोने लगी। अंडे से निकल बच्चे ने अपनी अपूर्ण काया देखी तो उसे माता की अधीरता पर क्रोध आया। उसने विनता को शाप दिया : 'तुमने समय से पहले अंडा फोड़कर मेरा जीवन नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिस कद्रू

से तुम्हें ईर्ष्या है, तुम उसी की 500 वर्ष तक दासी बनकर रहोगी। दूसरे अंडे का ध्यान रखना क्योंकि उससे निकलने वाला तुम्हारा दूसरा पुत्र ही कद्रू की दासता से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा।'

यह कहकर विनता का पुत्र आकाश में उड़ गया। उसका नाम अरुण था। वह इतना तेजवान था कि उसने ज्यों ही उड़ान भरी, आकाश गुलाबी आभा से रंजित हो गया। उसका तेज देखकर सूर्यदेव भी प्रभावित हुए। उन्होंने अरुण को अपना सारथी बना लिया। सूर्यदेव का रथ जब निकलता तो रथ के आगे बैठा उनका सारथी अरुण, सूर्यदेव से पहले प्रकट हो जाता। इसीलिए सूर्योदय से पहले आकाश गुलाबी दिखता है और अरुण के नाम पर ही उस गुलाबी आभा को अरुणिमा कहते हैं।

इस घटना के कुछ दिन बाद विनता और कद्रू में एक शर्त लगी और यह तय हुआ कि जो शर्त हारेगा, वह दूसरे का दास बनेगा। कद्रू, छल से शर्त जीत गई और विनता को 500 वर्ष के लिए कद्रू का दासत्व स्वीकार करना पड़ा। अरुण का शाप फलीभूत हो गया। विनता का दूसरा अंडा समय से फूटा और उसमें से एक विशाल पक्षी निकला। वह गरुड़ था। गरुड़ बड़ा हुआ तो उसे अपनी माता विनता के दासत्व का पता लगा। उसने कद्रू के सर्प-पुत्रों से विनता को मुक्त करने का आग्रह किया। दुष्ट सर्पों ने गरुड़ से कहा, 'यदि तुम देवलोक से अमृत लाकर हमें दे दो, तो हम तुम्हारी माता को

मुक्त कर देंगे।'

गरुड़, पर्वतों से विशाल और देवताओं से अधिक सामर्थ्यवान था। वह अमृत लेने देवलोक पहुंच गया। देवताओं ने बहुत प्रयास किया, पर गरुड़ उन्हें परास्त करके अमृत का कलश ले गया। गरुड़ इतना निष्ठावान था कि अमृत पास होने के बावजूद उसके मन में अमृत को चखने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। उसकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया।

अमृत-कलश लेकर गरुड़ कद्रू के सर्प-पुत्रों के पास पहुंचा और उसने कलश कुश घास पर रख दिया। अमृत-कलश को देखकर सर्प अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनता को कद्रू के दासत्व से मुक्त कर दिया। परंतु गरुड़ के लिए एक काम शेष था। सर्पों को अमृत-पान करने से रोकना था। इसके लिए गरुड़ ने सर्पों से कहा कि उन्हें स्नान के उपरांत ही अमृत-पान करना चाहिए। सर्प नदी की ओर चले गए। इस बीच गरुड़ ने अमृत-कलश उठाया और फिर से उसे इंद्र को सौंप दिया।

सर्प, जब स्नान करके लौटे तो अमृत-कलश को वहां न पाकर उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध ने बुद्धि हर ली। वे कुश घास पर टपके अमृत को पीने की मंशा से नुकीली घास को चाटने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि घास की नोक को चाटने से सर्पों की जीभ के दो हिस्से हो गए। तब से, सांप की जीभ दो भाग में बंटी होती है!

विपक्ष से बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय-

डराने की कोशिश न करो, हम भयभीत होने वाले नहीं है...



मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों में हर घर नल कनेक्शन के माध्यम से पानी पहुंचाने के कामों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों ने गुणवत्ताहीन काम किया है। दस प्रतिशत घरों में भी नल से पानी नहीं पहुंच रहा है। ठेकेदारों ने गांवों की कांक्रिट की सड़कों को पाइप लाइन बिछाने में बर्बाद कर दिया और सुधार भी नहीं हो रहा है।

पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति है। इसकी जांच कराई जाए। जब सत्ता पक्ष से इसका आश्वासन नहीं मिला तो कांग्रेस के सदस्यों ने ठेकेदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें डराने की कोशिश न करो, हम चमकने वाले नहीं हैं। ये मोहन सरकार है जो न तो जांच कराने से डरती है और न ही किसी को संरक्षण दिया जा रहा है। प्रश्नकाल में लगभग 45 मिनट इस मुद्दे पर हंगामा चला और कांग्रेस ने बहिर्गमन कर विरोध जताया। प्रश्नकाल के दौरान विवेक पटेल ने वारासिवनी क्षेत्र में नल जल योजना का विषय उठाया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उड्के ने इसके उत्तर में कहा कि जो समयसीमा और गुणवत्तायुक्त काम नहीं करेगा, उसके विरुद्ध

कार्रवाई की जाएगी। भुगतान भी नहीं होगा।

इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार, रामनिवास रावत सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि बड़ी योजना है और इससे बड़ी आबादी लाभांवित होगी लेकिन ठेकेदारों ने कहीं भी काम पूरा नहीं किया है। गर्मी आने वाली है और कहीं भी नल से पानी नहीं मिल रहा है। सरकार अधिकारियों को क्यों बचाना चाहती है। हर तरह भ्रष्टाचार है। आखिर ये सरकार जनता की है या नहीं।

विधानसभा स्तर से समिति बनाकर इसकी जांच कराने में क्या परेशानी है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक विधानसभा से जुड़ा मामला है। ऐसे पूरे प्रदेश की जांच नहीं करा सकते हैं। सदस्य, जहां की जानकारी देंगे, वहां जांच कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये मोहन सरकार है न तो हम जांच करवाने से डरते हैं और न ही किसी को संरक्षण देंगे। इस पर सिंधार ने सदन में पूरे प्रदेश की जांच कराने का आश्वासन देने की मांग रखी, जिसे उन्होंने नकार दिया, जिस पर दोनों पक्षों में बहस होने लगी और फिर विजयवर्गीय ने कहा कि डराने की कोशिश न करो, हम चमकने वाले नहीं है।

जैविक खेती का एक
चौथाई रकबा प्रदेश में,
दूसरे नं. पर महाराष्ट्र

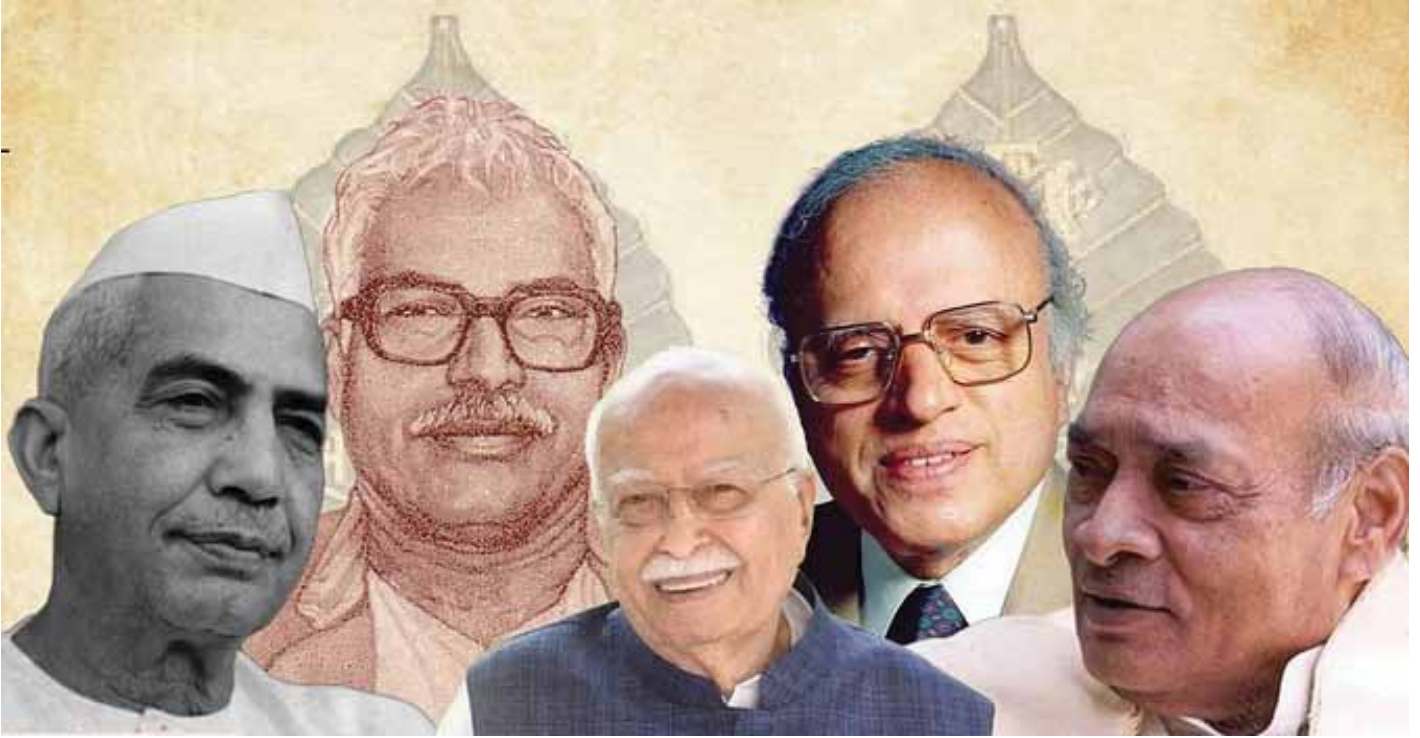


खादों के ज्यादा उपयोग से जमीन और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट के बीच अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ा है। देश में जैविक खेती का सबसे बड़ा रकबा मध्य प्रदेश में 15 लाख 92 हजार हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पर 13 लाख हेक्टेयर के साथ महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात में नौ लाख 37 हजार हेक्टेयर, राजस्थान में छह लाख 78 हजार है। बाकी राज्यों में जैविक खेती का रकबा तीन लाख हेक्टेयर से कम है। देश में कुल 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। केंद्र सरकार की पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में तीन हजार से अधिक क्लस्टर बने हैं। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय की पिछले दिनों राज्य सभा में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। बता दें कि प्रदेश में खेती का कुल रकबा डेढ़ करोड़ हेक्टेयर है। प्रदेश में कुछ किसान लंबे समय से जैविक खेती करते रहे हैं, पर सरकारी प्रोत्साहन के साथ इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में प्रत्येक विकासखंड में एक गांव में जैविक खेती के साथ हुई थी। केंद्र सरकार की जैविक उत्पादन कृषि नीति (एनपीओपी) के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई है। इसमें जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रविधान किए गए हैं। उत्पादों का सीधे विक्रय की जगह ब्रांड नाम उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना, जैविक उत्पाद विपणन केंद्रों का विकास, प्रसंस्करण की सुविधाएं प्रदान करना, उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण शामिल है।

लगभग 15 लाख टन प्रतिवर्ष
तैयार हो रहा जैविक उत्पाद

किसान एवं कृषि कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 14 से 15 लाख टन जैविक उत्पाद तैयार हो रहा है। इसमें लगभग पांच लाख टन से अधिक जैविक उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। सहकारिता के माध्यम से भी इसे और विस्तार दिया जा रहा है।

भारत रत्न : मास्टर स्ट्रोक... स्पष्ट हैं इसके राजनीतिक संदेश...



भारत रत्न का सम्मान दिए जाने और न दिए जाने के पीछे हमेशा से राजनीति होती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नया अर्थ और प्रासंगिकता दी है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख हों या फिर लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, यह उन लोगों को सम्मानित करने की मोदी की राजनीति के स्पष्ट संकेत थे, जिन्हें कांग्रेस द्वारा नजर अंदाज और तिरस्कृत किया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ कृषि वैज्ञानिक एमएसे स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की मोदी की नवीनतम घोषणा से यह पता चलता है कि उनकी सरकार भारत की समकालीन राजनीति और अर्थव्यवस्था में इन तीनों हस्तियों की भूमिका को कितना महत्व देती है। इन्हें क्रमशः पहली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों, किसानों के हितों की वकालत करने वाले और बेहतर खाद्य उत्पादकता और सुरक्षा के लिए विज्ञान का उपयोग करने वाले चैंपियन के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प यह है कि ये सभी 2024 के चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी के अभियान के पसंदीदा विषय हैं।

दरअसल, महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन को यह पुरस्कार 1960 के दशक में भारत

के खाद्य संकट को खत्म करने के लिए हरित क्रांति को लाने में उनकी बड़ी भूमिका को मान्यता देता है। यह स्वामीनाथन की रणनीति ही थी, जिसकी बदौलत भारत के कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से बतौर वैज्ञानिक उनके काम के परिणामस्वरूप पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को उच्च उपज की किस्म वाले बीज, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और उर्वरक उपलब्ध कराए गए। वर्षों बाद, 2004 से 2006 के बीच राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. स्वामीनाथन ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जिस पर किसान अपनी फसलें सरकार को बेचते हैं, वह औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा होना चाहिए। डॉ. स्वामीनाथन के योगदान का महत्व इस

तथ्य से समझा जा सकता है कि आज ऐसा कोई दिन नहीं बीतता, जब किसानों के संघ कानूनी गारंटी के रूप में सभी उपज के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू करने की मांग न करते हों। यह महज संयोग तो नहीं हो सकता कि स्वामीनाथन को पुरस्कार तब दिया गया है, जब उपज की खरीद के लिए कानूनी गारंटी और बिजली के बिलों में संशोधन सहित अपनी लंबित मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया हो।

दूसरी तरफ, चुनावी वर्ष में नरसिम्हा राव और चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार महज उनके योगदान को मान्यता नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं की यादृशत को ताजा करने का मोदी का तरीका है कि कैसे उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार को चुनौती दी

थी, जिससे सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के बारे में भाजपा का जो नैरेटिव रहा है, उसे ही मजबूती मिलती है।

इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। आडवाणी भाजपा के राम मंदिर आंदोलन का चेहरा थे, जिन्होंने 1992 के उन दृश्यों को देखा था, जब भीड़ द्वारा विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। कालांतर में इस आंदोलन ने एक लंबी कानूनी लड़ाई का रूप लिया, जिसकी परिणति सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के रूप में हुई, जिसने भव्य मंदिर खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। कर्पूरी ठाकुर की भूमिका तो और भी महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ ओबीसी राजनीति का चेहरा नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के कट्टर आलोचक और बिहार में कांग्रेस विरोधी आंदोलन का गढ़ भी थे।

बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री के तौर पर ठाकुर राज्य में ओबीसी के लिए कोटा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। नरसिम्हा राव नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1991 में उदारीकरण की पहली लहर शुरू करने का राजनीतिक साहस दिखाया और 1996 तक बदलावों के लिए काम करते रहे, जब तक कि उनकी सरकार चुनाव हार नहीं गई। प्रधानमंत्री के रूप में अपने चुनौतीपूर्ण वर्षों के दौरान राव ने उस वक्त सोनिया गांधी के नजदीकी समझे जाने वाले शरद पवार और अर्जुन सिंह जैसे कांग्रेसी नेताओं की चुनौतियों का भी सामना किया। राव के कार्यकाल में गांधी परिवार और उनके समर्थकों के प्रभाव को कम किया गया, जिससे वह समकालीन कांग्रेस विरोधी नेताओं के लिए नायक बने।

अयोध्या में विवादित ढांचे को बचाने में कथित विफलता के लिए सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने राव को दोषी ठहराया, पर एक सुधारवादी के रूप में उनका कौशल इन सब पर हावी रहा। 1996 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के जीतने में विफल रहने पर सोनिया गांधी और उनके वफादार नेताओं ने खुले तौर पर राव की विरासत को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण देवगौड़ा और गुजराल के नेतृत्व में एक गठबंधन हुआ, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। हालांकि दिसंबर, 2004 में अपनी मृत्यु तक राव डॉ. मनमोहन सिंह जैसे अपने वफादार नेताओं के लिए आदरणीय और अविभाजित आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए राज्य के गौरवशाली पुत्र बने रहे। भाजपा का दावा है कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखने की अनुमति न देकर कांग्रेस नेतृत्व ने उनका अपमान किया।

राव को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा तब हुई है, जब आगामी अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तेलंगाना में भी राव को भारत रत्न दिए जाने की मांग बीआरएस जैसी पार्टियां लंबे समय से करती आई हैं। चरण सिंह मामले में, जो इंदिरा गांधी द्वारा केवल 24 सप्ताह के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिए गए समर्थन के झांसे में आ गए थे, यह सम्मान जाट समुदाय में आज भी 'कुलक नेता' के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। उनकी राजनीति को महत्व देने वालों के लिए वह 1970 के दशक में गैर-कांग्रेसवाद का एक प्रमुख चेहरा थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों के लिए उन्होंने जो किया, वह कृषि क्षेत्र के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को देखा जा सकता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले-

एक राष्ट्र-एक छात्र में 25 करोड़ रुपए आईडी तैयार, बाल वाटिका से पीएचडी तक आएगा काम...



केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आईडी से बोर्ड परीक्षा, जेईई मेन, नीट, सीयूईटी यूजी, पीजी समेत अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा, दाखिला, स्कॉलरशिप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट से लेकर नौकरी के दौरान छात्र के सत्यापन करने में आसानी होगी। इससे यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसका पता लगाना आसान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को बताया कि 'एक राष्ट्र-एक छात्र' योजना के तहत 25 करोड़ छात्रों की यूनिक आईडी तैयार हो चुकी है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बालवाटिका (पूर्व में नर्सरी) से लेकर पीएचडी और कौशल विकास में छात्रों की पहचान इस 12 अंक की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (एपीएएआर) से होगी। यह आईडी भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर पर भी सुविधाएं प्रदान करेगी।

प्रधान ने बताया कि आईडी से बोर्ड परीक्षा, जेईई मेन, नीट, सीयूईटी यूजी, पीजी समेत अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा, दाखिला, स्कॉलरशिप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट से लेकर नौकरी के दौरान छात्र के सत्यापन करने में आसानी होगी। इससे यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसका पता लगाना आसान होगा। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा में कोई भी छात्र किसी अन्य की जगह परीक्षा नहीं दे पाएगा। सर्टिफिकेट और डिग्री की धोखाधड़ी से निजात मिलेगी। योजना में छात्रों का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी से साझा नहीं होगी।

एक राष्ट्र-एक छात्र में 25 करोड़ आईडी तैयार,

बालवाटिका से पीएचडी तक आएगा काम

जन्म से लेकर बालवाटिका में दाखिला लेने तक छात्र का नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (एपीएएआर) से जुड़ जाएगा। उसमें छात्र और माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो, पता और आधार नंबर डाला जाएगा। बालवाटिका दाखिले के समय बनी आईडी पीएचडी, स्कॉलरशिप, रिसर्च और कौशल विकास तक चलेगी। यही आईडी उसकी पहचान होगी। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए भी अभिभावकों को अब नहीं भटकना पड़ेगा।

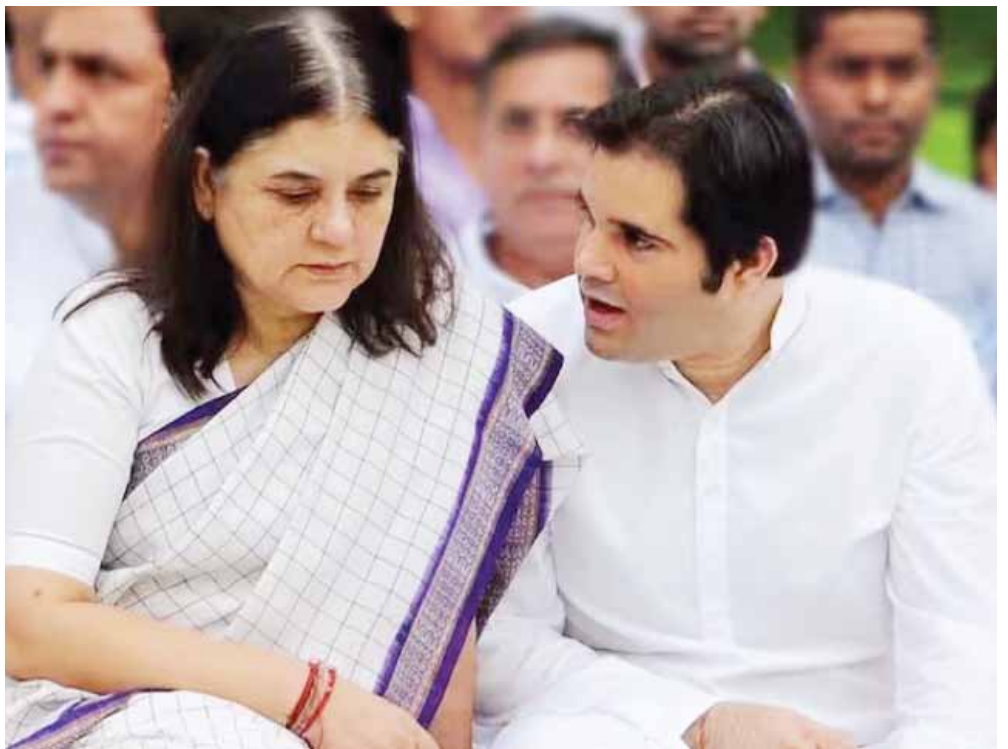
डिजिटल और अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी जुड़ी

यह आईडी डिजिटल और अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी जुड़ जाएगी। जैसे ही छात्र कोई कोर्स, डिग्री, सर्टिफिकेट, स्किल कोर्स समेत अन्य कोई उपलब्धि हासिल करता है तो उसके सर्टिफिकेट उसमें जुड़ जाएगा। इससे छात्र की शैक्षणिक योग्यता और सर्टिफिकेट की जांच अलग से नहीं होगी। योजना में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्र देश में कहीं से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। लेकिन ट्रांसफर सर्टिफिकेट से लेकर अन्य जटिलताओं के कारण अभी सरकारी, निजी स्कूलों और कॉलेजों में यह संभव नहीं हो पाता है। इस यूनिक आईडी में डिजिटली सब सर्टिफिकेट होने से छात्र आसानी से ट्रांसफर ले सकेगा।

मेनका और वरुण का टिकट काट कर तथा सोनिया को हरा कर

उत्तरप्रदेश को गांधी परिवार से मुक्त करेगी भाजपा...

प्रियंका वाड़ा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से भले ही अपने को समेट लिया हो लेकिन रायबरेली में उनकी राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं, इसीलिए राजनीति के जानकार प्रियंका वाड़ा के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इंकार नहीं करते हैं।



भा रतीय जनता पार्टी देश को कांग्रेस मुक्त भले नहीं कर पाई हो लेकिन उत्तर प्रदेश को गांधी मुक्त बनाने की ओर उसके कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेताओं को लगता है कि ऐसा मोदी-योगी के कुशल नेतृत्व में होने जा रहा है। ऐसा कैसे होगा? यह समझना मुश्किल नहीं है। एक तरफ इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी के लिये लगातार मुसीबत साबित हो रहे राहुल गांधी के चचेरे भाई और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काट सकता है, वहीं उनकी माता मेनका गांधी को उम्र दराज होने के कारण लोकसभा से साइड लाइन करने की तैयारी की जा रही है। मेनका गांधी और वरुण गांधी अब बीजेपी के लिये अनुपयोगी हो गये हैं। बीजेपी इन दोनों नेताओं को यह सोच कर पार्टी में लाई थी कि वरुण गांधी के जरिये वह सोनिया और राहुल गांधी को सियासी आईना दिखायेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं उल्टे वरुण गांधी बीजेपी और पीएम मोदी के लिए ही सिरदर्द बन गये। पूरे कार्यकाल के दौरान वरुण गांधी केन्द्र की मोदी सरकार के कामकाज की आलोचना में लगे रहे, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ मुंह तक नहीं खोला। इसी के चलते वरुण का टिकट कटना तय है। यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी गांधी मुक्त हो जायेगी।

बात प्रदेश को गांधी मुक्त करने की कि जाये तो आज की तारीख में यूपी में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली में दिखाई दे रही है। बाकी जगह वह सिमट चुकी है। राहुल गांधी को तो 2019 में ही बीजेपी ने अमेठी से हार का स्वाद चखा कर, ना केवल अमेठी बल्कि प्रदेश से बाहर कर दिया है। अब बीजेपी की मंशा रायबरेली को सोनिया मुक्त करने की है। इसके लिए पिछले पांच सालों में बीजेपी ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में काफी मेहनत की है। बीजेपी को जिसका फल आगामी लोकसभा चुनाव में मिलता दिख रहा है। रायबरेली में सोनिया गांधी की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रह गई है जितनी पहले हुआ करती थी। यहां से प्रियंका वाड़ा के भी चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। बीजेपी दोनों ही दशा में गांधी परिवार से मुकाबला करने के लिए कमर कसे हुए है। बीजेपी रायबरेली में कांग्रेस की उन दोनों संभावनाओं को खत्म कर देना चाहती है जिसके अनुसार रायबरेली में सोनिया गांधी की जगह प्रियंका वाड़ा को चुनाव लड़ाये जाने की चर्चा राजनीति के गलियारों में चल रही है। बीजेपी सोनिया गांधी या प्रियंका वाड़ा दोनों को ही अब यहां पर पैर जमाये रखने का मौका नहीं देना चाहती है।

दरअसल, प्रियंका वाड़ा ने 2022 के विधानसभा

चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से भले ही अपने को समेट लिया हो लेकिन रायबरेली में उनकी राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं, इसीलिए राजनीति के जानकार प्रियंका वाड़ा के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इंकार नहीं करते हैं। यदि सोनिया गांधी राजनीतिक दबाव के चलते रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो प्रियंका वाड़ा के लिए अमेठी दूसरी सबसे सुरक्षित सीट रह सकती है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां से राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने काफी मेहनत की है। इसलिए हाल फिलहाल राहुल गांधी की तो दाल अमेठी में नहीं गलती दिखाई दे रही है वहीं प्रियंका वाड़ा को भी यहां से चुनाव लड़ने से पहले सौ बार सोचना होगा। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 48 सालों तक उत्तर प्रदेश की अमेठी विकास से वंचित रही, जबकि लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार के लोग करते रहे थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही इस संसदीय क्षेत्र का विकास होना शुरू हुआ। ईरानी ने कहा कि राजमोहन गांधी ने गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें गांधी परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए नकली गांधी बुलाया गया था।

मेनका गांधी और शरद यादव को भी अपमानित किया गया था। शरद यादव से कहा गया कि वह जाकर गाय चराएं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में यदि अमेठी के बाद रायबरेली में भी गांधी परिवार का उम्मीदवार हार जाता है तो यूपी पूरी तरह से गांधी परिवार मुक्त हो जाएगा। सोनिया की हार की संभावनाओं से इसलिए इंकार नहीं किया जाता क्योंकि पिछले 5 सालों से वह रायबरेली से पूरी तरह से कटी हुई है, जबकि भाजपा ने यहां काफी मेहनत की है।

बात अमेठी और रायबरेली से आगे की कि जाये तो बीजेपी का सबसे अधिक फोकस यूपी पर ही है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी लगातार प्लान बना रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी करीब डेढ़ दर्जन सांसदों के टिकट काट सकती है वहीं जातीय समीकरणों को देखते हुए कई नए चेहरों पर भी मंथन किया जा रहा है। इसी के साथ यूपी की हारी सीटों को लेकर भी बीजेपी ने अहम रणनीति बनाई है। यूपी में जिन सीटों पर नए चेहरों को लेकर चर्चा है उनमें पहला नाम सहारनपुर का है जहां से बीजेपी के राघव लखनपाल की जगह नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही बिजनौर सीट पर कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह नया जाट चेहरा आगे किया जा सकता है। नगीना सीट से यशवंत सिंह की टिकट पर सस्पेंस है। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश कुमार की जगह नया चेहरा संभव है। संभल सीट से परमेश्वर लाल सैनी की टिकट पर और अमरोहा से कंवर सिंह तंवर की टिकट पर संशय है। इसी तरह से मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य की जगह नया उम्मीदवार उतारा जा सकता है। वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी वर्मा, श्रावस्ती से दहन मिश्रा, लालगंज से नीलम सोनकर, घोसी से हरिनारायण राजभर का टिकट काट सकता है। उधर गाजीपुर से 2019 में बीजेपी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी रहे मनोज सिन्हा की जगह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सीट दी जा सकती है। जौनपुर से कृष्ण प्रताप सिंह की जगह निषाद पार्टी के प्रत्याशी को यहां से लड़ाया जा सकता है। यह वह बीजेपी नेता हैं जो 2019 में लोकसभा चुनाव जीत नहीं सके थे।

बात भाजपा के मौजूदा सांसदों, जिनका टिकट कटने की उम्मीद है उनकी की जाये तो उसमें कानपुर से सत्यदेव पंचेरी (76 साल), बहराइच से अक्षयवर लाल (77), बाराबंकी से उपेंद्र सिंह, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह (73), मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल (73), हाथरस से राजवीर दिलेर, मथुरा से हेमामालिनी (75), बरेली से संतोष गंगवार (75), फिरोजाबाद से चंद्रसेन जादौन (73) का और कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी और बदरगंज से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या की बेटी संघमित्रा मौर्या का भी टिकट कटना तय लग रहा है।

लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि यूपी में बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक 80 सीटें हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी कि बात की जाये तो 2019 में यूपी की 80 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में एनडीए में बीजेपी और अपना दल (एस) एक साथ मिलकर लड़े थे और एनडीए का 51.19 प्रतिशत वोट शेयर रहा था। जिसमें बीजेपी के खाते में 49.98 प्रतिशत और अपना दल (एस) को 1.21 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। वहीं महगठबंधन (बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल) को 39.23 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। जिसमें बसपा को 19.43 प्रतिशत, सपा को 18.11 प्रतिशत और अलौद को 1.69 प्रतिशत वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 6.36 वोट शेयर मिला था।

सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश

पश्चिम बंगाल की जेलों में 4 साल में जन्में 62 बच्चे

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई महिला कैदियों के हिरासत में गर्भवती होने के आरोप पर संज्ञान लिया था। मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सूचित किया गया कि पिछले चार वर्षों में पश्चिम बंगाल की जेलों में 62 बच्चों का जन्म हुआ और जन्म देने वाली ज्यादातर महिला कैदी थी।



जेलों में अमानवीय स्थितियों के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल न्याय मित्र के रूप में कोर्ट की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि कि उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में हिरासत में रहते हुए महिला कैदियों से पैदा हुए बच्चों के संबंध में जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की जेल में 62 बच्चे पैदा हुए थे।

कोर्ट के निर्देश के लिए दायर एक आवेदन में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश महिला कैदी उस समय पहले से ही गर्भवती थीं जब उन्हें जेलों में लाया गया था। कुछ मामलों में महिला कैदी पैरोल पर बाहर गई थीं और उम्मीद से वापस लौट आईं। गौरतलब है कि गौरव अग्रवाल ने जेलों में प्रचलित कथित अमानवीय स्थितियों से संबंधित एक मामले में आवेदन दायर किया। उन्होंने कहा कि जेलों या महिलाओं के लिए बैरक में सुरक्षा उपायों को समझने के लिए उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और

दिल्ली के जेल अधिकारियों के साथ चर्चा की। आवेदन में कहा गया है कि बातचीत से ऐसा लगता है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल समेत कुछ जगहों पर महिलाओं के लिए अलग जेलें हैं। इसमें कहा गया है कि इन जेलों में केवल महिला अधिकारी हैं और किसी भी पुरुष कर्मचारी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नौ फरवरी को पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों के गर्भवती होने के आरोपों पर संज्ञान लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने गौरव अग्रवाल को इस पर गौर करने और एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आठ फरवरी को एक संबंधित मामले को एक आपराधिक खंडपीठ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जब न्याय मित्र ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में बंद कुछ महिला कैदी जेल में गर्भवती हो गई थीं और कई बच्चों का जन्म हुआ था।

मौसम बदलते ही गले की खराश के लिए नींबू - शहद का उपाय



बदलते मौसम गले की खराश के लिए नींबू और शहद का उपाय कितना कारगर साबित होगा, जानिए सीके बिड़ला अस्पताल (आर), दिल्ली के ईएनटी विभाग की प्रमुख सलाहकार डॉ. दीप्ति सिन्हा ने कहा, यह प्राकृतिक इलाज राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर लक्षण गंभीर या पुराने हैं तो हमेशा डॉक्टर को देखने की सलाह दी जाती है। मौसम बदलते ही अक्सर सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसी मौसमी समस्याओं का अनुभव करते हैं। जबकि एक गोली खाने या कफ सिरप पीने को प्राथमिकता दी जाती है, कई लोग घरेलू हर्बल उपचारों का भी सहारा लेते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इससे तुरंत राहत मिलती है। आइए जानते हैं क्या नींबू का रस और शहद मिलाकर गले की खराश से राहत मिलती है? जानें एक्सपर्ट की राय।

आहार विशेषज्ञ सिमरत भुई ने कहा, जब गले में खराश होने पर नींबू को शहद के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है, तो दोनों की एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति एकदम राहत देती है। भुई ने कहा, 'शहद में एंटी-इंफ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं और सांस रोगों में कई चिकित्सीय भूमिकाएं होती हैं। जिंदल नेचरक्योर इंस्टीट्यूट के डॉ. श्रीकांत एचएस (सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी) ने कहा कि नींबू की खट्टा प्रकृति कफ को तोड़ने और संक्रमण से लड़ने में सहायता कर सकती है। वहीं एक्सपर्ट सिमरत भुई ने कहा कि इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी मिला सकते हैं। भुई ने कहा,

'इससे दर्द, सूजन और खराश से तुरंत राहत मिलेगी।'

डॉ. श्रीकांत ने कहा कि इस मिश्रण का नमीयुक्त प्रभाव गले में सूखापन और जलन को कम करने में मदद करता है, जिससे सेहत में राहत मिलती है। 'शहद से जुड़े बोटुलिज़्म के खतरे के कारण, शिशुओं और बच्चों को छोड़कर, नींबू और शहद का उपाय आम तौर पर सभी आयु समूहों के लिए सुरक्षित है। बच्चों के लिए नींबू के रस को पानी में घोलकर और थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर मिश्रण को और अधिक स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।' सीके बिड़ला अस्पताल (आर), दिल्ली के ईएनटी विभाग की प्रमुख सलाहकार डॉ. दीप्ति सिन्हा ने कहा कि ताजा अदरक के रस में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीने से बच्चों सहित हर आयु वर्ग के लिए गले की खराश का अधिक शक्तिशाली घरेलू इलाज हो जाता है। 'शहद के जीवाणुरोधी और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गले की खराश को शांत करते हैं, और नींबू की विटामिन सी कंसंट्रेशन प्रतिरक्षा को बढ़ाती है और बलगम के खत्म करने की सुविधा प्रदान करता है। अदरक के आवश्यक एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण उपचार की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं।'

कैसे बनाएं?

200 मिलीलीटर पानी में ताजा अदरक का एक छोटा टुकड़ा, एक चम्मच शहद और ताजा नींबू

के रस की कुछ बूंदें उबालकर एक स्वस्थ मिश्रण बनाया जा सकता है। डॉ. सिन्हा ने कहा, 'ओसीटी (ओवर-द-काउंटर) सूप पैकेट के बजाय ताजी सामग्री का उपयोग सक्रिय पदार्थों की उच्च कंसंट्रेशन की गारंटी देता है, जो इलाज के संभावित लाभों को बढ़ा सकता है।'

तथा ध्यान रखें?

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिशु बोटुलिज़्म के जोखिम के कारण एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं दिया जाना चाहिए। जिन लोगों को इनमें से किसी भी घटक से एलर्जी है, उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। डॉ. सिन्हा ने कहा, 'इस प्राकृतिक इलाज से राहत मिल सकती है, लेकिन अगर लक्षण गंभीर या लंबे समय तक बने रहें तो हमेशा डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है।' बता दें कि, साइट्रस एलर्जी वाले व्यक्तियों को सावधानी बरतनी चाहिए। इसके जगह वैकल्पिक उपाय अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। डॉ. श्रीकांत ने कहा, 'अगर गले में खराश बनी रहती है या बिगड़ जाती है, खासकर बच्चों में, तो चिकित्सकीय सलाह लेना सर्वोपरि है। ये प्राकृतिक उपचार सहायक उपायों के रूप में काम करते हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा मार्गदर्शन का स्थान नहीं लेना चाहिए।'

मां लक्ष्मी ने पृथ्वी पर लिए कई अवतार, इन मंत्रों के जाप से प्रसन्न होंगी धन की देवी...

धार्मिक ग्रंथों में देवी महालक्ष्मी को सप्त ऋषियों में से एक महर्षि भृगु की पुत्री बताया गया है। बताया जाता है कि महालक्ष्मी का समुद्रमंथन के समय पुनर्जन्म हुआ था। जिसके बाद वह वैकुण्ठ लोक में वास करने लगी थीं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक क्षीर सागर से समुद्रमंथन के समय महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। जिसके बाद महालक्ष्मी ने श्रीहरि विष्णु को अपने वर के रूप में स्वीकार किया था। बता दें कि महालक्ष्मी को श्री के रूप में भी जाना जाता है। तमाम धार्मिक ग्रंथों में देवी महालक्ष्मी को सप्त ऋषियों में से एक महर्षि भृगु की पुत्री बताया गया है। बताया जाता है कि महालक्ष्मी का समुद्रमंथन के समय पुनर्जन्म हुआ था। जिसके बाद वह वैकुण्ठ लोक में वास करने लगी थीं। वहीं महालक्ष्मी ने श्रीहरि विष्णु के श्रीराम अवतार में मां सीता और श्रीकृष्ण अवतार में देवी राधा का अवतार लिया था।

मां महालक्ष्मी के पुत्र

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक श्री महालक्ष्मी के 18 पुत्र हैं। जिनके नाम देवसखा, आनन्द, कर्दम, श्रीप्रद, सम्वाद, विजय, चिक्लीत, जातवेद, अनुराग, वल्लभ, मद, हर्ष, बल, गुग्गुल, कुरूण्टक, तेज, दमक और सलिल हैं।

मां लक्ष्मी का स्वरूप

मां लक्ष्मी को कमल-पुष्प पर खड़ी या विराजमान मुद्रा में चतुर्भुज रूप में चित्रित किया जाता है। वह अपने ऊपर के दो हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और मां लक्ष्मी का एक हाथ वरदान मुद्रा में होता है। जो अपने भक्तों को सुख-संपत्ति और समृद्धि प्रदान करता है। मां लक्ष्मी का अंतिम हाथ अभय मुद्रा में रहता है। श्रीलक्ष्मी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं और स्वर्णाभूषणों से अलंकृत रहती हैं। श्रीलक्ष्मी के मुख पर हमेशा शांति और सुख का भाव रहता है। मां के पास 2 या 4 हाथी उनका जलाभिषेक करते रहते हैं। वहीं देवी लक्ष्मी का वाहन श्वेत गज और उल्लू है।

लक्ष्मी जी के अवतार

मां आदिलक्ष्मी इस सृष्टि की सर्वप्रथम माता हैं। मां धनलक्ष्मी धन और संपत्ति प्रदान करती हैं। मां धान्यलक्ष्मी अन्न और आहार प्रदान करने वाली हैं। मां गजलक्ष्मी सभी को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करती हैं। मां संतानलक्ष्मी वंश वृद्धि और संतान प्रदान करती हैं। मां वीरलक्ष्मी साहस और वीरता प्रदान करने वाली हैं। मां विजयलक्ष्मी सभी शत्रुओं पर विजय प्रदान करने का आशीर्वाद देती हैं। मां ऐश्वर्यलक्ष्मी सभी तरह के भोग-विलास प्रदान करने वाली हैं।



मां लक्ष्मी के इन महालक्ष्मी स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इन अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों के अलावा मां लक्ष्मी की अन्य रूपों में भी पूजा-अर्चना की जाती है। मां विद्यालक्ष्मी सभी को ज्ञान और विद्या प्रदान करने वाली हैं।

मां राज्यलक्ष्मी राज्य और भू-संपत्ति प्रदान करने वाली हैं। मां सौभाग्यलक्ष्मी सौभाग्य देने वाली हैं। मां वरलक्ष्मी वरदान प्रदान करने वाली हैं। मां धैर्यलक्ष्मी धैर्य प्रदान करने वाली हैं।

देवी लक्ष्मी के मंत्र

लक्ष्मी बीज मन्त्र

ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः॥

महालक्ष्मी मंत्र

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः॥

लक्ष्मी गायत्री मंत्र

ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि,

तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥

लौंग को रात भर मुंह में रखने से मिलते हैं यह सात फायदे



जब स्वास्थ्य की बात आती है तो आहार में छोटी-छोटी चीजें शामिल करने से बड़ा अंतर आ सकता है। लौंग एक प्रकार से हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट और एंटीइंफ्लेमेटरी गुणों वाला एक छोटा सा मसाला, न केवल एक फीके व्यंजन को स्वादिष्ट में बदल देता है, बल्कि आपके शरीर को शक्तिशाली पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करता है जो बीमारियों और संक्रमणों को दूर रख सकते हैं। पाचन स्वास्थ्य के लिए अद्भुत काम करता है, चाहे जोड़ों का दर्द हो या जी मिचलाना हो। सूजन या दांत स्वास्थ्य समस्या, लौंग का एक छोटा सा टुकड़ा कई लक्षणों से राहत दिला सकता है। हर भारतीय किचन के मसालों में लौंग का इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। यह खाने के स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रात के सोते समय मुंह में दो लौंग रखने से सेहत को बेहद फायदा मिलता है।

गट हेल्थ में फायदेमंद

लौंग में एंटीऑक्सिडेंट के गुण होते हैं और इसका सीधा फायदा गट हेल्थ को मिलता है। इससे गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर करता है।

शुगर में मदद करता है

लौंग में पाए जाने वाले गुण शुगर को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकते हैं। प्रीडायबिटीज वाले और बिना मधुमेह वाले लोग, जिन्होंने 30 दिनों तक प्रतिदिन 250 मिलीग्राम (मिलीग्राम) लौंग का अर्क लिया, उनमें भोजन के बाद शुगर काफी कम पाया गया। लौंग का रस बॉडी में इंसुलिन का तरह काम करता है। रात के समय मुंह में लौंग रखने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। लौंग को रात के समय मुंह में रखने से विषाक्त पदार्थ थायोएसिटामाइड के कारण होने वाली लिवर की क्षति में सुधार किया जाता है। इससे लिवर में फ्री रेडिकल्स से सुरक्षित रहता है और डैमेज सेल्स की मरम्मत हो जाती है।

यूटीआई में राहत

लौंग में मौजूद इथेनॉलिक तत्व बैक्टेरिया की रोकथाम करता है। इसलिए रात को सोते समय मुंह में लौंग रखने से यूरीन ट्रेक में इन्फेक्शन की समस्या से बचाव होता है।

मुंह के बदबू से छुटकारा

लौंग में कई गुण होते हैं जो मुंह की बदबू और दांतों के दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं, तो रात को आप मुंह में लौंग जरूर रखें।

आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं अष्टचिरंजीवी

किसी को श्राप... तो किसी को वरदान से प्राप्त हुआ अमरत्व



अष्ट चिरंजीवी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है, जो अमर होता है यानी की उनका कभी अंत नहीं होता है। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक पृथ्वी पर एक-दो नहीं बल्कि 8 चिरंजीवी मौजूद हैं। जिनका कभी अंत नहीं होगा और इनमें से कुछ को अमरता का वरदान प्राप्त है। तो वहीं कुछ श्राप के कारण अमर हो गए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इन 8 चिरंजीवी के बारे में बताने जा रहे हैं।

हनुमान जी

माता सीता द्वारा हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है। जब प्रभु श्रीराम का संदेश लेकर हनुमान मां सीता के पास अशोक वाटिका पहुंचे। तो मां सीता हनुमानजी की भक्ति व श्रीराम के प्रति समर्पण देख अति प्रसन्न हुईं। जिसके बाद सीताजी ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया। मान्यता के अनुसार, आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर वास करते हैं और प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन हैं।

अश्वत्थामा

जहां कुछ चिरंजीवी को अमरता का वरदान मिला, तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए। इस लिस्ट में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम शामिल है। महाभारत युद्ध के दौरान पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अनीति का रास्ता अपनाया। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का निद्रा में वध कर दिया। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को क्रोधित होते हुए श्राप दिया

कि पृथ्वी के अंत तक घावों से लथपथ शरीर लेकर अश्वत्थामा भटकता रहेगा और उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। श्रीकृष्ण के श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है।

राजा बलि

प्रह्लाद भगवान श्रीहरि विष्णु के परम भक्त थे और राजा बलि प्रह्लाद का वंशज है। जब श्रीहरि वामन रूप धारण कर राजा बलि की परीक्षा लेने आए, तो बलि ने भगवान वामन को अपना सबकुछ दान कर दिया था। राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने उनको अमरता का वरदान दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में वास कर रहे हैं।

विभीषण

विभीषण लंकापति रावण का सबसे छोटा भाई था। विभीषण को भी अमरता का वरदान प्राप्त था और यह वरदान स्वयं श्रीराम ने दिया था। बताया जाता है कि रावण के वध के बाद श्रीराम ने विभीषण को सोने की लंका सौंप दी थी और साथ ही अमरत्व का वरदान दिया था। वर्तमान में भी विभीषण पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं।

परशुराम

परशुराम भगवान शिव के परभक्त थे। साथ ही वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। परशुराम हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न

होकर स्वयं महादेव ने परशुराम को अमरता का वरदान दिया था। वहीं महाभारत और रामायण दोनों में ही परशुराम का उल्लेख मिलता है।

कृपाचार्य

बता दें कि कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से ऋषि कृपाचार्य ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कृपाचार्य का नाम परम तपस्वी ऋषियों में शामिल है। कृपाचार्य के तप की वजह से उन्हें अमरता का वरदान मिला था।

वेदव्यास

महर्षि वेदव्यास ने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचनाकार हैं। महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई। इनको भी अमरता का वरदान प्राप्त है।

ऋषि मार्कंडेय

ऋषि मार्कंडेय 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं। वह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय ने शिव के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्यंजय मंत्र की रचना भी की थी। हालांकि वह अल्पायु लेकर जन्मे थे। लेकिन स्वयं भगवान शिव यमराज से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया था।

आस्था के
प्रतीक हैं

खाटू के श्री श्याम

कौरवों और पाण्डवों के मध्य
महाभारत युद्ध का समाचार बर्बरीक
को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में
सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुयी।
जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त
करने पहुंचे तब मां को हारे हुये पक्ष
का साथ देने का वचन दिया।

हमारे देश में बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो अपने चमत्कारों व वरदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले का विश्व विख्यात प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। यहां फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्याम बाबा का विशाल वार्षिक मेला भरता है। जिसमें देश-विदेशों से आये करीबन 25 से 30 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं। खाटू श्याम का मेला राजस्थान के बड़े मेलों में से एक है।

इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की श्याम यानी कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है उन्हें श्याम बाबा का नित नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को तो इस विग्रह में कई बदलाव भी नजर आते हैं। कभी मोटा तो कभी दुबला। कभी हंसता हुआ तो कभी ऐसा तेज भरा कि नजरें भी नहीं टिक पातीं। श्याम बाबा का धड़ से अलग शीष और धनुष पर तीन बाण की छवि वाली मूर्ति यहां स्थापित की गई। कहते हैं कि मन्दिर की स्थापना महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथों की थी। श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से आरम्भ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे तथा भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे तीन अभेद्य बाण प्राप्त कर तीन बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुये। अग्नि देव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे।

कौरवों और पाण्डवों के मध्य महाभारत युद्ध का समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुयी। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुये पक्ष का साथ देने का वचन दिया। महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिये वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर धनुष व तीन बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुये।

भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिये उसे रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ायी कि वह मात्र तीन बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिये पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापिस तरकस में ही आयेगा। यदि उन्होंने तीनों लोकों को प्रयोग में ले लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जायेगा। इस पर कृष्ण

वार्षिक मेले में आते हैं लाखों श्रद्धालु



ने उन्हें चुनौती दी की इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ। जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तब बर्बरीक ने कृष्ण से कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिये वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस और से सम्मिलित होगा तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिये वचन दोहराते हुये कहा कि वह युद्ध में निर्बल और हार की ओर अग्रसर पक्ष की तरफ से भाग लेगा। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है। अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा।

ब्राह्मण बने कृष्ण ने बालक बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिये चकरा गया परन्तु उसने अपने वचन की दृढ़ता जतायी। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की और कृष्ण के बारे में सुन कर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया।

उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरम्भ होने से पहले युद्धभूमि की पूजा के लिये एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे बड़े वीर की उपाधि से अलंकृत कर उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने

शीश का दान दिया। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया जहां से बर्बरीक सम्पूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे।

युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी खींचाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश सम्पूर्ण युद्ध का साक्षी है। उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गये। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्धनीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखायी दे रहा था जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी।

कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुये और वरदान दिया कि कलियुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलियुग में हारे हुये का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ होगा। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतरु ही बहा रही थी बाद में खुदायी के बाद वह शीश प्रकट हुआ।

एक बार खाटू के राजा को स्वप्न में मन्दिर निर्माण के लिये और वह शीश मन्दिर में सुशोभित करने के लिये प्रेरित किया गया। तदन्तर उस स्थान पर मन्दिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मन्दिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ई. में रूपसिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ई0 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है।

घर में महाभारत रखना अशुभ क्यों माना गया?



महाभारत ग्रंथ महर्षि वेद-व्यास द्वारा लिखा एक हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक है। आखिर क्यों महाभारत या उससे जुड़ी चीजों को घर में क्यों नहीं रख सकता। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों हैं ऐसा। धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया महाभारत का युद्ध हर इंसान को सिखाता है कि उसे जीवन में किन गलतियों को करने से बचना है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता भी महाभारत का ही भाग है, हालांकि इसे पवित्र माना और प्रेरणा देने वाला ग्रंथ माना जाता है और इसका पाठ भी किया जाता है। जबकि महाभारत को घर में रखना या फिर पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। बता दें कि, महाभारत को पांचवा वेद भी माना गया है।

हो सकते हैं ये परिणाम

हिंदू मान्यताओं के अनुसार गीता और रामायण की पवित्र ग्रंथ माना गया है, जबकि महाभारत को अशुभ माना जाता है क्योंकि इसे रखने या पढ़ने से घर में नकारात्मकता आती है। घर में कलह-क्लेश देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप महाभारत का पाठ करते हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां आने लगती हैं। इसके साथ ही परिवार में भूरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं।

इनसे होती है परेशानी

इतना ही नहीं, महाभारत से जुड़ी कोई भी चीज रखने से या पढ़ने से ही व्यक्ति को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि युद्ध के प्रीतक जैसे- तस्वीर या रथ आदि को भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे मनुष्य के मानसिक सेहत पर भी बुरा असर करता है और घर में लड़ाई-झगड़ें होने लगते हैं।

मंदिर में कर सकते हैं पाठ

महाभारत को घर में रखना अशुभ माना जाता है। अगर आपको महाभारत का पाठ करना है तो आप मंदिर में जाकर वहां महाभारत का पाठ कर सकते हैं या आप किसी खाली स्थान पर भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पाठ को कभी भी पूरी नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए आप एक पृष्ठ को छोड़कर पढ़ सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि... जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व



हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ये पर्व देशभर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और नौ दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है...

शुभ मुहूर्त: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 08 अप्रैल को देर रात 11 बजकर 50 मिनट से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी 09 अप्रैल को संध्याकाल 08 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 09 अप्रैल को घटस्थापना है।

घटस्थापना का समय

09 अप्रैल को घटस्थापना समय सुबह 06 बजकर 02 मिनट से लेकर 10 बजकर 16 मिनट तक है। इसके

अलावा 11 बजकर 57 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों मुहूर्त में घटस्थापना कर सकते हैं।

बन रहे ये शुभ योग

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 07 बजकर 32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्याकाल 05 बजकर 06 मिनट तक है।

घटस्थापना विधि

- सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करके पूजा का संकल्प लें।
- फिर इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें और चौकी रखें जहां पर कलश में जल भरकर रखें। इसके बाद कलश को कलावा से लपेट दें।
- फिर कलश के ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें।
- इसके बाद नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर कलश के ऊपर रख दें।
- इसके बाद धूप-दीप जलाकर मां दुर्गा का आवाहन करें और शास्त्रों में मां दुर्गा के पूजा-उपासना की बताई गई विधि से पूजा प्रारंभ करें।

लड्डू गोपाल को ऐसे कराएं स्नान, मिलेगा आशीष



हिं दू धर्म में बहुत सारे लोगों के घर में लड्डू गोपाल स्थापित होते हैं। मान्यता के मुताबिक लड्डू गोपाल जिससे अपने पूजा और सेवा करवाना चाहते हैं, सिर्फ उसी के मन में अपने प्रति प्यार का भाव जगाते हैं। वहीं जिससे लड्डू गोपाल को अपनी सेवा नहीं करवानी होती है, वह लोख कोशिशों के बाद भी लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला पाता है। वहीं लड्डू गोपाल की सेवा में कई नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। वहीं शास्त्रों में भी पूजा-सेवा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। आपको बता दें कि धर्म ग्रंथ में लड्डू गोपाल के स्नान के बारे में काफी वर्णन मिलता है। जैसे लड्डू गोपाल को कब और किस विधि से स्नान कराना चाहिए। साथ ही किन-किन वस्तुओं से स्नान कराना शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि लड्डू गोपाल को किन-किन चीजों से स्नान करवाना चाहिए।

केसर से स्नान

केसर का इस्तेमाल लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय किया जा सकता है। इससे लड्डू गोपाल का मन हर्षित यानी की प्रसन्न रहता है। साथ ही लड्डू गोपाल की कृपा से घर

में सकारात्मकता और शुभता बनी रहती है और खुशहाली का आगमन होता है।

पंचामृत से स्नान : लड्डू गोपाल को आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। हालांकि रोजाना पंचामृत का इस्तेमाल करने पर मनाही है। सिर्फ मंदिरों में रोजाना पंचामृत से स्नान होता है। उत्सव आदि के मौके पर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए।

इतनी बार लगाएं भोग

बता दें कि लड्डू गोपाल की सेवा बालक के रूप में की जाती है। इनको सुबह, दोपहर और रात को भोग लगाना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। माना जाता है कि बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए।

गोपीचंदन से स्नान

गोपी चंदन लड्डू गोपाल को बेहद प्रिय है। इसलिए रोजाना आप गोपी चंदन से लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं। गोपी चंदन से स्नान करवाने लड्डू गोपाल प्रसन्न होने के साथ ही वह नित्य रूप से शुद्ध बने रहते हैं।

सुख-समृद्धि लाने के लिए इस तरह करें गणेशजी की पूजा



भ गवान शंकर जी के सुत और भवानी के नंदन भगवान गणेश विघ्नहर्ता के साथ ही बुद्धि प्रदाता भी हैं। विद्यार्थियों को इनकी आराधना करने से उनके बौद्धिक स्तर में वृद्धि के साथ ही लेखन शैली में विकास होता है। भगवान शंकर जी के सुत और भवानी के नंदन भगवान गणेश विघ्नहर्ता के साथ ही बुद्धि प्रदाता भी हैं। विद्यार्थियों को इनकी आराधना करने से उनके बौद्धिक स्तर में वृद्धि के साथ ही लेखन शैली में विकास होता है। गणेश जी लेखनी के धनी हैं, इसलिए भगवान वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना के विषय में विचार किया तो उन्होंने इसे लिखने के लिए गणेश जी का चुनाव किया।

महाभारत लिखने में गणेश जी को क्यों लगे 3 साल? : महाभारत की कथा इतनी बड़ी है कि जिसे लिखने में किसी अन्य देवता को सदियों लग जाती किंतु गणेश जी की लेखन गति बहुत तेज थी, फिर भी उन्हें लिखने में तीन सालों का समय लगा। महाभारत लिखते समय गणेश जी ने शर्त रख दी की उनकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि यह तो ठीक है लेकिन आप हर श्लोक को समझ कर ही लिखेंगे। बताते हैं कि गजानन को जितना समय श्लोक का अर्थ समझने में लगता था, उतनी देर में व्यास जी अगले श्लोक की रचना कर लेते थे।

इस तरह करें गणेशजी के दर्शन

मान्यता है कि गणेश जी के पीछे पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा सामने से ही गणेश जी के दर्शन करने चाहिए। गणेश जी के मंदिर से बाहर निकलते समय ध्यान रखें कि हाथ जोड़ कर पीछे की तरफ उलटते कदम चलते हुए ही बाहर निकलें।

साथ में करें माता लक्ष्मी की पूजा

भगवान विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी एक दिन काफी दुखी भाव से अपने पति की सेवा कर रही थीं। उनके दुख का कारण उनके किसी संतान का न होना था। जैसे ही यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह तुरंत ही अपने बालक गणेश के साथ पहुंचीं और उन्हें माता लक्ष्मी की गोद में बैठा कर कहा गणेश माता लक्ष्मी के भी पुत्र हैं। इस पर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुईं और कहा कि जब तक कोई उनके साथ भगवान गणेश की पूजा नहीं करेगा, उसे कभी भी सुख-समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी।

सर्दियों में बेसन से नहीं रूखी होगी स्किन, बस ऐसे करें इस्तेमाल...



जब आप ठंड के मौसम में बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आपको उसके साथ नींबू को मिलाकर से बचना चाहिए। दरअसल, नींबू आपकी स्किन को लाइटन तो करता है, लेकिन उसके साथ-साथ यह आपकी स्किन को रूखा भी बनाता है। बेसन को स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। बचपन से ही हम सभी ने अपनी नानी-दादी से बेसन की अच्छाइयों के बारे में सुना है। यह आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने के साथ-साथ उसे अधिक ग्लोइंग भी बनाता है। हालांकि, सर्दियों में बेसन का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस मौसम में स्किन बहुत अधिक रूखी हो जाती है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही आसान टिप्स के बारे में बता रहे हैं। जब आप ठंड के मौसम में बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आपको उसके साथ नींबू को मिलाकर से बचना चाहिए। दरअसल, नींबू आपकी स्किन को लाइटन तो करता है, लेकिन उसके साथ-साथ यह आपकी स्किन को रूखा भी बनाता है। इसलिए, जब आप ठंड में बेसन का इस्तेमाल करें तो उसके साथ नींबू को अफ्लाई करने से बचें।

बहुत देर तक ना छोड़े

यह देखने में आता है कि जब हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे फेस पैक बनाते हैं। लेकिन आपको इसे बहुत देर तक चेहरे पर छोड़ने से बचना चाहिए।

दरअसल, जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी स्किन रूखी हो जाती है। जिससे आपको स्किन में जलन, रेडनेस व इरिटेशन की शिकायत हो सकती है।

मिलाएं ये सामग्री

जब आप ठंड में बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके साथ किस तरह के इंग्रीडिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं, इसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। मसलन, इस मौसम में आपको बेसन के साथ दही, दूध या शहद जैसे इंग्रीडिएंट्स को मिलाकर से बचना चाहिए। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग गुण प्रदान करते हैं। ठंड में रूखेपन से निपटने के लिए इन इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है।

करें कस्टमाइज

बेसन हर स्किन टाइप के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करें तो मौसम के साथ-साथ आपको अपनी स्किन टाइप का भी ख्याल रखना चाहिए। मसलन, अगर आपकी स्किन रूखी है तो बेसन के साथ-साथ शहद या दही को मिलाकर से किया जा सकता है। वहीं, अगर आपकी स्किन सेसेटिव है तो आप बेसन के साथ एलोवेरा जेल या फिर गुलाब जल को मिलाकर से सकते हैं।

सर्दियों में फटी एड़ियों से हो गए हैं परेशान तो अपनाएं ये टिप्स



सर्दियों के मौसम में अपनी त्वचा का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि सर्द हवाओं का सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है, जिसके कारण हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। ऐसे में पैरों के रूखेपन को दूर करने के लिए आप ये टिप्स अपना सकते हैं। जनवरी की सर्दी ने हर किसी का हाल खराब कर रखा है। इसलिए ठंड से बचने के लिए लोग जैकेट और स्वेटर पहन रहे हैं। इसके बाद भी लोगों को सर्दी ने परेशान कर रखा है। वहीं सर्दी के मौसम में अपनी त्वचा का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि सर्द हवाओं का सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है, जिसके कारण हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। हालांकि तमाम तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल लोग स्किन के रूखेपन से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। सर्दियों में लोग चेहरे और हाथ का ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन जब पैरों की बारी आए तो इस पर लोगों का आसानी से ध्यान नहीं जाता है। जिसके कारण पैर काफी ड्राई होने लगते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ भी यह परेशानी है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आपके पैर काफी मुलायम हो जाएंगे।

पेट्रोलियम जेली : अगर आपके पैर सर्दियों में हद से ज्यादा रूखे होने लगते हैं और आपके पास इनकी केयर के लिए ज्यादा समय नहीं है। तो आपके लिए पेट्रोलियम जेली एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसका इस्तेमाल कर अपने पैरों को मुलायम बना सकते हैं। यह मार्केट में आपको काफी आसानी से मिल जाएगा।

शहद : शहद में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं, तो स्किन के रूखेपन से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी रूखे पैरों की समस्या से निजात पाना चाहती हैं, तो 10-15 मिनट तक शहद अपने पैरों पर अफ्लाई करें। फिर हल्के गुनगुने पानी से पैरों को साफ कर लें। इससे आपके पैर मुलायम होंगे।

एलोवेरा : शायद ही ऐसा कोई घर होगा, जहां एलोवेरा का पौधा नहीं पाया जाता होगा। लोग बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए करते हैं।

श्री राम मंदिर के तर्ज पर बनेगा छत्तीसगढ़ का कौशल्य मंदिर



जि स तरह से यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक उसी तरह से देश के 10 राज्यों में कई बड़े मंदिरों-तीर्थों के निर्माण कार्य और रेनोवेशन के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें करीब 17 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 32 करोड़ रुपए की लागत से कौशल्य मंदिर का रेनोवेशन किया जाना है। इस मंदिर का एक हिस्सा अयोध्या के राम मंदिर जैसा होगा। वहीं केरल के भगवान श्रीहरि विष्णु के 5 हजार साल पुराने थिरुनेली मंदिर का कायाकल्प हो रहा है। बता दें कि यह मंदिर केरल-कर्नाटक सीमा पर ब्रह्मगिरि पहाड़ियों में स्थित है। इसको 'दक्षिण का काशी' भी कहा जाता है।

थिरुनेली मंदिर के रेनोवेशन पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 200 ऐतिहासिक स्मारकों और मंदिरों के रेनोवेशन किए जाने के लिए 20 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। इस रेनोवेशन के प्रोजेक्ट में 35.37 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा देश के 10 राज्यों में कई बड़े मंदिरों-तीर्थों के निर्माण कार्य और रेनोवेशन के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें करीब 17 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं।

कामाख्या देवी मंदिर परिसर : वाराणसी के काशी-विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर असम में स्थित कामाख्या देवी मंदिर परिसर में भी कॉरिडोर बनाए जाने की चर्चा की जा रही है। बटाद्रवा प्रोजेक्ट के लिए

नौगांव में बजट तय हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट प्लान को 'असम दर्शन' के तहत तैयार किया गया है। अयोध्या के बाद अब प्रयागराज में भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि अगले साल महाकुंभ से पहले प्रयागराज के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार बिलासपुर में दूबे मंदिरों को पानी से बाहर निकालने की तैयारी में जुटी है। वहीं भाजपा प्रेजिडेंट जेपी नड्डा का बिलासपुर गृहनागर भी है। बिलासपुर में हेरिटेज और धार्मिक टूरिज्म को प्रोमोट करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहीं ओडिशा सरकार पुरी में 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के साथ ही राज्य के सभी मंदिरों का कायाकल्प कर रही है। ओडिशा के हर गांव में 'जगन्नाथ संस्कृति' के संरक्षण का काम किया जाएगा। ओडिशा की ऐतिहासिकता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट भी किए जाने का प्लान है।

साल 2023 में राजस्थान चुनाव से पहले गहलोट सरकार ने राज्य के दो मंदिरों का कायाकल्प किए जाने की घोषणा की थी। बता दें कि डूंगरपुर और जयपुर के इन मंदिरों का ऐतिहासिक महत्व है। 'भारत राष्ट्र समिति' की देखरेख में तेलंगाना राज्य के नरसिम्हा स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। यह मंदिर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार को समर्पित है। इस मंदिर में गंडभेरुंड नरसिम्हा, योगानंद नरसिम्हा, ज्वाला नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा और लक्ष्मी नरसिम्हा के दर्शन होते हैं।

बिहार में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर कंबोडिया के 800 साल पुराने अंगकोरवाट मंदिर की तरह होगा। विराट रामायण मंदिर की वास्तुकला अंगकोर वाट मंदिर, मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर से प्रेरित है। 'महावीर मंदिर मंदिर ट्रस्ट' यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा।

पश्चिम बंगाल में प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ नए मंदिरों का निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य की ममता सरकार ने कोलकाता के हुगली के किनारे स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर, तारापीठ मंदिर, सागर द्वीप के कपिल मुनि मंदिर और कंकलीतला मंदिर समेत 150 से ज्यादा मंदिरों के लिए बजट आवंटित किया है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है। इस मंदिर तक आप दो रास्ते से पहुंच सकते हैं, जिनमें पहला रास्ता पहलगाव होते हुए और दूसरा रास्ता बालटाल से होते हुए है। लेकिन सबसे पुराना और ऐतिहासिक रूट पहलगाव माना जाता है।

पहलगाव से अमरनाथ की पवित्र गुफा की दूरी 48 किमी है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। जबकि बालटाल रूट 14 किमी ही है। हालांकि भले ही यह रास्ता छोटा है, लेकिन यह काफी मुश्किल रास्ता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई भी। अब इस जगह को भी आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। बता दें कि यहां पर हर साल अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वहीं अब सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

पेपर कप में चाय पीना सेहत के लिए हो सकता है नुकसानदेह

कागज के कप में प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आपको आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन यह चाय में घुलकर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। हम आपको कागज के कप में चाय पीने से सेहत को होने वाले कुछ नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं।



एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप कागज के कप में चाय पीते हैं, तो इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस गंभीर बीमारे के खतरे की वजह कागज के रूप में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है। जो आपको आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन यह चाय में घुलकर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कागज के कप में चाय पीने से सेहत को होने वाले कुछ नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। पेपर कप में जब गर्म चाय डालते हैं, तो इस पर चढ़ी प्लास्टिक की लेयर पिघलने लगती है। क्योंकि एक कप चाय में माइक्रोप्लास्टिक के 25 हजार से अधिक कण घुल जाते हैं। इन कणों का साइज इतना अधिक बारीक होता है कि आप इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक में मौजूद दूसरे हानिकारक केमिकल्स चाय में घुलकर हमारे शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप पेपर कप में दिन भर में 5 चाय पीते हैं, तो एक लाख 25 हजार माइक्रो प्लास्टिक कण आपके शरीर में पहुंच जायेंगे। वहीं लगातार इस कप में चाय पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही बॉडी में धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक कण जमा होने लगते हैं। जिससे डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। पेपर कप में चाय पीने से हाजमा खराब हो जाता है और आंतों में इंफेक्शन फैल जाता है और धीरे-धीरे इसका असर किडनी और लिवर पर भी पड़ने लगता है।

प्रेनैट महिलाओं के लिए हानिकारक : हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो गर्भवती महिलाओं को पेपर कप

के इस्तेमाल से बचना चाहिए। क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से हाई बीपी की समस्या हो सकती है। पेपर कप के इस्तेमाल से गर्भ में पलने वाले बच्चे का विकास रुक सकता है और बच्चे को मानसिक बीमारी होने का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं महिलाओं को थकान और एंजाइटी हो सकती है।

डिस्पोजल कप पर रिसर्च

एक रिसर्च में सामने आया है कि न सिर्फ व्यक्ति की सेहत बल्कि यह पेपर कप मिट्टी और पर्यावरण तक को प्रदूषित करते हैं। शोध के दौरान तितली और मच्छर के लार्वा पर रिसर्च की और पता लगाने की कोशिश कि अलग-अलग चीजों से बने डिस्पोजेबल कप का लार्वा पर कैसा असर पड़ता है। इसके लिए पेपर कप और प्लास्टिक कप को कुछ सप्ताह के लिए पानी में छोड़ दिया गया। पानी में कप में मौजूद केमिकल घुलकर लार्वा तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि तितलियों और मच्छरों के लार्वा के विकास पर कप में मौजूद केमिकल ने निगेटिव असर डाला। पॉली लैक्टिक एसिड को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। लोगों को लगता है कि दूसरे प्लास्टिक की तुलना में यह जल्द नष्ट हो जाता है। लेकिन बता दें कि दूसरे प्लास्टिक की तरह PLA भी खतरनाक और जहरीला हो सकता है। जब मिट्टी-पानी में पहुंचकर बायोप्लास्टिक के कण पर्यावरण में घुलते हैं, तो यह आसानी से नष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में यह पानी और हवा-मिट्टी के जरिए इंसानों

और जानवरों के शरीर में पहुंच जाता है। इन कणों में मौजूद केमिकल सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं।

पर्यावरण में घुल जाता है प्लास्टिक

प्लास्टिक हमेशा पर्यावरण में बना रहता है तो हमेशा खतरे के रूप में कायम रहता है। ऐसे में यह गलतकर माइक्रोप्लास्टिक की शक्ति में न सिर्फ इंसानों और जानवरों तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि प्लास्टिक में उतना प्लास्टिक होता है, जितना कि एक नॉर्मल 'कंवेशन प्लास्टिक' में। पेपर प्लास्टिक में भी नुकसान पहुंचाने वाले पार्टिकल्स मिले होते हैं, जो सेहत के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी बड़ा खतरा है।

ऐसे रिसाइकल होते हैं जूठे कप

बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिस्पोजेबल पेपर कप को रिसाइकल कर पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। हालांकि कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर पेपर कप को रिसाइकल कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। पेपर कप को रिसाइकल करने के लिए कागज और प्लास्टिक की परत को पहले अलग किया जाता है। फिर इसमें से निकले कागज से दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसी कई कंपनियां हैं, जो पेपर कप को रिसाइकल कर उससे नैपकिन, टिशू पेपर और कार्ड बोर्ड जैसे नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में हर साल 6 से 8 लाख टन पेपर का इस्तेमाल किया जाता है।

पलक जोशी ने 200 मी. बैकस्ट्रोक में जीता गोल्ड, तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड



महाराष्ट्र की तैराक पलक जोशी ने खेलो इंडिया युवा खेलों (केआईवाईजी) में गोल्ड मेडल के क्रम में 200 मीटर बैकस्ट्रोक के अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया। हांगझोउ एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी पलक ने दो मिनट 18.59 सेकंड के समय लिया। मंगलवार को महाराष्ट्र की तैराक पलक जोशी ने खेलो इंडिया युवा खेलों (केआईवाईजी) में गोल्ड मेडल के क्रम में 200 मीटर बैकस्ट्रोक के अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया। हांगझोउ एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी पलक ने दो मिनट 18.59 सेकंड के समय लिया। यह उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड (दो मिनट 18.90 सेकंड) से कम था, जो उन्होंने पिछले साल जुलाई में हैदराबाद में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के दौरान कायम किया था। तेलंगाना की श्री नित्या सागी ने दो मिनट 25.83 सेकंड के समय के साथ रजत, जबकि कर्नाटक की नायशा ने दो मिनट 25.83 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

इससे पहले तमिलनाडु की भारोत्तोलक आरपी कीर्तन ने स्नैच और कुल भार में राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड तोड़कर लड़कियों के 81 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कुल 188 किग्रा वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 85 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में 103 किग्रा शामिल था। वह राज्य की

साथी ओविया के (184 किग्रा) से आगे रहीं, जबकि उत्तर प्रदेश की संतुष्टि चौधरी ने कुल 162 किग्रा वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले स्नैच (81 किग्रा), क्लीन एवं जर्क (104 किग्रा) और कुल भार (185 किग्रा) का पिछला रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश की सीएच सिरिलक्ष्मी के नाम था।

महाराष्ट्र ने अपने खाते में नौ और स्वर्ण जोड़े जिससे उसके पीले तमगे का आंकड़ा 50 को पार कर गया। विश्व चैंपियन और 2022 एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता अदिति गोपीचंद स्वामी ने तीरंदाजी में महाराष्ट्र के दबदबे का नेतृत्व किया। उन्होंने लड़कियों के कंपाउंड और मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीता। पृथ्वीराज घाडगे और शरवानी शेंडे ने रिकर्व वर्ग में मिश्रित टीम का स्वर्ण जीता।

महाराष्ट्र की खो-खो टीम ने अपने दमखम को कायम रखते हुए दोनों वर्ग के स्वर्ण जीते। लड़कों की टीम ने ओडिशा को 40-10 से हराया जबकि लड़कियों की टीम ने ओडिशा को 33-24 से शिकस्त दी। राज्य की ही तारिणी सूरि और श्रावणी वालेकर ने बैडमिंटन में लड़कियों के युगल फाइनल में ओडिशा की प्रगति परिदा और विशाखा टोप्पो को 21-13, 20-22, 21-16 से हराकर राज्य की स्वर्ण पदक संख्या को 50 तक पहुंचा दिया।

विश्व चैंपियनशिप से पैरा लंपिक में जगह बनाने पर लगी पैरा खिलाड़ियों की निगाहें



पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी, मंदीप कौर और पलक कोहली की निगाहें 20 से 25 तक पटया में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन से इस साल के अंत में होने वाले पैरालंपिक में जगह बनाने पर लगी हैं। भारत ने पिछले साल हांगझोउ पैरा एशियाई खेलों में ऐतिहासिक 111 पदकों में से 21 पदक बैडमिंटन में हासिल किये थे। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी, मंदीप कौर और पलक कोहली की निगाहें 20 से 25 तक पटया में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन से इस साल के अंत में होने वाले पैरालंपिक में जगह बनाने पर लगी हैं। भारत ने पिछले साल हांगझोउ पैरा एशियाई खेलों में ऐतिहासिक 111 पदकों में से 21 पदक बैडमिंटन में हासिल किये थे जिसमें मानसी और मंदीप ने एकल में कांस्य पदक जीते थे।

महिलाओं की एसएल3-एसयू5 युगल स्पर्धा में मानसी ने टी मुरुगेसन के साथ रजत पदक और मंदीप ने मनीषा रामदास के साथ कांस्य पदक जीता था। मानसी ने प्रायोजक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पीटीआई से कहा, “हम सभी विश्व चैंपियनशिप में खेलेंगे जिसके लिए हम 17 फरवरी को जा रहे हैं। यह फाइनल है, यह पैरालंपिक क्वालीफिकेशन वर्ष का अंत है।”

उन्होंने कहा, क्वालीफिकेशन प्रक्रिया 31 मार्च को खत्म हो रही है, इस दिन से हमारी रैंकिंग और ‘रेस टू पेरिस’ यही पर रूक जायेगी। इसलिए यह विश्व चैंपियनशिप हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है।” मंदीप ने कहा, “हमें पैरा एशियाई खेलों से पहले ट्रेनिंग करने का ज्यादा समय नहीं मिला था। लगातार टूर्नामेंट हो रहे हैं। लेकिन विश्व चैंपियनशिप से पहले हम ट्रेनिंग के लिए करीब दो महीने मिले और हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम अपना शत प्रतिशत देंगे।

जियोर्जिया ने की थी ब्रेकअप पर बात, अरबाज खान को नहीं आई रास...

अरबाज खान ने कहा, 'मैं जानता हूँ कि हाल के कुछ इंटरव्यू में से यह अहसास होता है कि अंत तक चीजें सही थीं, जो सच नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे यहां बैठना पड़ा और इस तरह का स्पष्टीकरण देना पड़ा।' अभिनेता अरबाज खान अपनी शादीशुदा जिंदगी का लुप्त उठा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान के साथ निकाह रचाया था। अभिनेता की दूसरी शादी के दौरान उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जियोर्जिया एंड्रियानी ने कुछ इंटरव्यू दिए थे, जो काफी वायरल हुए थे। अब अरबाज ने अपनी एक्स के इन इंटरव्यू की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इन्हें अनुचित बताया है। इसी के साथ अभिनेता ने जियोर्जिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में कई खुलासे किए।

इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में अरबाज खान ने कहा, 'मैं जानता हूँ कि हाल के कुछ इंटरव्यू में से यह अहसास होता है कि अंत तक चीजें सही थीं, जो सच नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे यहां बैठना पड़ा और इस तरह का स्पष्टीकरण देना पड़ा।' अभिनेता ने आगे

खुलासा किया कि शूरा के साथ शादी करने से लगभग डेढ़ साल पहले जियोर्जिया एंड्रियानी के साथ उनका ब्रेकअप हो गया था।

अरबाज ने कहा, 'मेरा पिछला रिश्ता शूरा से मिलने से लगभग डेढ़ साल पहले ही खत्म हो गया था। उसके साथ मेरा एक साल का डेटिंग पीरियड रहा। उन इंटरव्यू में कोई समयसीमा नहीं दी गई थी और ऐसे साक्षात्कार लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि 'ओह, मैं इससे वहां पहुंच गया' लेकिन यह सच नहीं है। शूरा से मिलने तक मैं लगभग डेढ़ साल तक किसी को डेट नहीं कर रहा था। यही हकीकत है।' अरबाज और जियोर्जिया ने साल 2018 में एक दूसरे को डेट किया। 2023 में अभिनेता की दूसरी शादी की अफवाहों आने के बाद जियोर्जिया और उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आयीं। अरबाज की शादी के कुछ दिन पहले जियोर्जिया ने कई इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अभिनेता के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अभिनेत्री ने कहा था कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है और वह उसके लिए 'हमेशा भावनाएं' रखेंगी।



रेनी के साथ पार्टी में पहुंचे मुन्वर फारूखी

दोनों को साथ देख लोग हुए हैरान,
कहा- वो वहां क्या कर रही है?

पिछले महीने संपन्न हुए बिग बॉस 17 के विजेता के रूप में उभरने के बाद से मुन्वर फारूखी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बुधवार रात मुन्वर को एक पार्टी में स्टाइल में पहुंचते देखा गया। वह ऑफ-व्हाइट को-ऑर्ड सेट में हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे थे, जिसे उन्होंने मैचिंग स्नीकर्स की एक जोड़ी के साथ पहना था। बिग बॉस 17 के विजेता मुन्वर फारूखी के लिए एक और पार्टी आयोजित की गयी। 7 फरवरी की रात मुंबई में एक पार्टी आयोजित की गई और इसमें भारतीय मनोरंजन

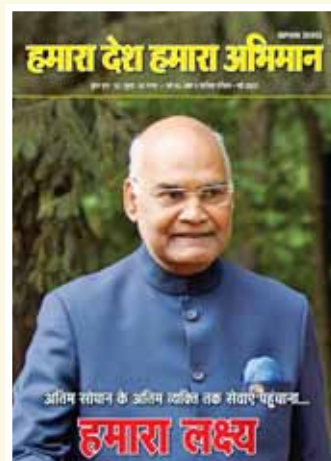
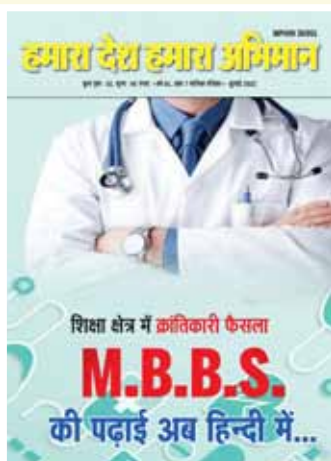
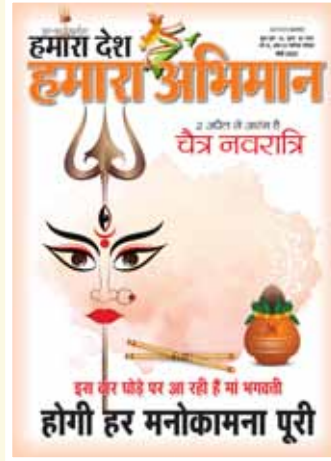
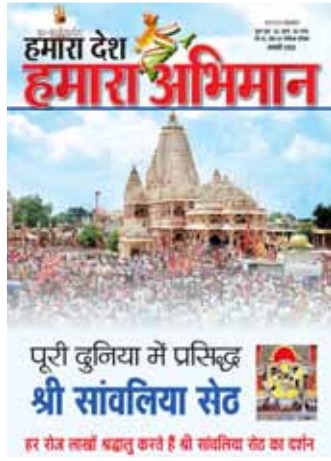
उद्योग के लोकप्रिय नाम शामिल हुए। मुन्वर फारूखी ने पार्टी में आते ही पपराजी के लिए पोज दिया। उन्हें सुष्मिता सेन की बेटी रेनी सेन के साथ पोज देते हुए स्पॉट किया गया था। पार्टी में ओरी भी शामिल हुए।

पार्टी में अन्य मेहमानों में सुजैन खान और उनके बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी, अभिनेता वाणी कपूर, तारा सुतारिया और मंदिरा बेदी शामिल थे। पिछले महीने संपन्न हुए बिग बॉस 17 के विजेता के रूप में उभरने के बाद से मुन्वर फारूखी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बुधवार रात मुन्वर को एक पार्टी में स्टाइल में पहुंचते देखा गया। वह ऑफ-व्हाइट को-ऑर्ड सेट में हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे थे, जिसे उन्होंने मैचिंग स्नीकर्स की एक जोड़ी के साथ पहना था।



हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव



हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका
की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136



**भमहाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः।
सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ॥**

अर्थ : भगवान शिव शंकर जो पर्वतराज हिमालय के नजदीक पवित्र मन्दाकिनी के तट पर स्थित केदारखण्ड नामक श्रृंग में निवास करते हैं और हमेशा ऋषि मुनियों द्वारा पूजे जाते हैं। जिनकी यक्ष-किन्नर, नाग व देवता-असुर आदि भी हमेशा पूजा करते हैं उन अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव शंकर की मैं स्तुति करता हूँ।